

[2023] 8 एस. सी. आर 283

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी।

वी.

एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी।

(सिविल अपील सं। 4049-4053 2023 का)

15 जून, 2023

[वी. रामसुब्रमणियन और पंकज मिट्टल, जे. जे.]

मुकदमा-विभाजन मुकदमा-फरमान-प्रारंभिक डिक्री-मथरुका

संपत्ति-चाहे तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह घोषणा करने में सही था कि दिनांकित प्रारंभिक डिक्री धोखाधड़ी से दूषित थी और परिणामस्वरूप अमान्य थी, विशेष रूप से जब कोई अभिवचन नहीं था और कोई सबूत नहीं दिया गया था-आयोजित किया गया: 28.06.1963 दिनांकित प्रारंभिक डिक्री विभाजन की मांग करने वाले कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए स्वामित्व के दावे को निर्धारित नहीं कर सकती थी।

तृतीय पक्ष-प्रारंभिक डिक्री में दिया गया कोई भी निष्कर्ष, कि संपत्तियां विभाजित होने के लिए उत्तरदायी मातृका संपत्तियां थीं, केवल कानूनी उत्तराधिकारियों के दावे के लिए आकस्मिक था और इस तरह का निष्कर्ष संपत्ति पर उनके अधिकार का निर्धारण नहीं करेगा।

पक्षकार-जिस तरह से कार्यवाही के पक्षों के साथ-साथ गैर-पक्षकारों द्वारा निर्णय और प्रारंभिक डिक्री का उपयोग, दुरुपयोग और दुरुपयोग करने की मांग की गई थी, जो प्रारंभिक डिक्री के कुछ हिस्सों को खरीदकर और तीसरे पक्ष के अधिकारों को हराकर अदालत के माध्यम से उन्हें निष्पादित करने की मांग कर रहे थे, उसी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ को यह ठहराने के लिए प्रेरित किया है कि प्रारंभिक डिक्री धोखाधड़ी से दूषित है।

क्या था?

विभाजन के लिए एक साधारण मुकदमा; और आकस्मिक निष्कर्ष में दर्ज किया गया कि संपत्तियां मथरुका की संपत्तियां थीं, पक्षों और गैर-पक्षों द्वारा अजनबियों के खिलाफ संपत्तियों पर अधिकार का दावा करने के लिए उपयोग किया गया था यह निश्चित रूप से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

और 28.06.1963 दिनांकित प्रारंभिक डिक्री, हालांकि धोखाधड़ी से दूषित नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से तीसरे पक्ष जैसे दावा याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं जिन्होंने स्वतंत्र दावे किए हैं और जो कुछ भी प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में किया गया था।

यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

सूट-डिक्री-प्रारंभिक डिक्री-'पैगाह' एस्टेट-मथरुका

संपत्ति-चाहे तथ्यों पर, एकल के समवर्ती निष्कर्ष

न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ कि खुर्शिद जाह

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक 'पैगाह' अनुदानकर्ता, जो अपने पीछे कोई मातृका संपत्ति नहीं छोड़ता था, निर्णय में दर्ज निष्कर्ष के विपरीत जाता है और प्रारंभिक डिक्री जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है-क्या निर्णय और प्रारंभिक डिक्री में दर्ज निष्कर्ष कि सवाल यह है कि क्या मातृका संपत्ति तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी थी आयोजित किया गया: ट्रायल जज द्वारा कभी भी कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था

निर्णय दिनांक 28.06.1963 कि खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियाँ मथरुका संपत्तियाँ थीं-इसलिए, तर्क मानो ऐसी कोई खोज हुई हो और यह कि खोज प्राप्त हो गई हो

अंतिमता और यह कि विवादित निर्णय इस तरह के निष्कर्ष के विपरीत जाता है, पूरी तरह से गलत धारणा है-एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ (विवादित निर्णय में) निर्णय लेने में सही थे। कि संपत्तियाँ मातृका संपत्तियों के रूप में स्थापित नहीं की गई थीं

-

ट्रायल जज-- किसी भी मामले में, ऐसी परीक्षा की जानी थी। स्वतंत्र रूप से और विभाजन मुकदमे में नहीं, 1955 को ध्यान में रखते हुए

कृषि भूमि से संबंधित अधिनियम और उसके बाद के विभिन्न अधिनियम सुधार और शहरी भूमि सीमा-जब का पूरा दावा

अपीलकर्ताओं ने कहा कि ये संपत्तियाँ उत्तराधिकार में मिलने वाली मथरुका संपत्तियाँ थीं कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विफल हो गया था, एक डिक्री को निष्पादित करने का सवाल

इस दलील की ताकत कि संपत्ति एक मातृका संपत्ति है

उत्पन्न नहीं होता है-अपीलार्थियों के पूर्ववर्तियों के पास है यह जानते हुए कि फैसल पट्टी दावे के नाम पर दर्ज की गई थी

1978 में ही याचिकाकर्ता-यहाँ तक कि प्राप्तकर्ता को भी इसके बारे में पता था, जैसा कि प्राप्तकर्ता द्वारा 09.04.1980 पर लिखे गए पत्र से देखा जा सकता है।

क्लेक्टर-अपीलार्थियों के लिए सवाल पूछने में दिन में बहुत देर हो चुकी है। दावा याचिकाकर्ताओं का दावा कैसे स्थापित हुआ।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश XXI, rr. 97- 101

कार्यक्षेत्र के तहत पूछताछ आयोजित: आदेश XXI के तहत एक जांच में,
आरआर। 97 101 तक, सी. पी. सी., निष्पादन न्यायालय के प्रश्नों का निर्णय नहीं ले सकता है
तृतीय पक्षों द्वारा स्थापित शीर्षक (पार्टियों के माध्यम से या उनके तहत दावा नहीं करना)
मुकदमे या उनके परिवार के सदस्यों के लिए), जो स्वतंत्र शीर्षक का दावा करते हैं
स्वयं-वह सब जो ऐसे मामलों में किए जा सकते हैं
निष्पादन, प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए है कि क्या अवरोधक /
दावा याचिकाकर्ताओं के पास अधिकार के लिए एक प्रामाणिक दावा है, स्वतंत्र
विभाजन मुकदमे के पक्षकारों के अधिकार-यदि वे पाए जाते हैं
अधिकार के लिए एक स्वतंत्र दावा, फिर के लिए डिक्री के धारक
इन कार्यवाहियों में विभाजन को तीसरे पक्ष के अधिकारों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्ठी एंड ओआरएस. ईटीसी।

मुकदमा-विभाजन मुकदमा-प्रारंभिक डिक्री-का प्रभाव-आयोजित: विभाजन के लिए एक मुकदमे में एक प्रारंभिक डिक्री केवल उन शेयरों की घोषणा करती है जो पक्षकार वादी अनुसूची में शामिल किसी भी संपत्ति में हकदार हैं और विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं-प्रारंभिक डिक्री के तहत होने वाले अधिकारों की केवल घोषणा के आधार पर, पक्षकार संपत्तियों की विशिष्ट वस्तुओं या वाद अनुसूची संपत्तियों के विशिष्ट भागों पर व्यापार नहीं कर सकते हैं-क्योंकि विभाजन मुकदमे में तीन चरण होते हैं, अर्थात् (i) विभाजन में एक प्रारंभिक डिक्री पारित करना।

आदेश XX नियम 18 (2) की शर्तें; (ii) एक आयुक्त की नियुक्ति और आदेश XXVI नियम 14 (3) के संदर्भ में अंतिम डिक्री पारित करना; और (iii) आदेश XXI नियम 35 के तहत ऐसी डिक्री के निष्पादन में कब्जा करना, विभाजन के लिए मुकदमे का कोई भी पक्षकार, भले ही

समझौता, संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु या किसी विशिष्ट संपत्ति के किसी विशेष हिस्से पर कोई भी अधिकार प्राप्त कर सकता है, यदि ऐसा समझौता केवल मुकदमे के कुछ पक्षों के साथ किया जाता है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश XX, आर. 18 (2); आदेश XXVI, आर. 14 (3) और ऑर्डर XXI, आर. 35।

मुकदमा-विभाजन मुकदमा-आयोजित: विभाजन के लिए एक मुकदमे में, सिविल कोर्ट स्वामित्व के सवाल में नहीं जा सकता है, जब तक कि वही नहीं है

दावे के मूल आधार के लिए प्रासंगिक।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. जिस तरह से मुकदमे के दावे का मूल्यांकन किया गया है और अदालत-शुल्क का भुगतान किया गया है, वह बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह मुकदमा नहीं था।

किसी भी संपत्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद। यह केवल विभाजन के लिए एक सूट था। सभी वाद अनुसूची संपत्तियों का मूल्य एक विशेष दर पर किया गया है और न्यायालय शुल्क का भुगतान उस हिस्से के मूल्य पर किया गया था, जिसमें से वादी विभाजन की मांग कर रहा था। अगर यह एक सूट था

अधिकार की घोषणा के लिए एक प्रार्थना के साथ, अदालत-शुल्क उत्तरदायी था

संपत्ति के पूरे मूल्य पर भुगतान किया जाना चाहिए न कि विभाजित किए जाने वाले हिस्से पर। इसलिए, प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.06.1963 शीर्षक के दावे को निर्धारित नहीं कर सकती थी।

विभाजन की मांग करने वाले कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया, जैसा कि तीसरे पक्ष के खिलाफ है। प्रारंभिक डिक्री में दिया गया कोई भी निष्कर्ष, कि

सम्पत्तियाँ विभाजित की जाने वाली मातृका संपत्तियाँ थीं, केवल कानूनी उत्तराधिकारियों के दावे के लिए आकस्मिक थीं और इस तरह का निष्कर्ष संपत्ति पर उनके अधिकार का निर्धारण नहीं करेगा, जबकि तीसरी

पार्टियाँ। [पारस 119 और 120] [341-ई-एच] [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय, सही कानूनी अर्थों में, प्रारंभिक डिक्री को ब्रांडिंग करने में सही नहीं हो सकता है जैसा कि

धोखाधड़ी। लेकिन तथ्य यह है कि जहां तक खुर्शीद जाह के परिवार (और उनके तहत दावा करने वालों) के तीसरे पक्षों का संबंध है, प्रारंभिक आदेश केवल एक कागज के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उन तीसरे पक्षों का दावे से कोई लेना-देना नहीं है

विभाजन के लिए, हालांकि उनके पास मुकदमों की अनुसूची में वर्णित संपत्तियों के स्वामित्व का वैध दावा है। इसलिए, 28.06.1963 दिनांकित निर्णय और प्रारंभिक डिक्री, हालांकि धोखाधड़ी से दूषित नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से तीसरे पक्ष जैसे दावा याचिकाकर्ताओं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं जिन्होंने स्वतंत्र दावे किए हैं। इसके अलावा, आदेश XXI, नियम 97 से 101, सी. पी. सी. के तहत एक जांच में, निष्पादन न्यायालय तीसरे पक्ष द्वारा स्थापित स्वामित्व के प्रश्नों पर निर्णय नहीं ले सकता है, जो अपने आप में स्वतंत्र अधिकार का दावा करते हैं। मरीना बीच (चेन्नई में) या हुसैन सागर (हैदराबाद में) या इंडिया गेट (नई दिल्ली में) को याचिका अनुसूची में संपत्तियों की वस्तुओं में से एक के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन के मुकदमे में और इन संपत्तियों के स्वामित्व के प्रश्नों को आदेश XXI, नियम 97-101, CPC के तहत दावा याचिकाओं में निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा 126] [344-ई-एच; 345-ए]

3. 28.06.1963 का निर्णय और प्रारंभिक डिक्री, हालांकि धोखाधड़ी से दूषित नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। तीसरे पक्ष जैसे दावा याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ

सरकार जिन्होंने स्वतंत्र दावे किए हैं और प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में जो कुछ भी किया गया था, वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। आदेश XXI, नियम 97 से 101, सी. पी. सी. के तहत एक जांच में, निष्पादन न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता है। तीसरे पक्ष द्वारा स्थापित स्वामित्व के प्रश्न (मुकदमे के पक्षकारों या उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से या उनके तहत दावा नहीं करते हैं), जो अपने आप में स्वतंत्र अधिकार का दावा करते हैं। सब कुछ ऐसा किया जा सकता है

निष्पादन के चरण में मामले, प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए हैं कि क्या अवरोधकों/दावा याचिकाकर्ताओं का एक प्रामाणिक दावा है विभाजन मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों से स्वतंत्र शीर्षक। यदि उनके पास अधिकार के लिए एक स्वतंत्र दावा पाया जाता है, तो विभाजन के लिए डिक्री के धारक को हारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

इन कार्यवाहियों में तीसरे पक्ष के अधिकार।

[पैरा 139] [348-डी-जी] मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्ची एंड ओआरएस. ईटीसी।

जागीरों की व्यक्तिगत संपत्तियों को धारा 18 के तहत छूट दी गई थी। 1955 के अधिनियम के प्रभाव की कभी किसी ने जांच नहीं की। भले ही विचाराधीन संपत्ति जागीर उन्मूलन के तहत गिलोटिन से बच जाए

विनियमों के अनुसार, यह 1955 के अधिनियम के तहत अपने भाग्य को पूरा कर सकता है। इसलिए,

एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ यह अभिनिर्धारित करने में सही थी कि संपत्तियाँ मथरुका होने के लिए स्थापित नहीं की गई थीं

संपत्तियाँ। नज़ीम अतियत के आदेश के प्रभाव की जाँच विचारण न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, इस तरह की जांच स्वतंत्र रूप से की जानी थी न कि विभाजन के मुकदमे में, 1955 के अधिनियम और संबंधित विभिन्न बाद के अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए।

कृषि भूमि सुधार और शहरी भूमि सीमा। [पारस 159 और 160] [355-बी-ई]

5. जब अपीलार्थियों का यह पूरा दावा कि संपत्तियाँ कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में मिली मातृका संपत्तियाँ थीं, विफल हो गया था, तो इस दलील के बल पर एक डिक्री को निष्पादित करने का सवाल नहीं उठता है कि संपत्ति एक मातृका संपत्ति है। [पैरा 166] [356-एफ-जी]

एन. एस. एस. नारायण सरमा बनाम मेसर्स गोल्डस्टोन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट

लिमिटेड (2002) 1 एस. सी. सी. 662: [2001] 5 पूरक। एस. सी. आर. 327; वेंकट रेड्डी बनाम पेथी रेड्डी एयर 1963 एससी 992: [1963] 2 पूरक। एस. सी. आर. 616; राजा रामचंद्र रेड्डी बनाम। रानी शंकरम्मा एयर 1956 एससी 319; सिकंदर जहाँ

बेगम वी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ए. आई. आर. 1962

एससी 996 [1962] 2 पूरक। एस. सी. आर. 226; आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) v. ए. पी. राज्य वक्फ बोर्ड 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एससी 159; मोहम्मद. हब्बीबुद्दीन खान बनाम। जागीर प्रशासक, आंध्र सरकार

प्रदेश (1974) 1 एस. सी. सी. 82; रंगम्मल बनाम कुप्पुस्वामी

(2011) 12 एस. सी. सी. 220 [2011] 6 एस. सी. आर. 835; राष्ट्रीय वक्ख निगम (महाराष्ट्र दक्षिण) लिमिटेड बनाम। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (2000) 10 एस. सी. सी. 592 और लक्ष्मण दास बनाम। जगत राम और अन्य (2007) 10

एससीसी 448: [2007] 2 एस. सी. आर. 980-संदर्भित।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2001] 5 पूरक। एससीआर 327

संदर्भित किया गया है

पै

रा 78

पै

रा 99 (vii)

आकाशवाणी 1956 एस. सी. 319

संदर्भित किया गया है

[1962] 2 पूरक। एससीआर 226

पै

रा 99 (vii)

संदर्भित किया गया है

(1974) 1 एससीसी 82

पै

रा 99 (vii)

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 835

पै

रा 99 (ix)

संदर्भित किया गया है

(2000) 10 एस. सी. सी. 592

संदर्भित किया गया है

पै

रा 104

[2007] 2 एससीआर 980

पै

रा 104

संदर्भित किया गया है

[1963] 2 पूरक। एससीआर 616

संदर्भित किया गया है

पै

रा 188

सिविल अपील न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 4049

4053 2023 तक।

उच्च न्यायालय के 20.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ओ. एस. ए. संख्या में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए। 54 , 56 , 57 , 58 और 2004 का 59।

के साथ

सिविल अपील सं। 4054 , 4055-4058 , 4059 , 4060 , 4061-4064 ,
4065 ,

4066 , 4067 और 2023 का 4068-4072।

गोपाल शंकरनारायणन, वी. वी. एस. राव, के. एस. मूर्ति, पी. वी.

पीचारा, राजीव कुमार चौधरी, सुश्री पल्लवी, दुव्वुरी सुब्रमण्य भानू, विनायक गोयल, बैरपानेनी सुयोधन, भरत जे जोशी, कुमार शशांक, अभिजीत बसु, सुश्री तातिनी बसु, रोहन दीवान, बालाजी श्रीनिवासन, वी. वी. एस. राव, के. एस. मूर्ति, मुल्लापुडी रामबाबू, के. वेंकट राव, मेसर्स। एम. रामबाबू एंड कंपनी, रजनीश कुमार झा, सुश्री जैस्मीन दामकेवाला, सुश्री अनु गुप्ता, कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, सुश्री यशोदा कटियार, अर्जुन रघुवंशी, रितुल टंडन, राम किशोर मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी।

सिंह यादव, नमित सक्सेना, अवनीश मैथानी, प्रशांत रेड्डी, शिवम रघुवंशी, सुश्री शिक्षा आश्रम, सुयश व्यास, कुमार शशांक, निवेश कुमार, सुश्री सुनीति सिंह, नितीश राय, पीयूष टोंक, विशाल प्रसाद, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति 2022 की डायरी संख्या 19266 में दी गई है।

2. देरी को माफ कर दिया गया।

3. छुट्टी दे दी गई।

4. प्रभाग द्वारा दिए गए एक सामान्य निर्णय से व्यथित

तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की पीठ ने अंतर-न्यायालय अपीलों के एक समूह में, एक दीवानी मुकदमे में आवेदनों के एक समूह में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि करते हुए, तेलंगाना राज्य और कुछ तीसरे पक्षों सहित विभिन्न पक्षों ने इन दीवानी अपीलों को पेश किया है।

5. हमने श्री गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील को पक्षकारों के एक समूह की ओर से पेश होते हुए सुना है जो यहाँ अपीलकर्ता हैं।

(और जो डिक्री के समनुदेशकों होने का दावा करते हैं), श्री बी. आदिनारायण राव, श्री चंदर उदय सिंह, श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री संतोष कृष्णन, उन पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील जिन्होंने डिक्री (दावा याचिकाकर्ताओं) के निष्पादन में बाधा डाली और जो उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुए, श्री सी. एस. वैद्यनाथन, तेलंगाना राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री वी. वी. एस. राव, श्री हेमेंद्रनाथ रेड्डी और श्री के. एस. मूर्ति, तीसरे पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री दुष्यंत दवे, एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने एक याचिका दायर की है।

हस्तक्षेप के लिए आवेदन।

पृष्ठभूमि तथ्य:

6. हैदराबाद एक रियासत थी जब तक कि यह पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 18.09.1948 पर भारत संघ में शामिल नहीं हो गया था।

जिसे "ऑपरेशन पोलो" के नाम से जाना जाता है। हाय निजाम इसके थे।

तब तक शासक। जबकि आउटसोर्सिंग एक ऐसी चीज है जिससे हम अब केवल बीसवीं शताब्दी में परिचित हो गए हैं, एच. ई. एच. निजाम ने रक्षा सेवाओं को भी आउटसोर्सिंग करने की प्रथा को अपनाया है [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

200 साल पहले की बात है। ऐसा लगता है कि निजाम के पास सशस्त्र बलों की आपूर्ति और रखरखाव के उद्देश्य से लोगों को कुछ भूमि देने की प्रथा थी। इस प्रकार दी गई भूमि को "पैगाह" के नाम से जाना जाने लगा।

नाम खुर्शीद जाह और अनुदान खुर्शीद जाह के नाम से जाना जाने लगा पैगाह। हाथ में विवाद की प्रकृति और विस्तार को समझने के लिए, इतिहास में एक नज़र डालना प्रासंगिक हो सकता है।

7. ऐसा प्रतीत होता है कि मीर-कमर-उद-दीन खान (जिसे आसफ जाह की उपाधि दी गई थी) मुगलों के सामंती प्रमुखों में से एक था और

1713 से 1721 तक दक्कन का राज्यपाल। बाद में उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और हैदराबाद में आसफ जाही राजवंश की स्थापना की।

8. जैसा कि ग्रिबल ने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ़ डेक्कन' में कहा है, आसफ जाह अपने साथ कई अनुयायियों को लाए थे, जिनमें मुसलमान और हिंदू दोनों थे, जो उनके व्यक्तित्व और भाग्य से जुड़े थे। मुसलमान रईसों को, उन्होंने सैन्य कार्यकाल पर जागीर या संपत्ति प्रदान की और उन्हें अपने जनरलों के रूप में नियुक्त किया। हिंदुओं को मुख्य रूप से राजस्व और वित्त विभागों में प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त किया जाता था। उन्हें भी उन्होंने जागीरों को उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया और इन सभी जागीरों को चाहे नागरिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए दिया गया हो, वंशानुगत माना जाने लगा।

9. मुसलमान अनुयायियों में मोहम्मद प्रतिष्ठित थे।

पुरस्कृत किया गया और नए अनुदानों और सनदों के कारण उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई। 10. आखिरकार, वर्ष 1198 एच. (1784 ए. डी.) में या उसके आसपास जागीरें लगभग उसी समय से मेल खाती थीं जिसे उसके कुछ समय बाद पैगाह कहा जाता था।

निजाम अली खान ने उन्हें एक परवाना के तहत संपदा प्रदान की थी। उनकी मृत्यु पर, उसी संपत्ति और लगभग उसी क्षेत्र का एक नया अनुदान 1205 हिजरी में उनके बेटे फखरुद्दीन खान को दिया गया, जो उस समय नाबालिग थे। ऐसा लगता है कि यह अनुदान पैगाह अनुदान के रूप में दिया गया था।

11. वास्तव में, 1198 और 1205 एच के परवान में इस्तेमाल किया गया 'पैगाह' शब्द सेना के रखरखाव के लिए दी गई संपत्ति को दर्शाता है।

अबुल मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

फतेह खान ने वास्तव में एक निश्चित कीमत पर नियमित संख्या में सैनिकों को बनाए रखने का स्पष्ट रूप से बीड़ा उठाया। 1253 एच में। फखरुद्दीन खान के आवेदन पर, एक नियमित सनद दी गई थी। उस सनद की नींव है

12. हालाँकि, 1863 ईस्वी में फखरुद्दीन खान की मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े जीवित बेटे, रफीउद्दीन खान ने उनका स्थान लिया, जो स्वर्गीय निजाम मीर महबूब अली खान के अल्पमत के दौरान सर सालार जंग के साथ हैदराबाद राज्य के सह रीजेंट थे। रफीउद्दीन खान की मृत्यु पर उनके भाई रशीदुद्दीन खान और रफीउद्दीन खान के एक अन्य भाई सुल्तानुद्दीन खान के दो बेटों मोतासिम-उद-दौला और बशीर-उद-दौला (सर उस्मान जाह) के बीच पारिवारिक संपत्तियों को लेकर विवाद पैदा हो गया। इन झगड़ों के निपट जाने से पहले ही मोतासिम-उद दौला और रशीदुद्दीन खान की मृत्यु हो गई। अंततः 1882 ईस्वी में, सर सालार जंग द्वारा एक तरफ उस्मान जाह और दूसरी तरफ रशीदुद्दीन खान के दो बेटों, खुर्शीद जाह और विकर-उल-उमरा के बीच एक पुरस्कार दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप पैगाह तालुका नामक कुछ संपत्तियों को उस्मान जाह को प्रदान किया गया। श्री रिड्सडेल के पुरस्कार के परिणामस्वरूप परिवार के शेष पैगाह तालुकों को खुर्शीद जाह और विकर-उल-उमरा के बीच विभाजित कर दिया गया था। परिवार में आंशिक विभाजन था। 1878 ईस्वी में भी संपत्ति। इन व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप, मूल पैगाह एस्टेट तीन अलग-अलग एस्टेटों में विभाजित हो जाता है जिन्हें अस्मान जाहि पैगाह, खुर्शीद जाहि पैगाह और विकार-उल-उमराही पैगाह के नाम से जाना जाता है।

13. इसके बाद, अस्मान जाह, खुर्शीद जाह और विकर-उल-उमरा अपनी मृत्यु तक अपने-अपने पैगाहों के कब्जे में रहे। ये पैगाह अनुदान प्राप्तकर्ता, संपदाओं के पूर्ण मालिक नहीं थे। वास्तव में, हैदराबाद राज्य में जागीरें न तो प्रकृति में थीं

मद्रास राज्य के जमींदारों और न ही उत्तर प्रदेश के तालुकदारों के स्वामित्व अधिकार मद्रास के जमींदारों और अवध के तालुकदारों में निहित थे, जबकि हैदराबाद में जागीरदार केवल जीवन भर के लिए संपत्ति से राजस्व के उपभोग के हकदार थे। जागीरदार की मृत्यु पर अनुदान, कानूनी रूप से, क्राउन को वापस कर दिया जाएगा और नए जागीरदार को एक नए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। पैगाह एस्टेट, जिसके साथ यह मामला संबंधित है, इसका कोई अपवाद नहीं था। वास्तव में, चूंकि वे पैगाह सैनिकों को बनाए रखने के दायित्व के बोझ से दबे हुए थे, इसलिए यदि निजाम चाहें तो उन्हें फिर से शुरू किया जा सकता था। निजाम सैन्य बोझ को एक समतुल्य धन भुगतान में भी परिवर्तित कर सकता था और [2023] 8 एस. सी. आर. पर इस तरह के भुगतान की आवश्यकता होती थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पैगाह जागीर को फिर से शुरू करने का दर्द। उन्हें किसी भी समय यह कहने का अधिकार था कि उन्हें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके स्थान पर धन की आवश्यकता है।

14. इसके अलावा, जागीर जैसे पैगाह निजाम की सहमति के अलावा अविभाज्य और निष्पक्ष थे। इसलिए, उपर्युक्त विभाजनों के लिए निजाम की सहमति की आवश्यकता थी। वास्तव में, कई विभाजन जो हुए, उनमें स्पष्ट रूप से निजाम की निहित सहमति थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 12 वें रजब 1337 एच. (12-4-1919) को निजाम ने आदेश दिया था कि पैगाह जागीरों को आगे विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

15. लेकिन तथ्य यह है कि पैगाह जागीरों को उस समय शारीरिक रूप से विभाजित नहीं किया जाना था, ऐसे सदस्यों को नहीं रोका

जागीरों की आय के शेयरों को विभाजित करने से परिवार जो कानूनी रूप से इसके हकदार हैं।

16. हैदराबाद राज्य में पैगाह के साथ-साथ जागीरों और इनामों की एक विशेष विशेषता यह थी कि इस संपत्ति का अधिकार एक व्यक्ति को दिया गया था।

पैगाह धारक के रूप में एकल व्यक्ति (पैगाहों के मामले में) जो इसके अलावा

निश्चित रूप से, अमीर के हिस्से और प्रशासनिक खर्चों को काटने के बाद, विरासत द्वारा राजस्व में हिस्सेदारी। अमीर के पास एक था पैगाह के प्रमुख और प्रबंधक और निजाम और जनता के प्रति इसके प्रतिनिधि के रूप में अपने पद का समर्थन करने के लिए अपना विशेष हिस्सा। यह हिस्सा पहले अप्रमाणित था। यही कारण था कि सर खुर्शीद जाह और पैगाह के अन्य संबंधित धारकों की मृत्यु तक, अमीरों पर ही विचार किया जाना था और वे अपने लिए आय का वह हिस्सा ले सकते थे जो वे उचित समझते थे।

18. आय के विनियोग के इस तरह के मनमाने और मनमौजी तरीके से हुए अन्याय को दूर करने के लिए कई समितियां आईं

प्रस्तावों के साथ। सर ब्रेन एगर्टन की समिति ने अन्य मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर लिमिटेड के बीच प्रस्ताव रखा।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्फी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

जिन चीजों को अमीर को रुपये में 11 डी 2 आना लेने की अनुमति दी जानी चाहिए

पैगाह की सकल आय। रेली आयोग ने प्रस्तावित किया

कि अमीर को पैगाह की सकल आय के बजाय शुद्ध का एक निश्चित हिस्सा लेना चाहिए। वास्तव में, जागीरों के संबंध में 1340 एच का फरमान भी था कि प्रबंधक को शुद्ध आय के रुपये में 4 आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

19. सर खुर्शीद जाह की मृत्यु रबी-अल-थानी, 1320 हिजरी (जुलाई, 1902) को हुई थी और वे अपने पीछे दो बेटे, इमाम जंग और जफर को जीवित छोड़ गए थे।

जंग उनके एकमात्र मान्यता प्राप्त वैध उत्तराधिकारी थे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अनुदानकर्ता की मृत्यु पर जागीर का कोई भी अनुदान क्राउन को समाप्त हो जाएगा और पिछले अनुदानकर्ता के किसी भी उत्तराधिकारी को एक नया अनुदान दिया जा सकता है। निजाम के पास जागीरों को फिर से शुरू करने या किसी को भी नियुक्त करने के लिए पर्याप्त शक्तियां थीं।

व्यक्ति, चाहे वह सबसे बड़ा बेटा हो या नहीं, अमीर के रूप में या कोई अन्य व्यक्ति

व्यवस्थाएँ।

20. सर खुर्शीद जाह की मृत्यु पर, 1345 एच (फरवरी, 1927) तक उस पैगाह के संबंध में निजाम द्वारा कोई अमीर नियुक्त नहीं किया गया था और परिवार के किसी भी सदस्य को पैगाह का पूरा प्रभार नहीं दिया गया था। नवाब जफर जंग, सर खुर्शीद जाह की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद जारी एक फरमान के तहत, सामान्य नियमित काम को जारी रखने के लिए केवल पर्यवेक्षक और ट्रस्टी के रूप में खुर्शीद जाही पैगाह के प्रभारी बनाए गए थे और उन्हें सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निजाम के आदेश लेने और संपत्ति की आय और व्यय का हिसाब रखने का निर्देश दिया गया था।

21. इस पैगाह एस्टेट का प्रशासन, जैसा कि के मामले में

अन्य पैगाहों, जिनमें इसी तरह की व्यवस्था की गई थी, ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और वास्तव में ये सभी संपदाएँ भारी ऋण में डूब गईं। पैगाहों के सदर-उल-मोहम्मद नामक पैगाह मामलों के एक महानियंत्रक को निजाम द्वारा उनके आदेश पर तीन पैगाहों का पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह कदम सफल साबित हुआ और समिति के सक्षम और कुशल प्रबंधन ने भारी ऋणों को मिटाने के बाद प्रत्येक पैगाह संपदा के लिए सराहनीय भंडार बनाने में मदद की।

22. यह तब था जब लुत्फुद्दौला को 29 वें राजजाब, 1345 एच (2-2-1927) ए. डी. के फरमान के तहत अमीर नियुक्त किया गया था। अंतराल के दौरान, खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों को विभाजित करने की अनुमति नहीं थी, हालांकि उनके दो बेटों और उनके बच्चों द्वारा दावे किए गए थे।

23. विभिन्न उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, निजाम ने तीन शाही आयुक्तों को नियुक्त किया: (1) एगर्टन [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समिति (2) ग्लेंसी आयोग और (3) रेली आयोग। 24. इन रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, 17 जनवरी, 1929 (5 शाहबान 1347 एच) को एक फरमान जारी किया गया था।

इसमें कहा गया है कि पैगाह के संबंध में, वह तीन गुना क्षमता रखता था (i) राज्य के शासक के रूप में (ii) सरफ-ए-खास के प्रमुख के रूप में और (iii) पैगाह परिवार के संरक्षक के रूप में।

25. फरमान के सामान्य आदेशों के पैरा 2 में, उन्होंने निर्देश दिया कि "अब तक जो भी संपत्ति या वस्तुएँ अर्जित की गई थीं।

पैगाहों की आय से खरीदी गई या निर्मित इमारतों को पैगाहों की संपत्ति माना जाएगा, न कि किसी की।

व्यक्तिगत, और यह मथरुका की तरह विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा

संपत्ति "।

26. आदेश II में निजाम ने निर्देश दिया कि सकल राशि का एक-तिहाई

आय को जागीर के प्रशासनिक प्रभारों के लिए विनियोजित किया जाना चाहिए, और दूसरा-तीसरा प्रबंधक का हिस्सा होगा, यानी पैगाह अमीर का हिस्सा और शेष एक-तिहाई अन्य उत्तराधिकारियों, यानी पैगाह के शेयरधारकों का हिस्सा होगा।

27. आदेश III पैरा 9 में, उन्होंने आगे निर्देश दिया कि बहुमूल्य पत्थर, आभूषण और दुर्लभ वस्तुएँ, जो सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की गई हैं।

फरमान के पैरा 2 में नीचे से पैगाह की संपत्ति है

पुराना समय, या पैगाहों से संबंधित धन से खरीदा गया है, ट्रस्ट में पैगाह अमीर के पास रहेगा। पैगाह अमीर के पास नहीं होगा

उन्हें किसी भी व्यक्ति को बेचने, गिरवी रखने या देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के बाद पैगाह परिवार के सदस्यों को अस्थायी उपयोग के लिए उधार दिया जा सकता है समय-समय पर निजाम की मंजूरी, बशर्ते अमीर उनकी सुरक्षा और सावधानीपूर्वक उपयोग के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए। आदेश III पैरा 2 में, निजाम ने निर्देश दिया कि यदि किसी पैगाह की निर्वसीयत संपत्ति के रूप में कोई संपत्ति बची है, तो उसके वितरण का निपटारा भी फरमान द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा।

28. निजाम ने आदेश III, पैरा 2 में कहा कि सर खुर्शीद जाह की मृत्यु के समय उनके दो बेटे इमाम जंग और जफर जंग उनके थे।

केवल उत्तराधिकारी, जो, यदि जीवित होते, तो सकल आय के प्रत्येक तीसरे हिस्से के आधे हिस्से के हकदार होते, और चूंकि दोनों मर चुके हैं और उनके जीवित बचे लोगों की संख्या बड़ी थी और उनमें से कुछ के बारे में (विशेष रूप से जफर जंग के उत्तराधिकारियों के बीच) मतभेद था।

कुछ विवाहों की वैधता और कुछ बच्चों की वैधता के बारे में, मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तीसरे भाग के वितरण के लिए एक समिति नियुक्त की जानी थी।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

खुर्शीद जाह के दो बेटों के उत्तराधिकारियों के बीच खुर्शीद जाहि पैगाह की सकल आय।

29. इस समिति की अध्यक्षता हैदराबाद के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश नवाब मिर्जा यार जंग ने की थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

17 जनवरी, 1929। पैगाह समिति के रूप में जानी जाने वाली इस समिति ने एक निश्चित निष्कर्ष दिया कि नवाब खुर्शीद जाह ने ऐसी कोई संपत्ति नहीं छोड़ी जो पैगाह आय से अर्जित या खरीदी नहीं गई थी।

फरमान के प्रारंभिक भाग के पैरा 2 का अर्थ। इस प्रकार, सर खुर्शीद जाह ने जो कुछ छोड़ा वह था (1) पैगाहों की आय से खरीदी गई संपत्तियां या वस्तुएं या इमारतें और (2) कीमती पत्थर, आभूषण और दुर्लभ वस्तुएं जो फरमान में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्राचीन काल से पैगाहों की संपत्ति हैं। कई बार, या पैगाहों से संबंधित धन से खरीदे गए हैं जो पैगाह अमीर द्वारा पैगाह परिवार के विरासत के रूप में ट्रस्ट में रखे गए हैं। नवाब सर खुर्शीद जाह के उत्तराधिकारियों के बीच, फरमान को देखते हुए, इन दो वर्गों की संपत्तियों का वितरण, उनके संचय सहित, नहीं किया जा सका, क्योंकि उन्हें अविभाज्य, निष्पक्ष और अविभाज्य माना जाता था। अमीर पैगाह इन संपत्तियों के लिए केवल एक पर्यवेक्षक और ट्रस्टी थे।

30. इस रिपोर्ट के बीस साल बाद, राजनीतिक माहौल बदल गया और जागीरों और पैगाहों को जागीर के माध्यम से समाप्त कर दिया गया।

उन्मूलन विनियम (1358 एफ का हैदराबाद विनियम संख्या 69) 15.08.1949 से प्रभावी। जागीरों और जागीरों से जुड़ी संपत्तियों पर जागीर प्रशासक ने कब्जा कर लिया था और जागीरदारों को केवल परिवर्तन राशि का हकदार घोषित किया गया था। हालांकि, जागीरों से असंबद्ध अन्य संपत्तियों और संपदाओं को जागीरदारों के पास रहने की अनुमति दी गई थी।

31. वर्ष 1955-56 में, दिलदार-उन-निसा बेगम नाम की एक महिला, जो खुर्शीद जाह के वंशजों में से एक थी, ने एक मुकदमा दायर किया।

सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद की फाइल पर 1955-56 का O.S.No.41, यह दावा करते हुए कि (i) नवाब खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई संपत्ति एक मातृका एस्टेट थी; और (ii) कि वह 29/2944 शेयर की हकदार है। इस स्तर पर यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि 1955 के ओएस नंबर 41 में लड़ाई, जैसा कि मूल रूप से शुरू की गई थी, वास्तव में एक ओर नवाब जफर जंग के जीवित उत्तराधिकारियों और दूसरी ओर नवाब इमाम जंग के जीवित उत्तराधिकारियों के बीच थी। (नवाब जफर जंग और नवाब इमाम जंग खुर्शीद जाह के पुत्र थे)। सटीक रूप से, नवाब जफर जंग के जीवित उत्तराधिकारियों को (i) वादी; और (ii) प्रतिवादी [2023] 8 एस. सी. आर. के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नं. 1-35 और 44-49। इसी तरह, नवाब इमाम जंग के जीवित उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी संख्या के रूप में रखा गया था। 36-42 और 50। प्रतिवादी No.43 हैदराबाद सरकार का जागीर प्रशासक था। यहाँ यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि वाद की स्थापना के समय, केवल 43 प्रतिवादी थे जिनमें जागीर प्रशासक अंतिम थे, अर्थात् प्रतिवादी No.43। हालाँकि, बाद में मूल प्रतिवादियों की एक के बाद एक मृत्यु और कई अन्य कारकों के कारण प्रतिवादियों की संख्या असहनीय अनुपात में बढ़ गई, जिन्हें हम बाद में देखेंगे।

" इसलिए वादी प्रार्थना करता है कि एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाए:
(क) यह निर्देश देते हुए कि अनुसूची IV में वर्णित गुण जो हैं -

उस भाग के कब्जे में जो उसमें विस्तृत है और अन्य (बी) श्रेणी की संपत्तियां जो ऊपर पैरा (12) में विस्तृत हैं -

प्रतिवादी संख्या 43 का कब्जा और अन्य सभी संपत्तियां जो भी स्वर्गीय नवाब खुर्शीद जाह के मातृका से संबंधित पाई जा सकती हैं, उन्हें मेट्स एंड बाउंड्स द्वारा विभाजित किया जाएगा और वादी को उसमें 29/2944 वां हिस्सा दिया जाएगा।

(ख) एक आयुक्त की नियुक्ति-उक्त संपत्तियों का प्रभार लेने और उन्हें उन व्यक्तियों के बीच विभाजित करने के लिए जो

वैध रूप से इसके हकदार हैं;

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 से 43 तक को उक्त मातृका के संबंध में उपार्जित सभी लाभों और आय का लेखा देने का निर्देश देना।

मुकदमे की तारीख तक और उसके बाद लंबित रहने के दौरान की संपत्तियाँ

इस सूट का; और

(घ) प्रतिवादियों को इस वाद के लंबित रहने के दौरान किसी भी तरह से उपरोक्त संपत्तियों में से किसी पर बोझ डालने पर अलग करने, बदलने से रोकना। यदि मातृका संपदा की किसी भी संपत्ति को किसी भी प्रतिवादी द्वारा अलग कर दिया गया है, तो उसे उनके हिस्से में डेबिट किया जाए या उनसे बरामद करने का आदेश दिया जाए, यदि वह इस मामले में है।

उनके हिस्से से अधिका

वादी आगे प्रार्थना करता है कि उचित आदेश पारित किए जाएं

भुगतान वादी का खर्च मथरुका एस्टेट से निकलता है।

और इस तरह की और अन्य राहत दी जाए और आदेश पारित किए जाएं।

जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे। मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

33. उन कारणों के लिए जो तुरंत समझने योग्य नहीं हैं, हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट में दायर उक्त मुकदमे को उच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया था।

निकासी और स्थानांतरण भी हो सकता था (केवल एक अनुमान) लेटर्स पेटेंट के खंड 13 के संदर्भ में या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 (1) (बी) (आई) के संदर्भ में। यह याद रखना चाहिए कि जब तक

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत नवंबर, 1956 में उच्च न्यायालय का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कर दिया गया, उच्च न्यायालय हैदराबाद का उच्च न्यायालय था। मुकदमा जैसा कि मूल रूप से दायर किया गया था, वर्ष 1955-56 में था, लेकिन वापसी और हस्तांतरण वर्ष 1958 में हुआ और मुकदमे को 1958 के CS No.14 के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया।

34. चूंकि वर्तमान विवाद की उत्पत्ति का पता 1958 के सी. एस. सं. 14 में दिए गए वाद से लगाया जाना चाहिए, इसलिए वाद का मुख्य भाग निकालना आवश्यक है। इसलिए, शिकायत के पैराग्राफ 6 से 17 को इस प्रकार पढ़ा जाता है:

" 6.1320-एच में नवाब खुर्शीद जाह की मृत्यु के बाद, न तो

पैगाह एस्टेट और न ही मथरुका को विभाजित करने की अनुमति दी गई थी

दावों के माध्यम से उनके दो बेटों द्वारा और बाद में उनके बच्चों द्वारा आगे बढ़ाया गया था। पैगाह एस्टेट या नवाब खुर्शीद जहाँ के मथरुका के विभाजन की अनुमति नहीं देने का कारण प्रतीत होता है कि महामहिम निजाम आगे विभाजन के खिलाफ थे और इस प्राचीन परिवार को समग्र रूप से संरक्षित करना चाहते थे और इसकी अखंडता और भव्यता को बनाए रखना चाहते थे। यह 8 वें खुर्दाद 1328 फसली और 5 वें शबान 1347 एच के अनुरूप 11 वें रजब 1337 एच के महामहिम के दो फरमानों से स्पष्ट है।

15 इस्कंदर 1338 फसली (17. 1.1929)। उक्त दोनों की प्रतियाँ

फरमानों को इसके साथ दाखिल किया जाता है और द्वितीय और तृतीय को चिह्नित किया जाता है।

महामहिम निजाम ने तीन शाही नियुक्त किए
आयोग अर्थात्:

(1) एगर्टन समिति,

ग्लैंसी कमीशन, और

(2)

(3) रायली आयोग

इन तीन आयोगों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, महामहिम ने अंतिम उल्लिखित फरमान दिनांक जारी किया।

1 इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

17-1-1929 , (पैगाह एस्टेट को संरक्षित करने और पैगाह परिवार को स्थायी बनाने के उद्देश्य से)।
8. उपरोक्त के पैरा 2 में-फरमान दिनांक 17-1-1929 (चिह्नित III) महामहिम निजाम ने निम्नानुसार निर्देश दिया:

" पैगाहों की आय से अब तक जो भी संपत्ति अर्जित की गई है या वस्तु खरीदी गई है या भवन का निर्माण किया गया है, उसे पैगाहों की संपत्ति माना जाएगा, न कि किसी व्यक्ति की, और यह विरासत (मातृका) के रूप में विभाजित होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

9. महामहिम निजाम ने आदेश III पैरा 9 में उक्त फरमान के अनुसार आगे निर्देश दिया:

" बहुमूल्य पत्थर, आभूषण और दुर्लभ वस्तुएं जो उपरोक्त (फरमान पैरा 2) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पुराने समय से पैगाहों की संपत्ति हैं, या जिन्हें पैगाहों से संबंधित धन से खरीदा गया है, पैगाह के पास ही रहेंगे।

हालाँकि समय-समय पर मेरी मंजूरी प्राप्त करने के बाद उन्हें पैगाह परिवार के सदस्यों को अस्थायी उपयोग के लिए उधार दिया जा सकता है, बशर्ते अमीर उनके सुरक्षित और सावधानीपूर्वक उपयोग के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराए।

10. फरमान के क्रम III, पैरा (2) में (ऊपर उल्लिखित) एच. ई. एच. निजाम ने संपत्ति के दूसरे और तीसरे वर्ग का उल्लेख किया और

निम्नानुसार निर्देशित किया गया: " यदि किसी पैगाह में निर्वसीयत संपत्ति (मातृका) के रूप में कोई संपत्ति बची है तो उसके वितरण का निपटारा भी उसी समिति द्वारा किया जाएगा।

फरमान के हिस्से में संदर्भित समिति

ऊपर उद्धृत नवाब मिर्जा यार जंग समिति है जिसकी रिपोर्ट 9 अप्रैल 1929 को प्रस्तुत की गई थी। महामहिम निजाम ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और तदनुसार फरमान जारी किया। मिर्जा यार जंग समिति की उक्त रिपोर्ट में एक निश्चित निष्कर्ष दिया गया था कि दावेदारों द्वारा यह साबित नहीं किया गया था कि नवाब खुर्शीद जाह ने प्रारंभिक भाग के पैरा (2) के अर्थ के भीतर कोई ऐसी संपत्ति छोड़ी थी जिसे पैगाह आय से अर्जित या खरीदा नहीं गया था। फरमान का।

ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

(क) खरीदी गई संपत्तियाँ या वस्तुएँ या पैगाह की आय से निर्मित भवन, (ख) पैगाह परिवार के विरासत के रूप में पैगाह अमीर द्वारा विश्वास में रखे गए पैगाह से संबंधित धन से खरीदे गए कीमती पत्थर, आभूषण और दुर्लभ वस्तुएँ।

12. 5 शबाना 1347 एच (17-1-1929-ए. डी.) के फरमान के अनुसार, एच. ई. एच. निजाम ने उपरोक्त मथुरका संपत्तियों के दो वर्गों के वितरण और श्रेणी (ए) से संबंधित संपत्तियों की सूचियों को रोक दिया, जिसमें सभी परिवर्धन और परिवर्धन शामिल हैं, जहां तक वादी को पता है कि इसके साथ दायर की गई अनुसूची में दिए गए हैं और

चिह्नित IV और IV (a) का अनुमानित मूल्य O.S.Rs.652058-2-0 है और वे व्यक्तियों के कब्जे में हैं।

उक्त अनुसूची में संदर्भित। वादी को उपरोक्त पैरा 11 में उल्लिखित श्रेणी (बी) में निर्दिष्ट बहुमूल्य पत्थरों, आभूषणों और दुर्लभ वस्तुओं की सीमा और मूल्य के बारे में जानकारी नहीं है। अंतिम उल्लिखित संपत्तियाँ जो आमिर पैगाह के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में होनी चाहिए थीं, उन्हें सुरक्षित हिरासत में छोड़ दिया गया था।

पुलिस कार्रवाई के दिनों के दौरान सरकारी खजाने में और बाद में जागीर प्रशासक की हिरासत में चला गया

13. पैगाह सहित हैदराबाद राज्य में जागीरों को 1358 एफ के जागीर उन्मूलन विनियमन संख्या 69 द्वारा समाप्त कर दिया गया था, 15 अगस्त 1949 से मथुरका संपत्तियों की उपरोक्त दो श्रेणियों के विभाजन को रोकते हुए सईद फरमानों का संचालन बंद हो गया और वादी स्वर्गीय नवाब खुर्शीद की माथुरका संपत्ति में अपने वैध हिस्से का दावा करने का हकदार बन गया। जाह, उनका 29/2944 वां हिस्सा, जिसे वह अस्थायी रूप से ओ. एस. रुपये 7408-1-1 की कुल राशि के रूप में मानती हैं, जैसा कि अनुसूची में विस्तृत है। IV और IV (ए) पैरा 12, जो ओ. एस. रु. के कुल अनुमानित मूल्य के ऊपर निर्दिष्ट है। 752058-20 .

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. इस मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण 15 अगस्त 1949 को हैदराबाद-डी. एन. में उत्पन्न हुआ जब जागीर उन्मूलन विनियमन लागू हुआ और महामहिम निजाम के फरमानों ने विभाजन को रोक दिया। मुकदमे की संपत्तियों का परिचालन बंद हो गया। मुकदमा किसी भी स्थिति में समय पर है, क्योंकि अनुसूची IV और IV (ए) में अधिकांश संपत्तियाँ अचल संपत्तियाँ हैं और श्रेणी (बी) में अन्य संपत्तियाँ हैं और पैरा 13 में निर्दिष्ट प्रतिवादी संख्या 1 अमीर पैगाह ट्रस्ट के पास थीं और अब प्रतिवादी No.43 के पास हैं। इसके अलावा 14 और 15 अगस्त 1955 को रविवार के कारण अवकाश था।

और स्वतंत्रता दिवस।

15. वादी इस मुकदमे के दावे को अदालत के उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से महत्व देता है-शुल्क और अधिकार क्षेत्र O.S.Rs पर। 7405-1-1, उपरोक्त अनुसूची IV और IV (ए), पैरा 13 में विस्तृत संपत्तियों के उसके हिस्से का मूल्य समान है और वादी अदालत का भुगतान करता है-ओ. एस. रु. 562-7-0 , और ऐसे अतिरिक्त न्यायालय-शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करने का वचन देता है, जब विभाज्य संपत्तियों का पता लगाया जाता है और उनकी

सही मान तय किए जाते हैं।

16. वादी प्रस्तुत करता है कि अनुसूची IV और उसमें बताए गए मूल्य किसी भी तरह से संपूर्ण या पूर्ण नहीं हैं और इसी तरह कीमती पत्थरों और आभूषणों के मूल्य समान रूप से अनुमानित और अस्थायी हैं। यह संभव है कि अन्य मातृका संपत्तियाँ भी हों जो पक्षों के बीच विभाज्य हों। वादी स्वर्गीय नवाब खुर्शीद जाह की मातृका से संबंधित जो भी संपत्तियाँ पाई जा सकती हैं, उनमें 29/2944 वें के अपने वैध हिस्से का दावा करती है और उचित अदालत-शुल्क का भुगतान करने का वचन देती है।

17. इस माननीय न्यायालय के पास इस मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि इस विभाजन की विषय वस्तु अचल संपत्तियों का बड़ा हिस्सा हैदराबाद शहर में स्थित है और सभी प्रतिवादियों को छोड़कर प्रतिवादी No.36 हैदराबाद शहर में रहता है।

35. दिलचस्प बात यह है कि शिकायत को पहले वर्ष 1957 में संशोधित किया गया था, जिसमें अभियोग अनुसूची IV की रियाल Nos.29 और 30 उल्लिखित संपत्तियों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर लिखित आदेश के जवाब के रूप में 17 ए जोड़ा गया था। इसके बाद, वर्ष 1958 में अभियोग में दो बार संशोधन किया गया ताकि पैराग्राफ 17 बी और 17 डी को जोड़ा जा सके। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप कुछ लोगों को शामिल किया गया मुकदमे में राष्ट्रीय प्रतिवादी, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य और मैसूर राज्य प्रतिवादी संख्या के रूप में शामिल हैं। 53 और क्रमशः 55।

ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

36. अभियोग के ये पैराग्राफ 17 ए, 17 बी, 17 सी और 17 डी इस प्रकार हैं:

" 17 ए. लिखित कथन के पैरा 7 के अनुसार प्रतिवादी नं. 1 ने दावा किया है कि अनुसूची नं. 4 के क्रम No.29 और 30 में शिकायत के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित मातृका संपत्तियाँ, जमुतनपुर रामधन चौधरी और नजीब बाग में हैं।

मिसबाहुद्दीन खान और गौसुद्दीन खान का अधिकार, अधिकार के गुण से। यह दावा प्रतिवादी संख्या 1, दोनों कथित नाबालिगों के कानूनी और शरिया संरक्षक द्वारा किया गया है। यह वादी प्रतिवादी संख्या 1 के उपरोक्त दोनों बेटों के स्वामित्व के विवाद को स्वीकार नहीं करता है। उन दोनों के नाम प्रतिवादियों की श्रृंखला में शामिल किए गए हैं। इस प्रकार वादी मुकदमा करने का हकदार है और प्रतिवादी संख्या 1 के उपरोक्त दोनों पुत्र जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं (पैरा 17 ए को इस प्रकार जोड़ा गया है)

प्रति आदेश दिनांक 20.9.57)

17 बी. कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान के माध्यम से पता चला है कि अनुसूची 4 की मदें Nos.37 और 40 और अनुसूची 4 ए की संख्या 13 से 15 में उल्लिखित संपत्तियां ए. पी. राज्य के कब्जे में हैं। चूंकि ये वाद संपत्तियां हैं, इसलिए ए. पी. राज्य मुकदमे का एक उचित और आवश्यक पक्ष है। इस माननीय अदालत ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। कथित राज्य प्रतिवादी के रूप में, इसलिए इसे संशोधन के माध्यम से एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता है। इस प्रतिवादी को उक्त संपत्तियों पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि उक्त प्रतिवादी उसी के लाभ का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है और वादी उन्हें प्राप्त करने का हकदार है। इसलिए वादी मुकदमा करने का हकदार है और प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उक्त प्रतिवादियों को सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत नोटिस जारी किया गया है। उसी को प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी ने इस तथ्य के बावजूद इसका कोई जवाब नहीं दिया है कि इसकी प्राप्ति को दो महीने बीत चुके हैं।

17 सी. कि प्रतिवादी नंबर 1 बाल राज के लिखित बयान के अनुसार, प्रतिवादी No.54 के पास बाग हुसैन शाह बली है, जो एक वाद संपत्ति है, इसलिए, उसे एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता है और वह अपनी संपत्ति का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। आदेश के अनुसार किया गया संशोधन

दिनांकित 25.1.58।

17 डी. कि वादी को प्रतिवादी सं. के लिखित बयान के माध्यम से पता चला है। 1 , कि अनुसूची IV आइटम No.16 अनुसूची IVA [2023] 8 एस. सी. आर. के आइटम संख्या 35 और 36 में गुण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(अचल) मैसूर राज्य के कब्जे में हैं। चूँकि ये मुकदमे की संपत्तियों का एक हिस्सा हैं, इसलिए मैसूर राज्य मुकदमे के लिए एक उचित और आवश्यक पक्षकार है, इस माननीय अदालत ने

राज्य को प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई। इसलिए इसे संशोधन के माध्यम से एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता है। इस प्रतिवादी ने

उक्त संपत्तियों पर कब्जा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त प्रतिवादी वादी को एक हिस्से के अनुसार बहुत अधिक लाभ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी वह हकदार है। अतः वादी उक्त प्रतिवादी पर मुकदमा करने का हकदार है और प्रतिवादी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 80 सी. पी. सी. के तहत उक्त प्रतिवादी को सूचना जारी की गई थी कि उसकी प्राप्ति के बाद दो महीने का समय बीत गया था, लेकिन वादी को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया था। (दिनांकित 4.10.58 आदेशों के अनुसार संशोधित) "।

37. वर्ष 1961 में, मुकदमे के कुछ पक्षों ने एक

समझौता करें। जिन पक्षों ने उक्त समझौता किया, वे वादी संख्या थे। 1 और 2 और प्रतिवादी संख्या। 1 , 5 , 6 , 7 , 9 , 11-14 , 16-34 , 35 , 36 , 37 , 40-42 , 44 , 45 , 46 , 48 , 49-52 , 56-62 , 90-94 , 97 , 99 और 100। इस स्तर पर यह दर्ज किया जाना चाहिए कि शुरुआत में केवल एक ही वादी था

अर्थात् दिलदार-उन-निसा बेगम। लेकिन बाद में, प्रतिवादी No.38 को वादी संख्या 2 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह दो वादी थे।

38. समझौता करने वाले पक्षों ने आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के तहत 1961 के आवेदन No.264 में एक आवेदन दायर किया।

समझौते को दर्ज करना और एक प्रारंभिक डिक्री पारित करना। 1961 के आवेदन No.264 में मांगे गए उत्कीर्णन एक दिलचस्प पठन बनाते हैं और इसलिए उन्हें निम्नानुसार निकाला जाता है:

" आदेश 23, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन,

प्रार्थना करते हुए कि उच्च न्यायालय के साथ दायर समझौता ज्ञापन में बताई गई परिस्थितियों में प्रसन्न हो सकता है

1) समझौते के पैरा 18 और 19 में उल्लिखित विवाद के प्रश्नों और उन लोगों के अधिकारों को तय करने के बाद समझौते के संदर्भ में एक प्रारंभिक डिक्री पारित करना जिन्होंने समझौते को संयुक्त नहीं किया है।

(ग) प्रतिवादी सं. के पक्ष में अंतिम डिक्री पारित करना। 1 , 51 , 52 और 42 पैरा 4,7,9 और में उल्लिखित उनके अनन्य शेयरों को दी गई संपत्तियों की सीमा तक;

IV) फतेह सुल्तान लेन, नामपल्ली, हैदराबाद में रहने वाले श्री हफीज अहमद खान सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश, अधिवक्ता को मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निर्धारित शक्तियों के साथ रिसीवर-सह-आयुक्त के रूप में नियुक्त करना।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

समझौते का ज्ञापन और उसके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए अन्य अभियुक्त "

39. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं। 1 , 2 , 5 18,21 से 29,33,34,36 से 43,47,49 से 55,77,78 और 95 से 97 ने अपने लिखित बयान दाखिल किए। अन्य प्रतिवादियों ने कोई लिखित बयान दायर नहीं किया। प्रतिवादी सं।

3 , 4 , 19 , 29 32, 35 और 48 को पूर्व पक्ष निर्धारित किया गया था।

40. दलीलों के आधार पर, अदालत ने 50 के रूप में तैयार किया मुद्दे। कुछ मुद्दों में उप मुद्दे भी थे।

41. लेकिन मुकदमे के बाद, अदालत ने मुद्दा संख्या को रद्द कर दिया। 14 (ई) और 21।

42. मुकदमे के दौरान, की ओर से छह गवाहों से पूछताछ की गई।

वादी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ग्यारह गवाहों से पूछताछ की गई। प्रतिवादी Nos.2,8,10,15,17,41,43,47,56 से 62,86 और 87 और 88 की ओर से एक गवाह से पूछताछ की गई। प्रतिवादी की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई। 12 और 13, प्रतिवादी संख्या। 48 और 49 और प्रतिवादी No.97। की ओर से छह गवाहों से पूछताछ की गई

प्रतिवादी No.39 और प्रतिवादी No.53 की ओर से चार।

43. वादी के पक्ष में, 30 दस्तावेजों को चिह्नित किया गया था

प्रदर्शनी पी. 1 से पी. 30 तक चलती है। प्रतिवादी संख्या 1 ने 52 दस्तावेज प्रस्तुत किए जिन्हें प्रदर्शनी डी 1 (1) से डी 1 (52) के रूप में चिह्नित किया गया था। अन्य प्रतिवादियों ने भी कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

44. अंततः, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के रूप में बैठे

ट्रायल जज ने आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के तहत मुकदमे और आवेदन दोनों में 28.06.1963 पर एक निर्णय और डिक्री पारित की। निर्णय के संचालन भाग में दो भाग शामिल थे, एक प्रतिवादियों से संबंधित जो समझौते के पक्षकार नहीं थे और दूसरा उन लोगों से संबंधित जो समझौते के पक्षकार थे। निर्णय के कार्यात्मक भाग को इस प्रकार निकाला गया है:

पक्षकारों के अलावा अन्य प्रतिवादियों के संबंध में समझौता निम्नलिखित शर्तों में तय किया जाएगा:

(1) कि गुणों।

(क) शिकायत अनुसूची IV में उल्लिखित और आवेदन No.37/59 के लिए अनुलग्नक बनाने वाली सूची 'ए' में भी विस्तृत, मद 26,29,30,34,35 और 36 और नगरपालिका वाले

घरों

को

छोड़कर।

नं. 28 और अनुसूची के मद No.22 में 29; [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ख) लल्लागुड़ा में खुर्शीद बाग;

(ग) तैल चित्र, झूमर और फर्नीचर बारादरी। (अनुसूची IV में आइटम नंबर 1) और अनुसूची IV-B के पहले भाग में संदर्भित लिगामपल्ली गार्डन (आइटम No.27), जिसकी संख्या और मूल्य निर्धारित किया जाएगा

अंतिम डिक्री कार्यवाही;

(घ) अनुसूची 4-ख के भाग-2 में निर्दिष्ट आग्नेयास्त्रों और हथियारों और उनकी बिक्री की आय, संख्या और

(ई) भाग III में लेख, अनुसूची IV-B की उप-मद I, जैसा कि Exe.P-10 और P-12 में विस्तृत है, जागीर द्वारा लिया गया है। प्रशासक और बैंक में जमा।

(च) अनुसूची की उप-मद II में निर्दिष्ट सोने के सिक्के

IV-b जो जागीर द्वारा एक्स. पी.-9 के तहत लिए जाते हैं। प्रशासक; और

(छ) एक्स. पी.-8 में निहित आभूषण और प्राप्तकर्ता द्वारा तैयार की गई सूची

क्या परिसंपत्तियाँ खुर्शीद जाह के समय से आ रही हैं,

फरमान एक्स. पी.-30 दिनांक 5 शबबान, 1347 एच. के पैरा-2 और उसी फरमान के आदेश 3 खंड 9 द्वारा और स्वर्गीय नवाब खुर्शीद जाह के जीवित कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित होने के लिए उत्तरदायी हैं;

(2) वह गुण अनुसूची IV में आइटम 37 और 40 भी होंगे

विभाजन के लिए केवल तभी उपलब्ध है जब उन्हें सरकार द्वारा जारी किया जाता है;

(3) वह वादी संख्या 1 और प्रतिवादी 1 (मृत होने के बाद से) से 35,44,49,51,52,56 से 62,90,94,98,100 और 102 से 112 तक खुर्शीद जाह के उत्तराधिकार के क्रम में जफर जंग के माध्यम से उत्तराधिकारी हैं, और वादी संख्या 2 और प्रतिवादी 36,37,39 से 42,50,97,99 और 113 से 118 इमाम जंग के माध्यम से उत्तराधिकारी हैं, खुर्शीद जाह के उत्तराधिकार की पंक्ति में, जैसा कि फैसले के अनुलग्नक II में विस्तृत है;

(4) कि उपरोक्त संपत्तियों के साथ-साथ निर्णय के अनुलग्नक IV में शामिल संपत्तियों में, प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है, उसकी 51, 52 और 102 से 112 तक के कानूनी प्रतिनिधि एक तिहाई ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के हकदार हैं।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

हिस्सा; और शेष दो तिहाई में, इमाम जंग की पंक्ति में जीवित कानूनी उत्तराधिकारी एक आधे और जीवित कानूनी के हकदार हैं। जफर जंग की पंक्ति के उत्तराधिकारी, प्रतिवादी 51,52,102 से 112 को छोड़कर, और उनके व्यक्तिगत शेयर इस फैसले के अनुलग्नक III में विस्तृत हैं।

(5) कि इस न्यायालय के अधिवक्ता श्री पी. राम शाह को नियुक्त किया जाता है।

आयुक्त और वह इस निर्णय में निहित निर्देशों और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे आगे के निर्देशों के अधीन रहते हुए उसी का विभाजन करेंगे।

(6) कि आयुक्त उत्तराधिकारियों से लेखा लेगा

प्रतिवादी संख्या 1 और निम्नलिखित मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(क) मुकदमे के दौरान संपत्ति से आय और बचत

अवधि प्रतिवादी नंबर 1 आमिर के रूप में प्रबंधन में था

पैगाह, 1950 से उनकी मृत्यु की तारीख तक 26-11-1961, मुद्दे No.37 पर निर्णय के अनुसार;

(ख) अनुसूची IV की 51 से 53 वस्तुओं की बिक्री आय

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा महसूस किया गया;

(घ) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मरम्मत के लिए किए गए खर्च, बाग लिंगमपल्ली में विस्तार और सुधार (मद)

No.27) मुद्दे पर निर्णय के अनुसार No.22;

(7) आयुक्त संपत्ति का विभाजन करते समय यह भी करेगा

प्रतिवादी 9,10,11,14,15,16,18,19,21,22,24,25,30,31,32,40,42,48,49,62 और 93 को अनुलग्नक V के अनुसार उनके द्वारा किए गए हर्जाने के लिए ध्यान में रखें। गुण, उनके हिस्से की सीमा निर्धारित करने में;

(8) प्रतिवादी 86-88 दुकानों के संबंध में विदेशी हैं

नगरपालिका Nos.III C-113 से 120, जो वस्तु No.45 का एक हिस्सा है; गृह धारक नगरपालिका No.20-3-842 शाहगंज में स्थित है जिसमें 420 वर्ग किलोमीटर शामिल है। yds; हाउस बेयरिंग No.2-2-722 और टिनशेड शिबली गंज (दोनों को रथ खाना के रूप में जाना जाता है) में स्थित No.2-2-723 वाले; और शिबली गंज में स्थित नगरपालिका No.2-3-184 वाले बग्गी खाना, इन अन्य लोगों के शेयरों को [2023] 8 एस. सी. आर. के लिए अलग-अलग संपत्तियों को निर्धारित करके जितना संभव हो सके तैयार किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विदेशी का हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10, यदि वह अन्य भागीदारों के साथ अन्याय किए बिना किया जा सकता है।

आयुक्त का पारिश्रमिक अस्थायी रूप से निर्धारित किया जाता है

Rs.600/- प्रति माह।

वादी परिसंपत्तियों में से लागत का हकदार होगा।

अदालती शुल्क उस समय एकत्र किया जाएगा जब संपत्तियां मिलेंगी।

मूल्यांकन और विभाजन किया जा रहा है।

जहाँ तक समझौते के पक्षों का संबंध है, समझौते के संदर्भ में एक डिक्री का पालन किया जाएगा, जिसमें ऐसी शर्तें शामिल नहीं हैं -

आयुक्त और उन संपत्तियों के बारे में भी शर्तें जिन्हें प्रतिवादी 2 और 39 की संपत्तियां माना गया है।, मद No.26 और घर संख्या। 28 और अनुसूची IV में मद No.22 में 29; और जहाँ तक अनुसूची IV की मद No.34 का संबंध है, वह गुण साथ ही उससे जुड़ी बिक्री आय भी समझौते के पक्षों के बीच विभाजन के लिए उपलब्ध होगी, केवल जफर जंग के उत्तराधिकारियों के रूप में प्रतिवादियों 2 से 4,10,47,94 और 98 के देय शेयरों को अलग करने के बाद, जो दर्ज किए गए शेयरों के दोगुने पर काम करते हैं।

अनुलग्नक III में। समझौते के लिए पक्षों को शेयर आवंटित करते समय, प्रत्यर्थी, प्रतिवादी 119,120 और 121 के साथ-साथ प्रतिवादी No.77 के शेयरों को यथासंभव निर्धारित करके तैयार किया जा सकता है।

अलग की गई संपत्तियों को संबंधित विदेशी लोगों के हिस्से में अलग करना।

इस आदेश के पैरा (5) के तहत नियुक्त आयुक्त संपत्ति का विभाजन करेगा और फैसले में निहित निर्देशों और ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन समझौते की शर्तों का पालन करेगा। निर्देश जो समय-समय पर दिए जा सकते हैं।

कमीशन के निष्पादन में होने वाले खर्च होंगे -

परिसंपत्तियों से मिले। "

45. फैसले में पाँच अनुलग्नक थे। संलग्नक-I।

खुर्शीद जाह और खरगोशों के उत्तराधिकार की पंक्ति में उत्तराधिकारियों की सूची जिसमें वे हकदार थे। अनुलग्नक-II में खुर्शीद जाह और उनके उत्तराधिकारी उत्तराधिकारियों की सूची थी। अनुलग्नक-III ने संभावित भागीदारों के प्रत्येक हिस्से की राशि का संकेत दिया। अनुलग्नक-IV में अचल मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सूची शामिल है।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस

मृत्यु और ओआरएस। ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

ऐसी संपत्तियाँ जो स्वर्गीय खुर्शीद जाह के मातृका के रूप में मानी जाती थीं। में। वास्तव में, निर्णय का अनुलग्नक IV वास्तव में अभियोग अनुसूची IV का पुनरुत्पादन था, सिवाय उन लोगों के जो घोषित नहीं किए गए थे। अनुलग्नक-V में क्षतिग्रस्त संपत्तियों की सूची और संबंधित पक्षों द्वारा किए गए नुकसान की सीमा शामिल थी।

46. यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मुकदमा सी. एस. एन. नं. 14 1958 में

कानूनी और न्यायिक भ्रातृत्व, एक से अधिक कारणों से, सही और गलत दोनों। इस मामले के जिज्ञासु पहलुओं में से एक याचिका अनुसूची IV में सूचीबद्ध अचल संपत्तियों का विवरण था। यद्यपि मूल वाद की एक प्रति कागजी पुस्तकों के हिस्से के रूप में हमारे समक्ष दायर की गई है, लेकिन इसमें अनुसूचियाँ नहीं हैं। हालांकि, प्रारंभिक डिक्री के समर्थन में दिनांकित 28.06.1963 के फैसले के अनुलग्नक-IV में एक याचिका अनुसूची IV, IV (ए) और आवेदन संख्या 37/59 की सूची ए, ए-2, ए-3 और ए-4 में वर्णित वस्तुओं का पुनरुत्पादन। यही पाठक को यह समझने का उचित अवसर प्रदान करेगा कि कितनी असंख्य वस्तुएँ हैं।

अचल संपत्तियों का वर्णन वाद अनुसूचियों में करने की मांग की गई थी। इसलिए, हम निम्नानुसार पुनः उत्पादन करने के लिए विवश हैं:

" अनुलग्नक IV

उन अचल संपत्तियों की सूची जिन्हें स्वर्गीय खुर्शीद का मातृका माना जाता है

जाह।

एस. नं.

वस्तु संख्या में दिखाया गया है

वर्णन

का नाम

अभियोग अनुसूची

महल्ला या

जगह

4

3

2

शिकायत अनुसूची IV

कोटिका बंगला को भी कहा जाता है।

1 .

शाहगंज

1 .

बारा दारी, हाउस No.III C

3-1060 .

इशरत महल, घर No.III

2 .

2 .

" "

सी-3-1

दीवान खाना, हाउस No.III

3 .

3 .

23

- सी-3-1040

4 .

छोटा महल नं. 1, हाउस

33

4 .

No.II C-3-140।

नया महल हाउस No.III

5 .

5 .

सी-3-1053/13

इमारतों के साथ खाना बाग

6 .

6 .

" "

घर No.III C-3-139।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7 .

7 .

देवड़ी इमाम जंग हाउस

✓

No.III-C-3-1059 और 1066

8 .

8 .

नवाजीश महल हाउस

No.III-C-3-123/5।

खुर्शीद महल हाउस

9 .

9 .

No.IIIC-3-123/1

इमारत के साथ फरीद बाग

99

10 .

10 .

भाग घर No.IIIC-3

123/3 और 123/4

11 .

नुबारक

महल हाउस

11 .

शाहगंज

No.III C-3-1059/12।

कोटर का मकान, सेना

99

12 .

12 .

गार्ड क्वार्टर। मकान नं.

III सी-3-121

खास महल हाउस संख्या।

13 .

13 .

99

आई. आई. आई. सी.-3-1059/3

आई. आई. आई. सी.-3-1059/4

आई. आई. आई. सी.-3-1059/6

आई. आई. आई. सी.-3-1059/7

आई. आई. आई. सी.-3-1059/9

कोटोरा हौज, III सी-3-1040

14 .

14 .

बांग्ला नागपंचमी। II सी

15 .

15 .

3 .

16 .

16 .

महल सारा III सी-3-1059/2

टोटल महल (संख्या 2) III सी

" "

17 .

17 .

3-1059 / 1

18 .

जिल खाना III सी-3-1059/8

18 .

चपला खाना, III सी-30

>>

19 .

19 .

1059/10

20 .

क्लब का मकान III सी-3

20 .

1059/11

इशरत महल

पीछे

21 .

21 .

देवड़ी बहादुर जंग हाउस

22 .

22 .

" "

Nos.C-3-27

देवी गौसुद्दीन खान। III

23 .

23 .

"

सी-3-23।

कुतुब खाना III सी-3-शून्य

24 .

24 .

25 .

चिन्नी खाना III सी-3

25 .

1040/1

उद्यान,

26 .

लिंगमपल्ली

मोहल्ला

26. & 27

लिंगमपल्ली

एक बड़ी इमारत

और कुछ छोटे क्वार्टर,

पुरानी सड़क पर

क्षेत्र के भीतर 53 एकड़

विश्वविद्यालय

परिसर की दीवार और 77 एकड़

एडिकमेट।

दीवार के बाहर। सर्वेक्षण

No.200;

गाँव

लिंगमपल्ली, तालुक गरबी,

जिला. शहर के भीतर हैदराबाद

नगरपालिका सीमा, संख्या ए-9

1138 .

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस.
ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

वहीद बाग अड्डा मकई,

28 .

27 .

मोहल्ला

दो छोटे भूखंड कटे हुए

चिक्कडपल्ली

छोटी पुरानी इमारतें और झोपड़ियां

किरायेदारों, क्षेत्र को किराए पर दिया गया

214 एकड़। सर्वेक्षण No.200।

गाँव

सरूरनगर उद्यान भवन

31 .

28 .

और परिसर के साथ उद्यान

सरूरनगर

दीवार क्षेत्र 3 एकड़

तालुक शार्की।

29 .

32 .

डोआरिया 2 एकड़

हुसैन शाह वली उद्यान

गाँव

30 .

33 .

खंडहर उद्यान में इमारत

हुसैन

यौगिक के साथ संलग्न

शाहवाली

तालुक गरबी

दीवार। सर्वेक्षण No.38 क्षेत्र 8

एकड़।

37 *

हाफ़िज़पेट पट्टा उतरता है,

हफ़ीजपेट

31 .

1333 एकड़ का सघन क्षेत्र।

तालुक गरबी

हैदरनगर पट्टा भूमि।

32 .

हैदरनगर

38

1210 एकड़ का सघन क्षेत्र।

तालुक गरबी

33 .

हफीजपुर

39

2684 एकड़।

हफीजपुर, सघन क्षेत्र

झांसी मियां गुडे पट्टा

नसिमियांगु

घ

40 *

34 .

भूमि, सघन क्षेत्र 743

दा।

एकड़।

दुकानें 21 नंबर, बाजार,

41

मोहल्ला

35 .

शामौल उमरा, म्यूनिसिपल

मसुलामरा

श

Nos.III C-3-1031 से 1033,

1036 1038,1047 से 1050 तक।

दुकानें 6 नंबर उमदा

36 .

42

मोहल्ला

बाजार आई. आई. एस.-549 से 554

उमदाबाजार

डूड के पास

बाउली

मो

हल्ला डूड

43

दुकानें 9 नंबर डूड

37 .

बाउली

बाउली III सी-2-से 8 1155 और
1156 .

दरवाजा

म

हल्ला शिबली

दुकानें 32 नंबर वाला बाजार

38 .

44

शिबली गंज, III सी-3-125 से

गंज

137 , 151 159,146 और

147 .

दुकानें 34 नंबर वाला बाजार

45

मोहल्ला

39 .

खुर्शीद

खुर्शीद गंज III सी-3-89 से

120 , 722 और 752।

गंज

शाह इनायत

40 .

46

घर 1

संख्या III सी

3-938

गंज।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41 .

47

संख्या III सी

खुर्शीद



3-841

गंज।

ए.

खुर्शीद

48

संख्या III सी

42 .

3-184

गंज।

शाह इनायत

49

संख्या III सी-3

" "

43 .

गंज।

लाल्लागुडा

ए के साथ हाउस 1 नंबर III

44 .

50

विशाल परिसर।

बुरहानपुर भूमि सर्वेक्षण

51

45 .

उमागिर

No.333 102 एकड़ (बाहर)

गाँव

हैदराबाद एस्टेट)

बुरहानपुर

जि

ला. मध्य प्रदेश

प्रदेश

ऑप. नावा।

(बाहर

पूना लैंड्स

52

46 .

	हैदराबाद राज्य)	
ना में क्लब		पू
	खंडाला हाउस (बाहर)	
53		
खंडाला		
47 .		
बे राज्य।		बॉम्
	हैदराबाद राज्य)	
IV-ए	मुक्रदमे की अनुसूची	
लकाराम टी. क्यू.		म
	मलकाराम पट्टा उतरता है।	
48 .		
	1	
शाहबाद		
	हसमतपेट पट्टा भूमि	
49 .		
	2	
हसमतपेट		
तालुक, गरबी		
	दिलवरगुडा	

50 .

3

तानपुर टी. क्यू.

सुल्

लाबार,
मेडक

का
जि.

विलेज।

साहेबगुडा

51 .

4

साहेबगुड

तालुक

ब्राहिमपटना

श

एम.

कादराबाद

कादराबाद

52 .

5

तालुक

ब्राहिमपतम

श

गद्दी अन्नाराम (मल्ला)

गद्दी

6

53 .

बंडम)

अन्नापुरम

तालुक शारकी

54 .

7

मकता मोहम्मद। बक्स खान।

लल्लागुडा, पट्टा लैंड्स।

लालगुडा टी. क्यू.

8

55 .

शरकी

न

चवरम

नचवरम

56 .

9

टीक्यू। शरकी

फिसलबंदा

बाग साहब जन उद्यान

10

57 .

एक यौगिक के साथ संलग्न

जफर नागा,

दीवार।

हैदराबाद मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्ची एंड
ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

गुलबाग उद्यान भूमि।

लगभग पुराना।

58 .

11

भीतर

नगरपालिका

सीमाएँ

दारीचा बोहरा का खुला कथानक

59 .

12

पास।

भूमि।

हुसैनीआलम

गुण

सूची 'ए' में उल्लिखित

एप्लन में। No.37/59.

सूची 'ए'

1

प्लॉट संख्या 1 लगभग 4272 वर्ग कि. मी. yds।

सीमाएँ:

60

किरायेदार एस, ई और डब्ल्यू: सड़कें।

प्लॉट संख्या 2 5206 वर्ग कि. मी. yds। सीमाएँ: उत्तर

61 .

2

जुल्फिकार अली खान एस द्वारा कब्जा किया गया घर:
एस्टेट हाउस और खाली जमीन ई. साजनलाल की

घर डब्ल्यू: सड़क।

62 .

प्लॉट संख्या 3,872 वर्ग कि. मी. yds। सीमाएँ:

एन:

3

इस संपत्ति की खाली भूमि: एस: सड़क, ई:

साजनलाल का घर और डब्ल्यू: एस्टेट हाउस।

प्लॉट संख्या 4,1250 वर्ग कि. मी. yds। सीमाएँ

एन

4

63 .

इस संपदा की खाली भूमि, एस: ऐसा ही है: ई-एस्टेट

जुल्फिकार खान और डब्ल्यू: सड़क।

64 .

5

प्लॉट संख्या 5,578 वर्ग कि. मी. yds। सीमाएँ:

एन:

इस एस्टेट की खाली भूमि, एस: इसी तरह: रोड, डब्ल्यू:

फखरुद्दीन खान द्वारा कब्जा किया गया एस्टेट हाउस,

किरायेदार।

प्लॉट संख्या 6,1556 वर्ग कि. मी. yds। सीमाएँ

एन

65 .

6

फखरुद्दीन, किरायेदार द्वारा: एस: -करो-। द्वारा

अधिकृत

कुलसुंबी ईस्ट: सड़क और पश्चिम: एस्टेट हाउस

अब्दुल अली किरायेदार द्वारा कब्जा कर लिया।

प्लॉट संख्या 7,1522 वर्ग कि. मी. yds। : सीमाएँ: एन:

7

66

इस एस्टेट का सड़क, टाइल वाला घर: ई: सीमेंट

रोड, डब्ल्यू. रोड।

67 .

8

प्लॉट संख्या 8,734 वर्ग कि. मी. yds. बाउंड्रीज़: की गई।

एन:

टाइल

इस संपत्ति का घर, एस: साजनलाल का घर: ई:

सीमेंट रोड और डब्ल्यू: द्वारा कब्जा किया गया घर

जुल्फिकार अली, किरायेदार।

सूची 'ए'-2:

दुकान No.III C-184 नामित। खुर्शीद गंज

68 .

32

स्थापित करता है

सी-722 नामित

69 .

III

33

ना [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2 " "

III सी-723 नामित अड्डा

70 .

34

झटका

दो मंजिला घर

71 .

35

No.III C-752

सूची 'ए'-3:

1

मुख्यालय हाउस III सी-121

शिवलीगंज

72 .

बाजार

73 .

2

बैंड रूम III सी-122

शिवलीगंज

नवाशीष महल IIIC-123/4

74 .

3

बाजार

कमरा नं. III सी-150

75 .

17

27

76 .

III सी-149

77 .

III सी-843

" "

28

III सी-842

78 .

29

32

79 .

" " III सी-999

लगभग 4250 वर्ग कि. मी. गिरी हुई भूमि। yds।

सीमाएँ:

80 .

33

एन: एच. क्यू. घर और सड़क: एस: नवाजीश महल

ई: इस संपत्ति का कमरा: डब्ल्यू: (फटे हुए)।

सूची ए-3 निरंतर।

No.road,

गिरी हुई भूमि 400 वर्ग किलोमीटर। yds। सीमाएँ:

34 .

81 .

एस: खाना बाग, ई: रास्ता: डब्ल्यू: फॉललैंड।

" 220 स्क्वायर। yds। सीमाएँ: संपत्ति का घर

82 .

35 .

नाम रसोई, एस: सड़क, ई: रसोई का द्वार:

डब्ल्यू: इस संपत्ति के कमरे।

सूची 'ए'-4।

शमसुल

83 .

3

गिरने वाला कमरा संख्या 103।

उमरा

बंगला नं. 2

84 .

5

मुल्ती No.1041

7

85 .

बंगला No.1051

2

86 .

12

मुल्ली No.1052

87 .

13

88 .

14 .

" 1053

खाली भूमि सामने: जिल खाना गेट, 150 वर्ग

किलोमीटर।

89 .

15 .

yds। सीमाएँ: एन: मस्जिद और सड़क, एस:

किशनलाल हाउस, ई: सीमेंट रोड और डब्ल्यू:

किशनलाल का घर।

16 .

सदर महाबीबी नामक कटोरा हाउस

90 .

जागीर प्रशासक का कब्जा

3 गिरी हुई दुकानों की जमीन।

91 .

17 .

92 .

No.12/1

लालागुडा में जमीन के साथ गिरा हुआ घर,

18 .

514 , लल्लागुडा में खुशीद बाग "।

47. प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.06.1963 के बाद, कुछ

मुकदमे के पक्षकारों ने मुकदमे में अपने अविभाजित शेयरों को अनुसूचित मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

(i) निजाम और (ii) नवाब कासिम नवाज जंग नाम के एक अन्य व्यक्ति के पक्ष में संपत्तियाँ। इन दोनों व्यक्तियों को फंसाया गया था

प्रतिवादी सं। 156 और क्रमशः 157। इस स्तर पर यह याद किया जा सकता है कि जब मूल रूप से मुकदमा दायर किया गया था, तब केवल 43 थे।

अभियुक्त। जिस समय मुकदमे में दलीलें दी गई थीं, उस समय प्रतिवादियों की संख्या बढ़कर 119 हो गई थी और जब प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था, तो प्रतिवादियों की संख्या 135 हो गई थी। डिक्री के बाद यह और बढ़ गया और निजाम और नवाब खासिम नवाज जंग को प्रतिवादी Nos.156 और 157 के रूप में शामिल किया गया, जब उन्होंने डिक्री-धारकों से 80 प्रतिशत की सीमा तक अविभाजित शेयर खरीदे।

48. प्रारंभिक डिक्री के तीन वर्षों के बाद, अधिवक्ता आयुक्त-सह-प्राप्तकर्ता ने 1966 के आवेदन संख्या 268 में हैदरनगर गांव में सर्वेक्षण संख्या 172 में भूमि सहित भूमि पर कब्जा करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो शिकायत अनुसूची IV की मद No.38 का हिस्सा था। प्रत्यर्थियों द्वारा कोई प्रतिवाद दायर नहीं किया गया था। हालाँकि शिकायत अनुसूची और प्रारंभिक आदेश में हैदरनगर में विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या (ओं) का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन प्राप्तकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि उसने राजस्व अभिलेखों/पहाड़ियों/खसरा पट्टानियों का अध्ययन किया और पाया कि सर्वेक्षण संख्या 145 (220.10 एकड़), सर्वेक्षण संख्या 163 (175.06 एकड़), और सर्वेक्षण संख्या 172 (196.20 एकड़), सभी हैदरनगर में स्थित थे।

और बाद के मद No.38 अनुसूची IV का हिस्सा थे।

49. इस बीच, एच. ई. एच. निजाम (प्रतिवादी संख्या 156) ने एक पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 23.02.1967 के माध्यम से अपना अविभाजित आधा हिस्सा बेच दिया।

एफ. ई. दिनशॉ लिमिटेड का पक्ष लिया, जो बाद में मेसर्स बन गया। साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्रा. Ltd.² इस स्थानांतरण को मान्यता दी गई थी, और इसके परिणामस्वरूप, साइरस को 1958 के मुकदमे CS No.14 में प्रतिवादी संख्या 206 के रूप में शामिल किया गया था।

50. उच्च न्यायालय ने 1966 के आवेदन संख्या 268 में पारित दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से जिला कलेक्टर, हैदराबाद (जिनके पास राज्य की ओर से संपत्तियों का कब्जा था) को निर्देश दिया।

सरकार) दो आधारों पर प्राप्तकर्ता को संपत्तियों का कब्जा सौंपना अर्थात्: (i) कि राज्य सरकार प्रारंभिक डिक्री में एक पक्ष थी; और (ii) कि विचाराधीन संपत्ति को "मातृका" संपत्ति घोषित किया गया था।

51. इसके बाद, प्राप्तकर्ता ने 1958 के सीएस नंबर 14 में 1970 के आवेदन संख्या 73 के माध्यम से विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की। अनुसूची के अनुसार चल और शहरी अचल संपत्तियाँ। उच्च न्यायालय ने

2 संक्षेप में, "साइरस" [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29.01.1971 दिनांकित आदेश के माध्यम से योजना को स्वीकार कर लिया गया, और प्राप्तकर्ता को सूट अनुसूची कृषि भूमि के संबंध में एक योजना प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

52. आयुक्त-सह-प्राप्तकर्ता ने तब 1958 के सी. एस. संख्या 14 में 1971 के आवेदन संख्या 139 में एक जिज्ञासु आवेदन दायर किया जिसमें आदेश की मांग की गई कि क्या उन्हें केवल दावों (लेकिन वास्तविक भौतिक भूमि नहीं) के संबंध में विभाजन की योजना तैयार करनी चाहिए। यह इस आधार पर था कि सरकार के साथ-साथ तीसरे पक्ष-संरक्षित किरायेदारों के पास सूट अनुसूची कृषि भूमि का वास्तविक कब्जा था। एक व्याख्यात्मक टिप्पणी आवेदन के साथ यह कहते हुए संलग्न किया गया था कि कलेक्टर, जिन्हें हैदरनगर की भूमि का कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया था, आपत्ति उठा रहे थे कि यह सरकारी भूमि है।

53. 1971 के आवेदन No.139 में दिनांकित 16.09.1972 passed आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्राप्तकर्ता को केवल भूमि के मूल्य के संदर्भ में दावों को विभाजित करने की अनुमति दी क्योंकि भूमि शेयरधारकों के कब्जे में नहीं थी।

54. तदनुसार, प्राप्तकर्ता ने 03.12.1972 पर विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें केवल सर्वेक्षण संख्या के संबंध में दावों को वितरित किया गया।

सर्वेक्षण संख्या सहित। 145 , 163 और हैदरनगर के 172।

55. इसके बाद प्राप्तकर्ता ने 1958 के सी. एस. संख्या 14 में 1973 का आवेदन संख्या 19 दायर किया, जिसमें केवल आंध्र प्रदेश राज्य को एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया और कलेक्टर से सर्वेक्षण का कब्जा सौंपने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई।

नं. 145 , 163 और हैदरनगर गाँव के 172। कोई भी पक्ष जो

जिन्हें बेदखल किए जाने की संभावना थी, उन्हें इस आवेदन का पक्ष बनाया गया था।

56. उच्च न्यायालय ने 1973 के आवेदन संख्या 19 को अनुमति दी, दिनांक 05.07.1974 के आदेश के माध्यम से सरकार को प्रतीकात्मक देने का निर्देश दिया।

सर्वेक्षण सं. 18 में 220 गुंटा एकड़ भूमि का कब्जा। 145 और प्राप्तकर्ता को सर्वेक्षण No.163 में एकर 175 गुंटा 6 को मापना। जहाँ तक अन्य भूमि का संबंध है, उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया कि सरकार प्रतीकात्मक वितरण देने की स्थिति में भी नहीं है और

इसलिए प्राप्तकर्ता को सर्वेक्षण संख्या में भूमि सहित भूमि के वास्तविक अधिभोगियों से कब्जा लेने के लिए कानून में उपलब्ध कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। 172 , हैदरनगर गाँव।

57. चूंकि पक्ष भूमि के हिस्से के आवंटन पर सहमत होने में असमर्थ थे, इसलिए उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 31.01.1976, में पारित किया गया।

1971 के आवेदन संख्या 139 ने इस मामले को जिला कलेक्टर मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड को भेज दिया।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सी. पी. सी. की धारा 54 के तहत हिस्सेदारों को विभाजन और आवंटन के लिए। जिला कलेक्टर ने राजस्व मंडल अधिकारी 3, चेवेल्ला को अनुसूचित भूमि का विभाजन करने का निर्देश दिया। आर. डी. ओ., चेवेल्ला ने विभाजित किया और आवंटित किया

58. जहां तक सर्वेक्षण No.172 में भूमि का संबंध है, यह पाया गया कि 1978-79 के लिए फैसल पट्टी मंडल द्वारा जारी किया गया था। राजस्व अधिकारी, बालंगर, रंगा रेड्डी जिला ने पैगाह के कार्यकाल के दौरान किए गए सर्वेक्षण संख्या 172 में 25 उप-प्रभागों का उल्लेख किया है। उक्त फैसल पट्टी में 24 व्यक्तियों (बोद्दु वीरास्वामी, रुकिया बेगम, वारिस अली और गनी शरीफ सहित) के नाम भी उल्लिखित हैं, जिन्हें कथित तौर पर 1948 से पहले निजाम/उनके राजस्व सचिवालय द्वारा पट्टा दिया गया था।

59. इसलिए प्राप्तकर्ता ने एक रिपोर्ट दायर की, जिस पर न्यायालय ने 1971 के आवेदन संख्या 139 में दिनांक 12.06.1981 का आदेश पारित किया। न्यायालय ने नोट किया कि प्राप्तकर्ता की रिपोर्ट विभाजन के संबंध में थी

हाफिज़पेट के सर्वेक्षण सं. 80 और हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 को छोड़कर अन्य सभी सर्वेक्षण संख्याएँ। अदालत ने रिपोर्ट की प्रति प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

60. प्राप्तकर्ता द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पता चलने पर,

हैदरनगर का हफीजपेट गाँव, जिसका माप 48,477.5 सेंट (लगभग 484 एकड़) और सर्वेक्षण No.172, जिसका माप 19,650 सेंट (लगभग 196.5 एकड़) है, प्रतिवादी संख्या। 157 और 206 और प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त को कब्जे के वारंट को निष्पादित करने का निर्देश देने के लिए 3 संक्षेप में, "आरडीओ"

सिटी सिविल कोर्ट के माध्यम से और प्रतिवादियों को क्रमशः हफीजपेट के सर्वेक्षण संख्या 80 और हैदरनगर के सर्वेक्षण संख्या 172 के कब्जे में रखा। आवेदन के एकमात्र उत्तरदाता, अर्थात् प्राप्तकर्ता ने "कोई आपत्ति नहीं" की सूचना दी। सर्वेक्षण संख्या 172 में पट्टों के माध्यम से भूमि के कब्जे वाले व्यक्तियों में से कोई भी नहीं था।

प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त हफीजपेट के सर्वेक्षण No.80 और हैदरनगर के सर्वेक्षण संख्या 172 में भूमि का कब्जा खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी संख्या 206) को सिटी सिविल कोर्ट के माध्यम से कब्जे के वारंट को निष्पादित करके और खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस को सौंपने के लिए (प्रतिवादी संख्या 206) कब्जे में। पक्षकारों द्वारा यह कहा गया है कि यद्यपि उच्च न्यायालय ने प्राप्तकर्ता को कब्जे का वारंट जारी किया है, वही

[illegible]

रिसीवर ने इस आधार पर कि उसने इस आशय के एक विशिष्ट पूर्व आदेश दिनांक 27.10.1984 के बावजूद वितरण के लिए एक योजना प्रस्तुत नहीं की थी और रिसीवर को 01.12.1984 द्वारा उच्च न्यायालय के उप-पंजीयक को रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश दिया।

63. उक्त आदेश के अनुसार, प्राप्तकर्ता ने अपने पद का प्रभार उच्च न्यायालय के उप-पंजीयक को सौंप दिया, जिससे यह समाप्त हो गया।

सर्वेक्षण सं. 172 में भूमि के संबंध में 1958 के सी. एस. No.14 में प्राप्तकर्ता की भूमिका। शुद्ध परिणाम यह है कि 20.01.1984 दिनांकित आदेश और वारंट प्राप्तकर्ता द्वारा लागू नहीं किया गया या निष्पादित नहीं किया गया था। 64. इसके बाद, साइरस (प्रतिवादी No.206) और नवाब खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) ने एक कार्यपत्र निष्पादित किया।

29.11.1995 मेसर्स गोल्डस्टोन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में। Ltd.4 सर्वे No.172, हैदरनगर में 98.10 एकड़ की सीमा तक। इस समनुदेशन के आधार पर, गोल्डस्टोन ने चार आवेदन दायर किए, अर्थात् (i) हैदरनगर गाँव में सर्वेक्षण संख्या 172 में एकड़ 98.10 गुंटा की सीमा तक भूमि के अधिकारों के समनुदेशन की मान्यता के लिए 1995 का आवेदन संख्या 992; (ii) मुकदमे में पक्षकारों के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए 1995 का आवेदन संख्या 993; (iii) संशोधन के लिए 1995 का आवेदन No.994

4 संक्षेप में, "गोल्डस्टोन" मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड & ओआरएस। ईटीसी. बी. एम. एस. मर्ची एंड ओआरएस. ईटीसी। [बी. रामसुब्रमणियन, जे.]

याचिकाकर्ताओं के नामों को प्रतिस्थापित करके और सर्वेक्षण No.172, हैदरनगर में एकड़ 196.20 गुंटा में से आधे हिस्से की भूमि के कब्जे के वितरण का निर्देश देकर 1983 के आवेदन संख्या 266 में 20.01.1984 पर पारित आदेश; और (iv) राजस्व अधिकारियों को संबंधित अभिलेखों में उनके नाम दर्ज करने के निर्देश के लिए 1995 का आवेदन संख्या 995। 65. उपरोक्त आवेदनों में, केवल असाइनर्स यानी, खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी No.206) थे।

दलों के रूप में शामिल। 1978-79 के फैसल पट्टी के अनुसार जिन तीसरे पक्षों के कब्जे में थे, उन्हें इन आवेदनों में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया था। 66. 1995 के इन आवेदनों, आई. ए. Nos.992,993,994 और 995 को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.12.1995 के आदेश द्वारा निर्विरोध अनुमति दी गई थी।

67. इसके बाद, गोल्डस्टोन और अन्य लोगों ने जिले के समक्ष आदेश XXI नियम 35 सी. पी. सी. के तहत 1996 के ई. पी. Nos.3 में एक निष्पादन याचिका दायर की।

न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला ने 1958 के सी. एस. No.14 में दिनांकित प्रारंभिक डिक्री 26.08.1963 के अनुसार शिकायत अनुसूची IV (हैदरनगर का सर्वेक्षण संख्या 172) की मद संख्या 38 के वितरण की मांग की। समनुदेशकों का नाम है -

खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी नं.

206) उक्त निष्पादन याचिका में अकेले उत्तरदाता-निर्णय-देनदार के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। वास्तविक भौतिक कब्जे में तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया गया था। 68. जिला न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला ने 1996 के ई. पी. संख्या 3 में उस न्यायालय के बेलिफ को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया

उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त समनुदेशन के अनुसार और 1995 के आवेदन संख्या 994 में पारित दिनांकित आदेश के अनुसरण में 1996 के ई. पी. संख्या 3 में याचिकाकर्ताओं को सर्वेक्षण संख्या 172 में 98.10 एकड़ की सीमा की भूमि प्रदान करना। अदालत के बेलिफ ने तब 19.04.1996 दिनांकित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि फैसले का कोई विरोध नहीं था-देनदार और उन्होंने भूमि का कब्जा गोल्डस्टोन को सौंप दिया था।

69. उसी के बारे में पता चलने पर, कई व्यक्ति जिनके पास सर्वेक्षण संख्या में भूमि के कुछ हिस्सों का कब्जा था। 172 , हैदरनगर ने विभिन्न राहों के लिए अलग-अलग आवेदन दायर किए। उन्हें आसान प्रशंसा के लिए निम्नानुसार सारणीबद्ध किया जा सकता है:

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आवेदन में प्रार्थना के तहत कानून का प्रावधान

द्वारा दाखिल किया गया आवेदन

जिसने दाखिल किया

संख्या

आदेश 21, नियम 97 से

निर्णय लेना और उनके दावे

की अनुमति देना।

585 2002 का

34 लोग

101 आर/डब्ल्यू धारा 151,

5. 28 ग्राम एकड़ की

सीमा तक

सर्वेक्षण No.172/10

सीपीसी

निर्णय लेना और उनके दावे

की अनुमति देना।

708 2002 का

धारा 151, सी. पी. सी

2 लोग

722 वर्ग कि. मी. तक।

याड्स

5. 28 ग्राम में एकड़ का हिस्सा बनाना

सर्वेक्षण No.172/10

धारा 47 आर/डब्ल्यू आदेश

और निर्देश देना

उनके दावे पर निर्णय लेना

1318 2003 का

34 लोग

अधिकार का पुनः वितरण।

21 , नियम 58 सीपीसी

1319 2003 का

105 व्यक्तियों का आदेश 21, नियम 99 आर/डब्ल्यू की प्रतीकात्मक पुनर्प्राप्ति का निर्देश देने के लिए

अधिकार

धारा 151

1320 2003 का

14 लोग

आदेश 21, नियम 97 आर/डब्ल्यू दिनांकित वारंट को वापस लेने के लिए
धारा 151 सी. पी. सी.

29.03.1996 1996

के ई. पी. सं. 3 में

70. जिला न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला ने भी इनकार कर दिया

उपरोक्त आवेदनों को इस आधार पर स्वीकार करें कि यह 1995 के आवेदन संख्या 994 में जारी उच्च न्यायालय के अधिदेश से आगे नहीं जा सकता है।

71. जिला न्यायालय द्वारा विचार करने से भी इनकार करने से व्यथित

श्री सत्य साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड नामक एक सोसायटी ने उनके आवेदनों के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष 1996 के सी. आर. पी. संख्या 4921 में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। सेट-विन एम्प्लॉइज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की एक अन्य सोसायटी के कुछ सदस्यों और श्री सत्य साई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के 33 सदस्यों ने याचिका दायर की।

❖

ओ. एस. ए. सं. 10 , 11 और 1996 का 20 उच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाते हुए

उच्च न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध 1996 का ओ. एस. ए. No.19
1958 के C.S.No.14 में 1995 का एक अन्य आवेदन संख्या 963

1996 के एक अन्य ई. पी. सं. 4 से संबंधित।

72. उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने उन मूल लोगों को अनुमति दी
दिनांकित 06.11.1996 आदेश द्वारा पक्ष की अपीलें और:

❖

जिला न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला को निर्देश दिया। मनोरंजन के लिए

और दावा याचिकाओं का गुण-दोष के आधार पर निपटारा करना;

भूमि के कब्जे को बहाल करने का निर्देश दिया
याचिकाकर्ताओं का दावा करना और पारित करने से पहले उनकी आपत्तियों को सुनना

ई. पी. (ओं) में कोई भी आदेश।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

73. इसी तरह का आदेश 1996 के सी. आर. पी. No.4921 में जिला न्यायालय, रंगा रेड्डी जिले को पंजीकृत करने और निपटान करने का निर्देश देते हुए पारित किया गया था।

योग्यता के आधार पर याचिकाओं का दावा करें।

74. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, गोल्डस्टोन एक्सपोर्ट्स और अन्य ने दाखिल किया,

एस. एल. पी (ग) 1997 का Nos.8787-8789 ओ. एस. ए. Nos.11 में उच्च न्यायालय के दिनांकित 06.11.1996 और ओ. एस. ए. Nos.11 के 20 के आदेश को चुनौती देता है।

1996 ; और

एस. एल. पी (ग) 1996 की सं. 23706,1996 की ओ. एस. ए. सं. 10 के आदेशों के विरुद्ध (1995 की आवेदन सं. 994 और 1996 की ई. पी. सं. 3 से संबंधित)।

75. दिनांक 14.08.1997 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उन सभी SLP को अनुमति दी और 1996 के OSA Nos.10,11 और 20 को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। यह रिमांड का पहला आदेश था।

76. इस बीच, गोल्डस्टोन और 15 अन्य लोगों ने सी. एस. एन. में 1998 का आवेदन संख्या 517 दायर किया। 14 1958 में एक अंतिम डिक्री पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए, हैदरनगर गाँव के SurveyNo.172 में 98.10 एकड़ के संबंध में नवाब खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी संख्या 157) के एल. आर. को इस आधार पर आरोपित करना कि उन्हें जिला न्यायाधीश, रंगा रेड्डी जिले द्वारा 17.04.1996 पर संपत्ति का कब्जा सौंप दिया गया है।

1995 के आवेदन No.994 में उच्च न्यायालय का दिनांक 28.12.1995 का निर्देश। इस आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश dated 24.04.1998 द्वारा अनुमति दी गई थी और गोल्डस्टोन के पक्ष में एक अंतिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें सर्वेक्षण संख्या 172, हैदरनगर गाँव (मद No.38) में एकड़ 98.10 गुंटा मापने वाली संपत्ति के कब्जे को दर्ज किया गया था।

अनुसूची-IV) जिला न्यायाधीश, रंगा रेड्डी जिले के न्यायालय के बेलिफ द्वारा 1996 के ई. पी. संख्या 3 में 17.04.1996 पर उन्हें दी गई थी। विभाजन मुकदमे के इतिहास में शायद यह अपनी तरह का पहला आदेश होगा, जिसमें प्रारंभिक डिक्री के निष्पादन और संपत्ति का कब्जा लेने के बाद अंतिम डिक्री पारित की गई थी।

77. अंतिम डिक्री के पारित होने के कुछ महीनों के भीतर, इस न्यायालय से वापस भेजे गए मूल पक्ष की अपीलें को

उच्च न्यायालय की खंड पीठ और उन्हें 10.11.1998 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दावा याचिकाएं विचारणीय नहीं थीं और इसमें दावेदार इसके माध्यम से अधिकारों का दावा कर रहे थे।

1958 के सी. एस. सं. 14 में डिक्री के पक्षकार। वास्तव में, यह माना गया था कि बाधा डालने वालों के दावे कुछ निर्णयों के माध्यम से हैं-देनदार [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यह कि इसलिए आदेश XXI के नियम 97 या 99 के तहत आवेदन निर्णय-देनदारों, या उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण पर बनाए रखने योग्य नहीं हैं।

78. उच्च न्यायालय का दिनांकित 10.11.1998 का आदेश सिविल अपील Nos.7983 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बन गया।

2001 की सिविल अपील Nos.7984-85 और 2001 की 7986-88 के साथ। इन अपीलों को इस न्यायालय द्वारा एन. एस. नारायण सरमा बनाम मेसर्स गोल्डस्टोन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट में रिपोर्ट किए गए एक निर्णय द्वारा अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि दावा याचिकाएं बहुत अधिक विचारणीय थीं, क्योंकि दावा याचिकाकर्ता जागीर उन्मूलन विनियमों के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र रूप से अधिकारों का दावा कर रहे थे। इस तरह के निर्णय के बाद, इस न्यायालय ने दावे की याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय में भेज दिया। इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस न्यायालय के समक्ष (उस मामले में) अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिकाओं को विचार के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।

79. तदनुसार, 1995 के आवेदन No.994 सहित सभी आवेदन एल. नरसिम्हा रेड्डी, जे., (जैसा कि वे उस समय थे) के समक्ष रखे गए थे। विद्वान न्यायाधीश ने उन सभी आवेदनों में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले 11 मुद्दों और 2 अतिरिक्त मुद्दों को तैयार किया।

80. अंततः, विद्वान न्यायाधीश ने 26.10.2004 दिनांकित एक आदेश द्वारा सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया, जिसका कार्यात्मक भाग निकाला गया था।

इसके तहत, आत्म-व्याख्यात्मक है:

" 68. पूर्ववर्ती कारणों से;

(क) 1995 का आवेदन No.994 खारिज कर दिया जाता है।

(ख) 2002 का आवेदन Nos.585 और 708, और 1318 से 1320 तक

2003 की अनुमति है।

(ग) याचिकाकर्ताओं ने पूरे समय दलील दी कि भूमि में

सवाल खाली था। यह पहले ही पाया जा चुका है कि जिला न्यायाधीश, रंगा रेड्डी जिले के न्यायालय में ई. पी. दाखिल करना

और उसमें उठाए गए विभिन्न कदम कानून के विपरीत हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कब्जे की कथित डिलीवरी को प्रतीकात्मक माना जाता है।

(घ) उत्तरदाताओं को संबंधित बिक्री विलेख द्वारा कवर की गई भूमि का स्वामित्व और कब्जा रखते हुए पाया जाता है।

5 (2002) 1 एस. सी. सी. 662 मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस

मृत्यु और ओआरएस। ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

उनके हित में। जिस तरह से कब्जे की डिलीवरी थी

केवल प्रतीकात्मक रूप से, वह भी खाली भूमि के संबंध में, यह उनके लिए उक्त भूमि के कब्जे में रहने के लिए खुला रहेगा। याचिकाकर्ताओं के पास एक अधिकार नहीं है। भूमि के संबंध में स्वामित्व और व्याज। जो E.P.No.3 की विषय वस्तु थी

(ई) यदि याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्यर्थियों के अधिकार में रहने के अधिकार के बारे में कोई विरोध है जिला न्यायालय , रंगा रेड्डी प्रत्यर्थियों को ऐसी भूमि के कब्जे के पुनः वितरण का निर्देश देगा, यदि कोई आवेदन है।

इस उद्देश्य के लिए दायर किया गया है।
(च) याचिकाकर्ताओं के लिए अधिकारों के आवंटन के संबंध में ऐसे कदम उठाने के लिए खुला रहेगा जो उनके लिए कानूनी रूप से खुले हैं।

उनकी कृपा "।

81. विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 26.10.2004 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, फरमानों के समनुदेशकों ने ओ. एस. ए. में अपीलों का एक समूह दायर किया नं. 52 2004 का 59 तक। 23.06.2006 पर एक सामान्य आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलों को यह मानते हुए अनुमति दी कि दावा याचिकाकर्ता अपने स्वतंत्र अधिकार, स्वामित्व और हित को स्थापित करने में विफल रहे, जो किसी भी प्रकृति का अधिकार नहीं है।

82. दिनांकित 23.06.2006 आदेश के खिलाफ, दावा याचिकाकर्ताओं ने सी. ए. संख्या में अपील दायर की। 3327-3331 इस न्यायालय के समक्ष 2014 का। जब इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए अपीलें आईं, इस पर ध्यान दिया गया

अदालत ने कहा कि डिवीजन बेंच (न्यायमूर्ति B.Seshasayana रेड्डी) के न्यायाधीशों में से एक, जिसने उसमें विवादित आदेश पारित किया था, ने पहले एक आदेश पारित किया था, जबकि वह दावा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में रंगा रेड्डी जिले के जिला न्यायाधीश थे। इसलिए, विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वकीलों ने इस न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि ओ. एस. ए. में डिवीजन बेंच के दिनांक 1 के सामान्य फैसले को दरकिनार कर दिया जाए और मामले को एक बार फिर से वापस भेज दिया जाए। तदनुसार, इस न्यायालय ने दिनांक 2 के आदेश द्वारा अपीलों को स्वीकार कर लिया और दिनांक 1 के उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया और ओ. एस. ए. को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया।

83. रिमांड के आदेश के बाद, मूल पक्ष की अपीलों को कई के साथ उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अनुप्रयोग। 14.03.2018 पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने [2023] 8 एस. सी. आर. से उत्पन्न होने वाली सभी लंबित अपीलें और आवेदनों को केवल वर्गीकृत करते हुए एक आदेश पारित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1958 के सी. एस. No.14 में से 14 प्रकारों में और पार्टियों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करना

सुनवाई की अगली तारीख से उन सभी अपीलों और आवेदनों में बहस के लिए तैयार।

84. हालांकि यह एक डिफ़िटल आदेश नहीं था, लेकिन यह हाउस कीपिंग के लिए था ताकि सभी अपीलों और आवेदनों की सुनवाई एक संरचित तरीके से आगे बढ़ सके, उक्त आदेश को नवाब खासिम नवाज जंगंद गोल्डस्टोन/ट्रिनिटी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा एस. एल. पी. में इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी। 2018 की (सिविल) डायरी संख्या 40990। उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ इन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित शिकायत यह थी कि सुनवाई के लिए अपीलों और आवेदनों को वर्गीकृत करके, उच्च न्यायालय द्वारा पहले से निपटाई गई अपीलों को भी फिर से खोलने की संभावना थी।

85. इस विशेष अनुमति याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को नोटिस का आदेश दिए बिना, प्रवेश के चरण में ही 16.11.2018 पर किया गया था। आदेश इस प्रकार है:

" देरी को माफ कर दिया गया।

विद्वान वकील श्री गोपाल शंकरनारायण प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उन दूसरी अपीलों को भी फिर से खोलने की संभावना है।

जिनका पहले ही निपटारा कर दिया गया था।

आशंका निम्नलिखित अवलोकन पर आधारित है।

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में किया गया:

" श्रेणी-XIII और XIV के तहत आने वाली सभी रिट याचिकाओं पर 10 अप्रैल 2018 से एक दिन-आज के आधार पर सुनवाई की जाएगी, इस विशिष्ट समझ के आधार पर कि विद्वान सरकारी वकील 10 अप्रैल 2018 से रिट याचिकाओं पर बहस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सुविधा के उद्देश्य से, कारण सूची के रूप में मुद्रित की जाएगी

बिना किसी संशोधन के, क्योंकि आज सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्तों द्वारा दायर ज्ञापन का लाभ मिला है और यह है उन मामलों के संबंध में तैयार रहने के लिए जो

ये इन श्रेणियों में आते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि निष्पादन केवल उन रिट याचिकाओं से संबंधित होगा जो अन्यथा इसके कारण बच गई हैं -

रिमांड।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है

ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

86. उपरोक्त निपटान से संतुष्ट नहीं, उपरोक्त विशेष अवकाश

एक बार फिर 28.11.2018 पर सुनवाई के लिए लाया गया था

स्पष्टीकरण के लिए कहा। इस तरह के उल्लेख पर, इस न्यायालय ने एक पारित किया

28.11.2018 पर निम्नलिखित प्रभाव:

" 16.11.2018 दिनांकित आदेश का परिचालन भाग है

निम्नलिखित सीमा तक संशोधित (अंतर्निहित के साथ)

संशोधन}

" यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्णय केवल इन से संबंधित होगा -

वे रिट याचिकाएँ और अपीलें (ओ. एस. ए. एस.) जिनके पास अन्यथा है

रिमांड के कारण बच गया,

} }

शेष आदेश वैसा ही रहेगा।

87. इसके बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सभी मामलों को संभाला।

प्रारंभिक पक्ष अपील करता है और एक सामान्य निर्णय द्वारा उसका निपटारा करता है।

20.12.2019 . प्रभाग के आदेश का कार्यात्मक भाग

एच इस प्रकार पढ़ता है:

" 414. परिणामतः

(क) ओएसए एन. ओ. एस. 54 , 56 , 57 , 58 2004 को खारिज कर दिया गया है और विद्वान एकल न्यायाधीश का सामान्य आदेश dt.26.10। 2004 में

दावा याचिकाएं 2002 का आवेदन No.585, आवेदन

2002 का No.708, 2003 का आवेदन No.1319 और आवेदन

नं. 1320 2003 का Or.21 नियम 97-101 सी. पी. सी. के तहत दायर किया गया 1996 के ई. पी. 3 की पुष्टि की गई है;

(ख) यह घोषित किया जाता है कि दावे में याचिकाकर्ता/प्रतिवादी

O.S.A.s ने अपने अधिकार, शीर्षक और रुचि को स्थापित किया है

दावा याचिकाओं/आवेदन में उनके द्वारा दावा की गई संपत्तियाँ

2002 का No.585, 2002 का आवेदन No.708, आवेदन
आवेदन संख्या। 1320 2003 से।

2003 का No.1319 और

(घ) हम घोषणा करते हैं कि हैदरनगर गाँव की भूमि जागीर थी।
खेती करने के लिए पट्टा दिए जाते थे

भूमि, लेकिन 1948 से पहले,

रुकिया बेगम की तरह खुर्शीद जाह पैगाह के तहत रैयत,

वारिस अली, गनी शरीफ, बोड्डु वीरास्वामी और अन्य

एच. ई. एच. [2023] 8 एस. सी. आर. के राजस्व सचिवालय द्वारा माने गए पट्टेदार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1947 में निजाम। इसलिए इस भूमि का अधिकार 1948 से पहले ही उक्त खेती करने वाले रैयतों को दिया गया था और उन्होंने वैध रूप से दावा याचिकाकर्ताओं को अधिकार दिया था। इसलिए हैदराबाद जागीर उन्मूलन विनियमन, 1358 फसली के लागू होने के बाद यह भूमि राज्य सरकार के पास नहीं थी।

(ड) यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2004 के ओ. एस. ए. No.59 की इस न्यायालय में कोई प्रतिप्रेषण नहीं है, आदेश में कहा गया है कि 23.6.2006 उक्त में ओ. एस. ए. को कोरम गैर-न्यायिक द्वारा पारित और अमान्य घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप हम मानते हैं कि यह 2002 के आवेदन No.585,2002 के आवेदन No.708,2003 के आवेदन No.1319 और 2003 के आवेदन संख्या 1320 में दावा याचिकाकर्ताओं सहित किसी भी निकाय पर बाध्यकारी नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि पूरा आदेश अमान्य है, जिसमें इसमें किए गए सभी निष्कर्ष/टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें यह निष्कर्ष भी शामिल है कि दावा याचिकाकर्ताओं ने अपनी भूमि पर अपना अधिकार साबित नहीं किया है।

व्यवसाय;

(च) हम घोषणा करते हैं कि प्रारंभिक डिक्री डी. टी. 28.6.1963 1958 के सी. एस. No.14 में हैदरनगर गाँव में भूमि के संबंध में न्यायालय के साथ-साथ दावा याचिकाकर्ताओं और उक्त गाँव में भूमि के अन्य अधिभोगियों दोनों पर धोखाधड़ी का अभ्यास करके प्राप्त किया जाता है और इसे शुरू से ही शून्य घोषित किया जाता है।

(छ) हम घोषणा करते हैं कि आदेश डी. टी. 20.1.1984 आवेदन में No.266/1983 और आदेश में dt.28.12। 1995 आवेदन सं। 994 /

1995 इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा प्राप्त किए गए हैं

उसमें आवेदक न्यायालय और दावा याचिकाकर्ताओं दोनों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और प्रकृति में मिलीजुली भी होते हैं। नतीजतन उन्हें दावा याचिकाकर्ताओं और तीसरे पक्ष के खिलाफ फांसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ज) हम घोषणा करते हैं कि आदेश डीटी। 24.4.1998 एप्लन में अंतिम आदेश पारित करना। 1958 के सीएस No.14 में 1998 का No.517 अमान्य है और यह आगे घोषित किया जाता है कि अनुसूची IV की मद 38 के हैदरनगर गांव, रंगा रेड्डी जिले के Sy.No.172 में Ac.98-10 जीटीएस के संबंध में कोई अंतिम आदेश नहीं है।

(i) हम घोषणा करते हैं कि जिला न्यायाधीश, रंगा का आदेश

रेड्डी dt.29.03। 1996 1958 के C.S.No.14 में 1996 के E.P.No.3 के साथ-साथ बेलिफ रिपोर्ट dt.19.04 में। 1996 वारंट dt.29.03 को निष्पादित करना। 1996 गैर-मौजूद हैं और शून्य और ट्रिनिटी इन्फ्रैवेंचर लिमिटेड हैं।

& ओआरएस। ई. टी. मृत्यु और ओ. आर. एस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमण्य

शून्य, और अपीलार्थी इससे वंचित हैं किसी भी कार्यवाही में उन पर फिर से निर्भरता
याचिकाकर्ता या किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ।

(जे) हम अपीलकर्ताओं को तुरंत बहाली का निर्देश देते हैं।

2002 के आवेदन No.585 में याचिकाकर्ता, आवेदन करें

2002 का आवेदन No.1319 2003 का और ऐप

1320 दावा पी. ई. द्वारा दावा की गई 2003 की भूमि

Sy.No.172 हैदरनगर गाँव का (जो लिया गया था)

बेलीफ रिपोर्ट डी. टी. के अनुसार। 19.4.1996 ई. पी में

उक्त भूमि पर उनका अधिकार और आनंद (के) निम्नलिखित प्रेरित अनुप्रयोग डिस्म हैं

1. I.A.No। 2004 के ओएसए No.54 में 2014 का 1

2. 2004 के ओएसए No.54 में 2014 का I.A.No.2

3. 2004 के ओएसए No.54 में 2019 का I.A.No.2

2004 का ओएसए No.54

4. 2019 का I.A.No.3

5. 2014 का I.A.No.1

2004 का ओएसए No.56

6. 2004 के ओएसए No.56 में 2014 का I.A.No.2

7. 2004 के ओएसए No.56 में 2019 का I.A.No.2

8. 2004 के ओएसए No.56 में 2019 का I.A.No.3
2014 का I.A.No.2

9 2004 के ओएसए No.57 में

10. 2004 के ओएसए No.57 में 2019 का I.A.No.3
No.57 में 2019 का I.A.No.5

11. 2004 के ओएसए

12. 2004 के ओएसए No.58 में 2014 का I.A.No.2
No.58 में 2019 का A.No.2

13. 1. 2004 के ओएसए

14. 2004 के ओएसए No.59 में 2014 का I.A.No.2

15. 2004 के ओएसए No.59 में 2014 का I.A.No.3

16. 2004 के ओएसए No.59 में 2014 का I.A.No.4

18. 2004 के ओएसए No.59 में 2017 का LA.No.2
No.59 में 2018 का I.A.No.1

19. 2004 के ओएसए

20. 2004 [2023] 8 एस. सी. आर. के ओ. एस. ए. No.59 में 2018 का <आई. डी. 1.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. 1. 2004 के ओएसए No.59 में 2019 का A.No.5
24. 2004 के ओएसए No.59 में 2019 का I.A.No.4

(के) अपीलार्थी 2004 के ओ. एस. ए. एस. 54,56-58/दावे में प्रत्येक उत्तरदाता को <आई. डी. 1,000/- की लागत का भुगतान करेंगे।

2002 के आवेदन No.585 में याचिकाकर्ता/आवेदक,

2002 का आवेदन No.708,2003 का आवेदन-No.1319

और 2003 का आवेदन सं. 1320 "।

88. उपरोक्त निष्कर्ष पर आने से पहले, खंड पीठ ने कुछ निष्कर्ष दर्ज किए। पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि उसमें अपीलार्थी

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1983 के आवेदन No.266 और 1995 के आवेदन No.994 में प्राप्त आदेश भी धोखाधड़ी से दूषित हैं और इसलिए दावा याचिकाकर्ताओं और तीसरे पक्ष के खिलाफ निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं। यहां तक कि हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में एकड़ 98.10 गुंटा के संबंध में 1998 के आवेदन No.517 में 24.04.1998 पर पारित अंतिम डिक्री को भी डिवीजन बेंच द्वारा अमान्य माना गया था।

89. जहाँ तक ओ. एस. ए. Nos.54 और 2004 की धारा 56 से 58 में विभिन्न पक्षों द्वारा किए गए अभियोगों का संबंध है, उन्हें खंड पीठ द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि तीसरे पक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

किसी और द्वारा दायर दावा याचिका में शामिल किया गया है और यह कि संपत्ति के अधिकार का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक अलग दावा याचिका दायर करनी चाहिए थी। जहाँ तक 2004 के ओ. एस. ए. No.59 में भ्रामक आवेदनों का संबंध है, डिवीजन बेंच ने महसूस किया कि 2004 के ओ. एस. ए. No.59 की कोई रिमांड नहीं थी और इसलिए, एक अपील में धोखाधड़ी के लिए आवेदन। उच्चतम न्यायालय द्वारा रिमांड की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

90. तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 20.12.2019 के सामान्य आदेश को चुनौती देते हुए, कई पक्षों ने हाथ में अपीलें रखी हैं। विवादित फैसले के खिलाफ जो पक्ष सामने आए हैं, उनमें वे शामिल हैं, (i) जो हैं

फरमानों के समनुदेशकों और जो चाहते थे कि डिक्री को निष्पादित किया जाए और उन्हें कब्जा सौंप दिया जाए; (ii) जिनके मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रैक्चर लिमिटेड के लिए आवेदन।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

ओ. एस. ए. Nos.54 और 2004 के 56 से 58 में अभियोग खारिज कर दिए गए हैं; (iii) 2004 के ओ. एस. ए. No.59 में अभियोग लगाने के लिए जिनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं; (iv) जो हैदरनगर में भूमि के अन्य आधे हिस्से के बारे में चिंतित हैं (शिकायत अनुसूची IV की वस्तु <आई. डी. 1), लेकिन जिन्हें प्रारंभिक डिक्री को अमान्य ठहराए जाने के कारण संपार्श्विक नुकसान हुआ है; (v) मुकदमे में प्रतिवादी No.58, जो पक्षकार नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष, लेकिन जो दावा करता है कि हैदरनगर गाँव के सर्वेक्षण में भूमि का विस्तार, जिसके लिए वह हकदार बन गई थी, अब प्रारंभिक डिक्री को अमान्य ठहराए जाने से प्रभावित है; और (vi) तेलंगाना राज्य।

91. इसे सरल शब्दों में रखने के लिए, (i) ऐसे व्यक्ति जिनकी अंतर-न्यायालय अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी; (ii) ऐसे व्यक्ति जिनके लिए आवेदन किए गए थे -

उच्च न्यायालय द्वारा अभियोग खारिज कर दिया गया था; (iii) ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, लेकिन जिनके सर्वेक्षण के दूसरे भाग, या संपत्तियों की अन्य वस्तुओं के संबंध में अधिकार, विवादित निर्णय से प्रभावित माने जाते हैं; और (iv) राज्य सरकार, अपीलों के साथ आई है। गैर-पक्ष विशेष अवकाश याचिका दायर करने की अनुमति के लिए आवेदन लेकर आए हैं और उन आवेदनों को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है।

92. अपीलों के अलावा, अभियोग के लिए कुछ आवेदन भी थे, जिन्हें अलग से संबोधित करना पड़ सकता है। इसलिए, स्पष्टता के उद्देश्य से, हम इस निर्णय को नौ भागों में विभाजित करेंगे, जैसा कि नीचे विस्तृत है:

भाग-I में कुछ विशिष्ट शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ होगा।

भाग-II में इस बारे में विवरण होगा कि कौन किसके खिलाफ खड़ा है

इस लड़ाई को।

भाग-III में इस बात का विवरण होगा कि कैसे (i) अपीलार्थी; (ii)

दावा याचिकाकर्ता; और (iii) राज्य सरकार अधिकार का दावा कर रही है एक ही संपत्ति।

भाग-IV-अपीलों के इस समूह में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले मुद्दों (राज्य द्वारा दायर अपीलों सहित) पर विचार करेगा।

तेलंगाना)।

भाग-V उन लोगों के दावों पर विचार करेगा जिनके अभियोग आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए थे लेकिन जिनके मामले हैं

दावा याचिकाकर्ताओं के समान।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग-VI-विवादित लोगों के लिए गैर-पक्षकारों की अपीलों पर विचार करेगा।

विवादित निर्णय के एक भाग को चुनौती देने वाला निर्णय।

भाग-VII-मोहम्मद द्वारा दायर 2022 की आई. ए. संख्या 118143 से संबंधित होगा।

मुस्तफुद्दीन खान और अन्य (प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी) 2022 की एसएलपी (सिविल) संख्या 8884 से उत्पन्न अपील में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं।

भाग-VIII-2022 के आई. ए. No.112090 से संबंधित होगा।

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी।

भाग-IX-I.A.No से संबंधित होगा। दुर्गा द्वारा 2023 का 36422 दाखिल किया गया

माथा को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड।

कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों को डिकोडिंग करना

93. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डिकोड करना आवश्यक हो सकता है

शुरू से ही इन कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्द और अभिव्यक्तियाँ। यदि ऐसा नहीं होता है, तो वे पाठकों को परेशान और भयभीत करते रहेंगे। इसलिए, एक शब्दावली निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:

(1)

मृत मुसलमान द्वारा छोड़ी गई चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति को मातृका कहा जाता है।

मातृक:

((ख)

यह एक फारसी (या फारसी) शब्द है जिसका उपयोग धूमधाम और पद को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस शब्द का अनुवाद "सही" के अर्थ में भी किया गया है।

पैगाह:

हैंड मैन "या" फुटस्टूल "।

(iii)

पैगाह अनुदान:

यह सेना के रखरखाव के लिए दी गई संपत्ति है।

आमिर:

(iv)

पैगाह के धारक को "अमीर" कहा जाता है।

(v)

1. शाब्दिक रूप से, लेने की जगह। भूमि के एक हिस्से की उपज के सरकारी हिस्से में से एक व्यक्ति को सौंपा गया कार्य। जागीरों की दो प्रजातियाँ थीं; एक, व्यक्तिगत, अनुदान प्राप्तकर्ता के उपयोग के लिए; दूसरा, कुछ सार्वजनिक सेवा के लिए विश्वास में, आमतौर पर सैनिकों के रखरखाव के लिए।

जागीर:

[व्हार्टी] 2. पूर्ववर्ती राज्य के शासक द्वारा अपने परिवार के कनिष्ठ सदस्यों को वार्षिक भत्ता देने का आदेश 'जागीर' नहीं है। 3. अपने लोकप्रिय अर्थों और विधायी व्यवहार दोनों में, जागीर शब्द का उपयोग राज्य अनुदान के रूप में किया जाता है जो अनुदान प्राप्तकर्ताओं को भूमि के संबंध में अधिकार प्रदान करता है। राजस्व 3 899 "।

6 (2001) 8 एस. सी. सी. 599 का शीर्षक था "जमील अहमद और अन्य बनाम पांचवां अतिरिक्त। जिला। न्यायाधीश, मुरादाबाद और अन्य " 7 (1987) 1 एस. सी. सी. 52 का शीर्षक "हिम्मतसिंहजी बनाम। राजस्थान राज्य "। 8 ए. आई. आर 1955 एस. सी. 504,520,521: (1955) 2 एस. सी. आर. 303 शीर्षक "ठाकुर अमर सिंहजी बनाम।

राजस्थान राज्य मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

लेकिन "जागीर" शब्द को आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) (जागीरों का उन्मूलन) विनियम, 1358 फसली के विनियम 2 (एफ) में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक पैगाह, जागीर का संस्थान भाग, गाँव मुखता, गाँव अग्रहार, उमली और मुकासा शामिल हैं, चाहे वे किसी शासक या जागीरदार द्वारा दिए गए हों, और धारा 5 के तहत जागीर के लिए निर्धारित तिथि से शुरू होने वाली अवधि के संबंध में, इसका अर्थ है वहाँ की संपत्ति।

जागीर का गठन करना;

इस अभिव्यक्ति को उपरोक्त के विनियम 2 (एच) में परिभाषित किया गया है।

(vi)

जागीरदार:

विनियमन का अर्थ है वह व्यक्ति जो धारा 5 के तहत निर्धारित तिथि से तुरंत पहले एक जागीर का धारक (कबीज़) था और जिसमें एक पैगाह का अमीर और एक पैगाह का बली शामिल है।

समस्थान।

(vii) मकता/मखता: | सुमित मलिक द्वारा लिखित द लॉ लेक्सिकन विद मैक्सिमस

(ईस्टर्न बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण, 2016)

इंगित करता है कि यह शब्द हिंदुस्तानी, तेलुगु, मराठी और गुजराती में उपलब्ध है। इस शब्द का अर्थ है "एक अनुबंध, काम के लिए एक समझौता, किराया, दर, एक निश्चित दर या किराया"।

कौन किससे लड़ रहा है?

94. मिल के नियमित संचालन के विपरीत जो पहले सामने आते हैं

इस न्यायालय में जहां आमतौर पर विवादों के दो पक्ष होते हैं, वहां विवाद के कई पक्ष होते हैं। एक ओर हमारे पास विभाजन के मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री के आधार पर संपत्ति पर अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी ओर, हमारे पास लोग हैं

(जो निष्पादन न्यायालय के समक्ष दावा याचिकाकर्ता थे) जिन्होंने जागीर के उन्मूलन के बाद अपने पूर्ववर्तियों को दिए गए पट्टों के आधार पर स्वतंत्र अधिकार का दावा किया। हमारे पास तेलंगाना राज्य भी है।

संपूर्ण रूप से संपत्ति का दावा इस आधार पर कि संपत्ति बहुत पहले उनमें निहित थी। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग विभाजन मुकदमे में प्रारंभिक और अंतिम फरमानों के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हैं, वे शुरू में संपत्ति के एक हिस्से पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थे, जो उन लोगों के कब्जे में है जो निष्पादन न्यायालय के समक्ष अवरोधक/दावा याचिकाकर्ताओं के रूप में हैं। लेकिन दावा याचिकाकर्ताओं ने एक सख्त रुख अपनाया है, जो करने या मरने की इच्छा प्रदर्शित करता है। लेकिन जहां तक राज्य सरकार के

दावे का संबंध है, डिक्री धारकों के साथ-साथ दावा याचिकाकर्ता दोनों अपने विरोध में एकजुट हैं। मुख्य प्रतियोगियों के इन तीन समूहों के अलावा, अन्य भी हैं जिनमें (i) वे लोग जो दीवानी मुकदमे में डिक्री द्वारा कवर की गई अन्य संपत्तियों के संबंध में अपने हित को नुकसान पहुंचाने के लिए विवादित निर्णय की संभावना से डरते हैं; और (ii) एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जिसे ऋण के साथ एक संपत्ति का बंधक सौंपा गया है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

95. आसान प्रशंसा के उद्देश्य से, हम इसका उल्लेख करेंगे

पक्षकारों के रूप में (i) डिक्री धारकों और फरमानों के समनुदेशकों; (ii) याचिकाकर्ताओं का दावा करते हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे; (iii) याचिकाकर्ताओं का दावा करते हैं जिनके अभियोग आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए थे; (iv) तीसरे पक्षकार; और (v) राज्य सरकार।

भाग-III:

विवाद के विभिन्न पक्ष स्वामित्व का दावा कैसे करते हैं?

96. विवादित निर्णय को चुनौती देने वाले व्यक्ति तीन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् (i) फरमानों के समनुदेशक; (ii) याचिकाकर्ताओं का दावा करते हैं जिनके अभियोग आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए हैं; और (iii) राज्य सरकार।

फरमानों के समनुदेशकों के दावे का आधार

97. मुकदमे के पक्षकार, डिक्री धारक और फरमानों के समनुदेशकर्ता (साइरस/गोल्ड स्टोन/ट्रिनिटी) हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में लगभग 98 एकड़ की भूमि पर मुख्य रूप से अधिकार का दावा करते हैं।

आधार:

कि यह खुर्शीद जाह की मथरुका संपत्ति थी;

(i)

कि दिलदार-उन-निसा बेगम ने इस संपत्ति के विभाजन की मांग की थी

((ख)

अन्य संपत्तियों के साथ इस आधार पर कि यह था

वंशानुगत;

(iii)

कि निर्णय और प्रारंभिक डिक्री में पारित किया गया

28.06.1963 अदालत ने फैसला सुनाया था कि संपत्ति थी

एक मातृका संपत्ति;

((iv)

पुष्टि की।

कि यहां तक कि नज़ीम अतियत के समक्ष की कार्यवाही और
इसके बाद जारी किए गए मुंतखाब ने खुर्शीद जाह के नाम पर पूरे हैदरनगर गांव की

(v)

कि इनाम अलतमघा वंशानुगत और हस्तांतरणीय है;
कि प्रारंभिक डिक्री के अनुसार, प्राप्तकर्ता-सह

(vi)

न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त ने 1966 के आई. ए. No.268 में एक आवेदन
दायर करके भूमि का कब्जा सौंपने के लिए न्यायालय से कलेक्टर को निर्देश देने की मांग की।

(vii)

कि 23.02.1967 पर, HEH निजाम (प्रतिवादी No.156) ने बेच दिया
साइरस (प्रतिवादी No.206) के लिए उसके निर्णयात्मक अधिकार

एक पंजीकृत बिक्री विलेख; ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. बी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [बी. रामसुब्रमणियन, जे.]viii) कि 1966 के 24.03.1967 आवेदन No.268 पर अनुमति दी गई थी

उच्च न्यायालय द्वारा कलेक्टर को देने का निर्देश

प्राप्तकर्ता को अधिकार;

ix)

कि 05.11.1970 पर उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया संपत्ति के विभाजन के लिए खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी No.206) द्वारा दायर आवेदन

आपस में आधे में यह धारण करते हुए कि शेयरों के आवंटन के तुरंत बाद, डी-157 और 206 अपनी पसंद का प्रयोग कर सकते हैं और आयोग को इसमें कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

ध्यान दें;

कि 15.03.1972 पर, प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त ने दाखिल किया

x)

विशेष रूप से मद No.38-हैदरनगर के संबंध में न्यायालय के समक्ष एक ज्ञापन जिसमें कहा गया है कि उन्होंने तहसील कार्यालय और पहाड़ी देशभक्तों में उपलब्ध अभिलेखों का सत्यापन किया है और पाया है कि सर्वेक्षण संख्या में भूमि के संबंध में पट्टा नवाब हिमायत नवाज जंग (अमीर-ए-पैगाह) के नाम से दिखाया गया है। 145 , 163 और हैदरनगर गाँव का 172 एकड़ की कुल सीमा तक और वह सर्वेक्षण 196 एकड़, 20 गुंटा पाया गया है।

xi)

कि 03.12.1972 पर, प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त

कृषि भूमि के विभाजन की योजना तैयार की हैदरनगर और एक व्यक्ति सहित सूची I में उल्लिखित

हाफ़िज़पेट और हैदरनगर के विभाजन की (कथन 1) और सर्वेक्षण-वार (कथन 1 ए) योजना तैयार की गई थी।

xii)

कि 28.03.1973 पर, विशेष उप-कलेक्टर, हैदराबाद

यह कहते हुए एक काउंटर दायर किया कि सर्वेक्षण No.172 चराई भूमि थी

और खेती योग्य भूमि नहीं;

xiii) कि 05.07.1974 पर, न्यायालय ने 1973 के आवेदन संख्या 19 को अनुमति दी और सरकार को सर्वेक्षण संख्या में स्थित भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। 145 और हैदरनगर गाँव के 163 एकड़ को मापने वाले को क्रमशः 220 गुंटा 18 और एकड़ 175 गुंटा 6;xiv) कि जहाँ तक अन्य भूमि का संबंध है, न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में दर्ज किया कि सरकार प्रतीकात्मक अधिकार सौंपने की स्थिति में भी नहीं थी और इसलिए यह प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त के लिए है।

कानून में उपलब्ध ऐसे कदम उठाने के लिए; [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xv) कि न्यायालय ने दिनांक 31.01.1976 के आदेश के माध्यम से मामले को कलेक्टर को विभाजन और धारा 54 सी. पी. सी. के तहत शेयरों के आवंटन के लिए भेजा, लेकिन कलेक्टर ने कभी भी एक आदेश प्रस्तुत नहीं किया।

सर्वेक्षण No.172 के संबंध में रिपोर्ट;

(xvi) कि 09.04.1980 पर, प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त ने कलेक्टर को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि इसके बावजूद

अदालत के दिनांक 31.01.1976 के आदेश के अनुसार, कलेक्टर ने हैदरनगर में भूमि को विभाजित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन दूसरी ओर तालुक कार्यालय ने इन नामों पर पट्टा दिए थे -
कई व्यक्तियों ने रिसीवर को वसीम-ए-जमाबंदी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने और रद्द करने की मांग करने के लिए मजबूर किया

पट्टों का;

(xvii) कि 05.08.1983 पर, नवाब खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी) द्वारा दायर आवेदन

No.206) वादी संख्या के नामों को हटाने के लिए। 1 और 2 और अन्य प्रतिवादी और उन्हें उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करें (कारण उनके निर्णयात्मक अधिकारों की बिक्री की अनुमति दी गई थी);

(xviii) कि 1983 में, प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया था कि विभाजन की योजना के अनुसार, नवाब खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस

(प्रतिवादी No.206) पूरे सर्वेक्षण No.172 हैदरनगर का कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं क्योंकि यह उन व्यक्तियों को आवंटित किया गया था जिन्होंने उन्हें अपने निर्णायक अधिकार बेच दिए हैं और सर्वेक्षण No.172 को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है और कब्जा नवाब कासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी No.206) को दिया जा सकता है;

(xix) कि नवाब कासिम नवाज जंग (प्रतिवादी संख्या 157) और साइरस (प्रतिवादी No.206) द्वारा कब्जा मांगने के लिए दायर 1983 के आवेदन No.266 पर अनुमति दी गई थी और प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था और कब्जे के लिए वारंट भी जारी किया गया था;

कि प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में दिनांकित किया

(XX)

13.07.1984 , इस बात का उल्लेख किया कि सर्वेक्षण 196.20 एकड़ का पूरा हिस्सा नवाब खासिम नवाज जंग को आवंटित किया गया है

(प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी No.206) उन सभी पक्षों द्वारा निर्णयात्मक अधिकारों की बिक्री के अनुसार जिन्हें विभाजन की योजना में सर्वेक्षण No.172 में भूमि आवंटित की गई थी; ट्रिनिटी इन्फ्रैवेंचर लिमिटेड।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.](xxi) कि 1991 में, नवाब खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) और साइरस (प्रतिवादी No.206) ने पूरे मामले को संभाला।

196.20 सर्वेक्षण No.172 में एकड़, वे अपने-अपने अधिकार सौंपने के लिए एक आंतरिक व्यवस्था पर आए और साइरस के हिस्से के लिए, 16 याचिकाकर्ताओं को 10 भूखंड आवंटित किए जाने थे;

(xxii) कि 29.11.1995 पर, साइरस (प्रतिवादी No.206) ने गोल्डस्टोन और अन्य के पक्ष में असाइनमेंट डीड्स को निष्पादित किया।

हैदरनगर और नवाब के सर्वेक्षण No.172 में उनका आधा हिस्सा

खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) को फांसी दी गई

नजीर बेग और अन्य के पक्ष में असाइनमेंट डीड;

और

(xxiii) कि याचिकाकर्ता इस प्रकार पर पूर्ण अधिकार रखने के लिए आए

सर्वेक्षण No.172 में 98.10 एकड़ मापने वाली भूमि।

दावा याचिकाकर्ताओं के दावे का आधार

98. दावा याचिकाकर्ताओं का मामला था:

कि उनके पूर्ववर्ती मूल कृषक थे

((i)

हैदरनगर गाँव के सर्वेक्षण No.172 में भूमि;

कि वे भूमि के विस्तार के लिए पट्टादार बन गए

((ख)

कानून के संचालन द्वारा उनकी खेती, अर्थात् पट्टादारी अधिकारों के अनुदान से संबंधित नियमों के नियम 2 और 3

खालसा गाँव;

(iii) कि उसके बाद उसे एक जमीना सेठवार भी जारी किया गया था।

1947 में सर्वेक्षण No.172 को सर्वेक्षण संख्या में उप-विभाजित करके टोंक मानचित्र और पोट संख्याओं के साथ प्रभाव। 172/1 172 /

25 ;

((iv) कि मूल सेठवार कलेक्टर द्वारा प्राप्त किया गया था।

राज्य अभिलेखागार से और तहसीलदार (पश्चिम), हैदराबाद को भेजा गया ताकि इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके, जैसा कि फैसल पट्टी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(v)

कि सर्वेक्षण No.172 में भूमि के हिस्से थे सहकारी आवास समितियों द्वारा आवासीय भूखंडों की एक कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया और दावा याचिकाकर्ताओं ने सहकारी आवास समितियों से व्यक्तिगत आवास भूखंड खरीदे; और [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(vi) कि दावा याचिकाकर्ता इस प्रकार के मालिक बन गए

व्यक्तिगत भूखंड।

तेलंगाना राज्य के दावे का आधार

99. राज्य का दावा है:

कि खुर्शीद जाह ने उस समय कोई मथरुका संपत्ति नहीं छोड़ी थी

(i)

1902 में उनकी मृत्यु;

कि उस समय उनके पास केवल पैगाह/जागीर की संपत्ति थी;

(ख)

(iii)

कि ऐसी जागीर संपत्ति राज्य में निहित है

जागीर उन्मूलन विनियम, 1949;

(iv) कि इन तथ्यों की पुष्टि हैदराबाद के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश-मिर्जा यार जंग के माध्यम से पैगाह समिति द्वारा की गई थी।

1929 में;

(v)

कि पैगाह समिति द्वारा निर्धारण है

निर्णायक और पक्षों पर बाध्यकारी;

(vi) कि पैगाह समिति के निष्कर्षों की पुष्टि निज़ाम के शाही विशेषाधिकार द्वारा की गई थी, जैसा कि निज़ाम से देखा गया है।

फरमान;

((vii) राजा रामचंद्र रेड्डी बनाम रानी शंकरम्मा और सिकंदर जहां में इस न्यायालय की दो संविधान पीठों की राय के अनुसार, यह तय कानून है कि सभी जागीर भूमि राज्य में निहित हैं और वे अविभाज्य और गैर-वंशानुगत हैं।

बेगम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) बनाम ए. पी. में इस न्यायालय के दो अन्य निर्णय। राज्य वक्फ बोर्ड "और मोहम्मद। हब्बीबुद्दीन खान बनाम जागीर प्रशासक, आंध्र प्रदेश सरकार

(viii) कि राज्य को प्रतिवादी No.53 के रूप में मुकदमे में पक्षकार बनाया गया था, केवल तभी जब प्रतिवादी संख्या 1 ने एक लिखित बयान दायर किया था जिसमें संकेत दिया गया था कि शिकायत अनुसूची IV की वस्तु Nos.37 से 40 तक ली गई थी।

राज्य द्वारा;

1956 एससी 319

1962 एससी 996

2 एससीसी ऑनलाइन एससी 159

4) 1 एस. सी. सी. 82 का ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

((ix) जैसा कि इस न्यायालय ने रंगम्मल बनाम रंगमल में अभिनिर्धारित किया है।

कुप्पुस्वामी 1 3, विभाजन के लिए एक मुकदमा शीर्षक की घोषणा या निर्धारण के लिए मुकदमा नहीं है;

कि दर्ज किए गए निष्कर्ष जैसे कि गुण हैं

(x)

मातृका संपत्तियाँ, उन प्रतिवादियों की मिलीभगत का परिणाम थीं जिन्होंने मूल रूप से मुकदमे का विरोध किया था लेकिन

जिन्होंने बाद में समझौता किया;

(xi) कि जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया था, प्रारंभिक डिफ्री स्वयं धोखाधड़ी से दूषित थी और इसलिए

उसमें दर्ज किसी भी निष्कर्ष पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(xii) कि अतियत न्यायालय के समक्ष कार्यवाही भी थी

शीर्षक की घोषणा के संबंध में नहीं बल्कि केवल के लिए

मुआवजे में शेयरों का विभाजन;

भाग-IV: विचार के लिए उठ रहे मुद्दे

100. विद्वत एकल और इसमें आक्षेपित खंड पीठ के निर्णय पर सावधानीपूर्वक विचार करने और प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पता चलेगा कि निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैं: -

क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ सही थी

((i)

यह घोषणा करते हुए कि 28.06.1963 दिनांकित प्रारंभिक डिफ्री धोखाधड़ी से दूषित हो गई थी और परिणामस्वरूप अमान्य हो गई थी, विशेष रूप से जब कोई अभिवचन नहीं था और कोई सबूत नहीं था

अंदर आने दो?

क्या एकल न्यायाधीश के समवर्ती निष्कर्ष और

((ख)

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि खुर्शीद जाह ने कोई मातृका संपत्ति नहीं छोड़ी, निर्णय और प्रारंभिक डिक्री में दर्ज निष्कर्ष के विपरीत है जो अंतिमता प्राप्त कर चुका है?

12 एससीसी 220 [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ग) क्या निर्णय में अभिलिखित निष्कर्ष और

प्रारंभिक आदेश कि हैदरनगर की भूमि मातृका की संपत्ति है, तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी है?

(iv) आदेश XXI नियमों के तहत जांच का दायरा क्या है?

97-101 , सीपीसी?

क्या दावा याचिकाकर्ताओं के दावे कायम रहे

(v)

स्थापित? और

(€ vi) क्या तेलंगाना राज्य का कोई वैध दावा है।

और क्या न्यायालय कक्ष में राज्य सरकार को कई बार झटका लगने के बाद भी ऐसा कोई दावा कायम रहेगा?

मुद्दा सं. (i) और (iv):

(i) क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ यह घोषणा करने में सही थी कि 28.06.1963 दिनांकित प्रारंभिक डिक्री थी

धोखाधड़ी से दूषित और परिणामस्वरूप शून्य और शून्य, विशेष रूप से जब कोई अभिवचन नहीं था और कोई सबूत नहीं दिया गया था? और

((iv) आदेश XXI के तहत जांच का दायरा क्या है?

नियम 97-101, सी. पी. सी.?

101. जैसा कि श्री गोपाल शंकरनारायणन द्वारा उचित रूप से तर्क दिया गया है, आदेशों के समनुदेशकों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील, किसी ने भी अनुरोध नहीं किया कि

प्रारंभिक आदेश धोखाधड़ी से दूषित हो गया था। धोखाधड़ी के आरोपों के लिए, जैसा कि सही कहा गया है, आदेश VI, नियम 4 सी. पी. सी. के संदर्भ में विशेष दलीलों की आवश्यकता होती है।

102. वास्तव में, खंड पीठ का विवादित निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांकित निर्णय को चुनौती देने से उत्पन्न हुआ था।

26.10.2004 . अपने निर्णय के पैराग्राफ 19 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को तैयार किया। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का पैराग्राफ 19 इस प्रकार है:

" 19. पक्षों की दलीलों के आधार पर, निम्नलिखित
सभी मुद्दों और अतिरिक्त मुद्दों को तैयार किया गया है
अनुप्रयोग:

क्या हैदरनगर की S.No.172 द्वारा आच्छादित भूमि

1)

गाँव स्वर्गीय नवाब खुर्शीद झा पैगाह की मातृका संपत्ति है?

क्या निज़ाम प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है

2)

निज़ाम द्वारा S TRINITY INFRAVENTURES LTD के उन्मूलन से पहले
फरमान के माध्यम से।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

भूमि को किसी के पक्ष में हस्तांतरित करने से इनाम
लोग?

क्या विचाराधीन भूमि इनाम (जागीर) भूमि है

3)

और उन्मूलन के बाद सरकार में निहित हो

इनाम (जागीर) का?

4)

क्या पट्टा बोड्डू वीरा के पक्ष में दिया गया था

1947 में स्वामी और अन्य?

क्या कथित पट्टों को निष्पादित किया गया था

5)

बोड्डू वीरास्वामी और अन्य लोगों के पक्ष में वास्तविक हैं

दस्तावेज़ हैं या नहीं?

क्या दावेदार कब्जे में रहे हैं और

6)

बोड्डू के समय से संपत्ति का आनंद

वीरास्वामी (पट्टों का अनुदान)?

7)

क्या दावा सीमा द्वारा वर्जित है?

8)

क्या 1958 के सी. एस. No.14 में निर्णय और डिक्री

क्या याचिकाकर्ताओं/दावेदारों पर बाध्यकारी है?

9)

क्या दावेदारों के पास कोई अधिकार, स्वामित्व और ब्याज है
विचाराधीन संपत्ति पर?

10)

क्या दावा याचिका सीमा को देखते हुए वर्जित है

उच्चतम न्यायालय के रिमांड आदेश का?

11) किस राहत के लिए?

अतिरिक्त मुद्दे:

1)

क्या 17.4.1996 पर कब्जे की कथित डिलीवरी

वैध अवैध नहीं है और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि अंतिम डिक्री को उचित स्टाम्प
पेपर पर नहीं रखा गया है।

और संपत्ति को सीमा और सीमा से विभाजित नहीं किया गया है?

2)

क्या दावेदारों ने अन्यथा उनकी रक्षा की है
प्रतिकूल अधिकार द्वारा शीर्षक?

एप्पलन में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। 1995 का No.994। हालांकि,

ऊपर उल्लिखित मुद्दों में विवाद शामिल होगा आवेदन भी "।

103. जैसा कि उपरोक्त मुद्दों से देखा जा सकता है, धोखाधड़ी न तो बनाए गए मुकदमों में से एक थी और न
ही विद्वान [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धोखाधड़ी के बारे में एकल न्यायाधीश। लेकिन खंड पीठ ने इस तरह के निष्कर्ष को विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में पढ़ा।

104. इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने आदेश XXI नियम 97 से 101 सी. पी. सी. के तहत जांच के दायरे पर विचार करते हुए,

यह प्रश्न (पैराग्राफ 149 से आगे) कि क्या धोखाधड़ी का मुद्दा, यदि दावा याचिका में उठाया जाता है, तो निष्पादन न्यायालय द्वारा देखा जा सकता है। राष्ट्रीय वस्त्र में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के बाद

निगम (महाराष्ट्र दक्षिण) लिमिटेड बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 14 और बॉम्बे और कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा कि धोखाधड़ी का मुद्दा, यदि दावा याचिका में उठाया जाता है, तो निष्पादन न्यायालय द्वारा देखा जा सकता है। ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, उच्च न्यायालय सबसे पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बेलिफ की दिनांकित 19.04.1996 की रिपोर्ट, जैसे कि भूमि का कब्जा ले लिया गया था, धोखाधड़ी थी। पैराग्राफ 203 में ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 208 में राय दी कि यदि धोखाधड़ी अदालत के रिकॉर्ड से ही सामने आती है, तो एक अलग और विशिष्ट अभिवचन की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, उच्च न्यायालय ने लक्ष्मण दास बनाम जगत राम और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले से प्रेरणा ली, जिसमें इस न्यायालय ने कहा कि जहां पक्षकारों के बीच मिलीभगत रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, विशिष्ट अभिवचन का अभाव महत्वहीन था। उच्च न्यायालय तब उस विशिष्ट सीमाओं को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ा और

संपत्तियों के सर्वेक्षण संख्या को शिकायत अनुसूची में इंगित नहीं किया गया था

लेकिन प्राप्तकर्ता ने उत्सुकता से उन संपत्तियों की पहचान की और कहा कि जब सर्वेक्षण No.172, हैदरनगर में भूमि 1948 से पहले की अवधि से लंबे समय तक तीसरे पक्ष/पट्टादारों के कब्जे में थी, तो वादी द्वारा उनकी पीठ के पीछे एक डिक्री प्राप्त करने का प्रयास धोखाधड़ी था और यह कि

इसलिए हैदरनगर गाँव में भूमि के संबंध में प्रारंभिक आदेश शुरू से ही अमान्य था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि आवेदन संख्या में तथ्यों का दमन किया गया था। 994 1995 का और 1983 का 266

और यह कि इस तरह का दमन धोखाधड़ी की याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था।

105. लेकिन उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष के साथ कठिनाई यह है कि प्रारंभिक डिक्री के किसी भी पक्ष ने इसे चुनौती नहीं दी यह आधार कि यह धोखाधड़ी से दूषित हो गया था। यद्यपि आदेश XXI, नियम 97 से 101 सी. पी. सी. के संदर्भ में निष्पादन में बाधा डालने वाले और दावा करने वाले व्यक्ति भी धोखाधड़ी के आधार पर डिक्री पर हमला करने के हकदार हैं, ऐसे दावा याचिकाकर्ता इस बारे में अभिवचन करने के लिए बाध्य हैं कि रिकॉर्ड द्वारा धोखाधड़ी कैसे की जाती है।

15 (2007) 10 एस. सी. सी. 448 एम/एस ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

106. हमें याद रखना चाहिए कि कब्जा करने के लिए एक डिक्री के निष्पादन में बाधा डालने या विरोध करने वाले व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आ सकते हैं। एक अवरोधक वह हो सकता है जो वैध होने का दावा करता है

डिक्री के पक्षकारों में से एक द्वारा कब्जा। एक अवरोधक वह व्यक्ति भी हो सकता है जो अपने आप में स्वतंत्र उपाधि का दावा करता है।

107. वास्तव में, आदेश XXI नियम 97 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन डिक्री धारक (या डिक्री के निष्पादन में खरीदार) द्वारा दायर किया जाना है, जैसा कि वैधानिक प्रावधान से देखा जा सकता है। आदेश XXI नियम 97 इस प्रकार है:

" 97. अचल संपत्ति के कब्जे के लिए प्रतिरोध या बाधा

संपत्ति। (1) जहां अचल संपत्ति के कब्जे के लिए डिक्री के धारक या डिक्री के निष्पादन में बेची गई ऐसी किसी संपत्ति के खरीदार का किसी व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है या बाधा डाली जाती है।

संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए, वह एक आवेदन कर सकता है

न्यायालय को ऐसे प्रतिरोध या बाधा की शिकायत करने के लिए। (2) जहां उप-नियम (1) के तहत कोई आवेदन किया जाता है, वहां न्यायालय आवेदन पर उसके अनुसार निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

इसमें निहित प्रावधानों के साथ।

108. इसके विपरीत, आदेश XXI नियम 99 के तहत एक आवेदन अचल संपत्ति से बेदखल व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना है।

109. यद्यपि आदेश 21 के नियम 101 के आधार पर, नियम 97 या नियम 99 के तहत एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्नों का निर्धारण निष्पादन न्यायालय द्वारा किया जाएगा, न कि एक अलग अदालत द्वारा। मुकदमा, नियम 101 के तहत पारित कोई भी आदेश एक मुकदमे के परिणाम के अधीन है जहां अवरोधक एक अधिकार स्थापित करना चाहता है।

110. नियम 101 और 104 इस प्रकार हैं:

" 101. निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न। एक आवेदन पर कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न (संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित से संबंधित प्रश्नों सहित)

नियम 97 या नियम 99 या उनके प्रतिनिधि, और आवेदन के निर्णय के लिए प्रासंगिक, न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

आवेदन से निपटने के लिए, न कि एक अलग वाद द्वारा और इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय, उस समय लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, ऐसे प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र में समझा जाएगा।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

104. नियम 101 या नियम 103 के तहत आदेश लंबित मुकदमे के परिणाम के अधीन होगा। — नियम 101 या नियम 103 के तहत किया गया प्रत्येक आदेश किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगा जो आदेश के प्रारंभ की तारीख को लंबित हो सकता है। कार्यवाही जिसमें ऐसा आदेश दिया जाता है, यदि ऐसे मुकदमे में वह पक्ष जिसके खिलाफ नियम 101 या नियम 103 के तहत आदेश है

किए गए ने एक अधिकार स्थापित करने की मांग की है जिसका वह दावा करता है

संपत्ति का वर्तमान अधिकार "।

111. यह ध्यान रखना दिलचस्प हो सकता है कि जबकि नियम 101 निष्पादन न्यायालय को संबंधित प्रश्नों सहित सभी प्रश्नों पर निर्णय लेने की अनुमति देता है

संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित, नियम 103 एक काल्पनिक कल्पना पैदा करता है कि नियम 101 के तहत इस तरह से पारित आदेशों को एक डिक्री माना जाएगा।

112. नियम 101 और 103 के बावजूद, नियम 101 के तहत पारित आदेश, नियम 104 के तहत, किसी भी लंबित मुकदमे के परिणाम के अधीन किया जाता है।

113. हाथ में मामले में, बाधा डालने वाले मुकदमे के किसी भी पक्ष के तहत अधिकार का दावा नहीं करते हैं। उन्होंने अपने आप में स्वतंत्र खिताब स्थापित किया। दिलदार-उन-निसा बेगम द्वारा जो दायर किया गया था, वह केवल विभाजन का मुकदमा था। विभाजन के लिए एक मुकदमे में, सिविल कोर्ट स्वामित्व के प्रश्न में नहीं जा सकता है, जब तक कि यह दावे के मौलिक आधार के लिए आकस्मिक न हो।

114. उदाहरण के लिए हिंदू अविभाजित परिवार के एक सदस्य द्वारा विभाजन के लिए दायर किए गए मुकदमे को लें। यदि सह-भागीदारों में से एक या एक विदेशी

ऐसा सह-भागीदार, अपने व्यक्तिगत नाम से खरीदी गई संपत्तियों में से किसी एक पर स्वतंत्र स्वामित्व का दावा करता है, यह तय करने के लिए विभाजन के मुकदमे का प्रयास करते समय न्यायालय के लिए खुला हो सकता है कि क्या ऐसी संपत्ति विशेष रूप से प्रतिवादी की है। इस सीमित सीमा तक, एक पक्ष के शीर्षक की जांच करना

विभाजन के मुकदमे में भी अनुसूची संपत्ति की अनुमति है।

115. लेकिन विभाजन के लिए एक साधारण मुकदमे में, पक्ष अजनबियों के खिलाफ अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें प्रोफार्मा उत्तरदाताओं के रूप में भी आरोपित कर सकते हैं।

जिन अजनबियों को विभाजन मुकदमे में फंसाया जाता है, उनके पास विभाजन के दावे के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उनके पास संपत्ति के स्वामित्व का दावा हो सकता है और इस तरह के दावे का फैसला विभाजन मुकदमे में नहीं किया जा सकता है।

116. इस कठिनाई को महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि मुकदमा केवल विभाजन के लिए एक मुकदमा नहीं था, बल्कि यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा था कि संपत्तियां स्वर्गीय नवाब खुर्शीद जाह की मथरुका संपत्तियां हैं।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

उन्होंने इस संबंध में शिकायत के पैराग्राफ 18 (ए) में मांगी गई राहत की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

117. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम वादी के पैराग्राफ 18 (ए) में मांगी गई राहत को एक बार फिर इस प्रकार निकालेंगे:

" यह निर्देश देते हुए कि अनुसूची IV में विस्तृत संपत्तियां जो पक्षकार के कब्जे में हैं और पैरा (12) में विस्तृत अन्य (बी) श्रेणी की संपत्तियां जो ऊपर दी गई हैं।

प्रतिवादी No.43 के कब्जे में हैं और अन्य सभी संपत्तियां जो भी स्वर्गीय नवाब खुर्शीद जाह के मथरुका से संबंधित पाई जा सकती हैं, उन्हें मेट्स और बाउंड्री द्वारा विभाजित किया जाए और

वादी को उसमें उसका 29 वां हिस्सा दिया जाए।

118. चूंकि शिकायत के पैराग्राफ 18 (ए) में मांगी गई राहत शिकायत के पैराग्राफ 12 को संदर्भित करती है, इसलिए हमें पैराग्राफ पर एक नज़र डालनी पड़ सकती है।

मातृका संपत्तियों के दो वर्गों का वितरण और पैगाह की आय से खरीदी गई संपत्तियों की सूची, अनुसूची IV और आई. वी. ए. का अनुमानित मूल्य रु. 6,52,058-2-0 है। लेकिन वाद के पैराग्राफ 13 में, वाद अनुसूची संपत्तियों के अनुमानित कुल अस्थायी मूल्य का उल्लेख ओ. एस. रु. 7,52,058 20 के रूप में किया गया है। वादी के हिस्से का मूल्य, अर्थात् 29/2944 वां हिस्सा, अनुच्छेद 13 में ओ. एस. रु. 7,408-1-1 के रूप में आया है।

119. जिस तरह से मुकदमे के दावे का मूल्यांकन किया गया है और अदालत की फीस का भुगतान किया गया है, वह बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह घोषणा के लिए एक मुकदमा नहीं था। किसी भी संपत्ति का स्वामित्व। यह केवल विभाजन के लिए एक सूट था। सभी सूट अनुसूची

संपत्तियों का मूल्य एक विशेष दर पर किया गया है और उस हिस्से के मूल्य पर न्यायालय शुल्क का भुगतान किया गया था, जिसके विभाजन की वादी मांग कर रहा था। यदि यह एक मुकदमा था जिसमें अधिकार की घोषणा के लिए एक प्रार्थना थी, तो अदालत-शुल्क

संपत्ति के पूरे मूल्य पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था न कि उस हिस्से पर जिसे विभाजित करने की मांग की गई थी।

120. इसलिए, हमारा विचार है कि 28.06.1963 दिनांकित प्रारंभिक डिक्री द्वारा किए गए स्वामित्व के दावे का निर्धारण नहीं किया जा सकता था

विभाजन की मांग करने वाले कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा, तीसरे पक्ष के विपरीत। प्रारंभिक डिक्री में दिया गया कोई भी निष्कर्ष, कि संपत्तियां विभाजित होने के लिए उत्तरदायी मातृका संपत्तियां थीं, केवल कानूनी उत्तराधिकारियों के दावे के लिए आकस्मिक था और इस तरह का निष्कर्ष नहीं होगा

तीसरे पक्ष की तुलना में संपत्ति पर उनके अधिकार का निर्धारण।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

121. वास्तव में, हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि 50 मुद्दे हैं

मुकदमे में मुकदमे के लिए तैयार किया गया। लेकिन ये सभी 50 मुद्दे डी. जी. एम. टी. और प्रारंभिक डिफ्री में पाए गए जो तथ्य और कानून दोनों के केवल 10 व्यापक के आसपास घूमते हैं। वे 10 बिंदु इस प्रकार हैं:

" मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दे पर सवाल चारों ओर घूमते हैं

तथ्य और कानून दोनों के दस व्यापक बिंदुओं का पालन करना।

क्या नवाब खुर्शीद जाह ने कोई संपत्ति छोड़ी है

आई.

फरमान एक्स के पैरा 2 द्वारा कवर किया गया विवरण। पी 30 दिनांक 5 शाहाबाद, 1347 (17-1-1929 के अनुरूप) और या 3 खंड 9; और इसका विस्तार क्या है।

क्या उस संपत्ति को आपस में बांटा जा सकता है

II.

उनके उत्तराधिकार की पंक्ति में जीवित कानूनी उत्तराधिकारी? क्या इस तरह के विभाजन का दावा समय के भीतर है?

III.

IV.

विभिन्न उत्तराधिकारी कौन हैं?

उन उत्तराधिकारियों के संबंधित अधिकार क्या हैं, जिनमें शामिल हैं -

वी.

अमीर पैगाह के अधिकार जो कब्जे में रहे हैं

इन गुणों में से?

VI.

क्या प्रतिवादी संख्या 1 खातों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है और मेसन लाभ, जैसा कि दावा किया गया है?

VII. चाहे किसी प्रतिवादी ने नुकसान पहुँचाया हो या

मातृका संपत्ति को नुकसान, जैसा कि आरोप लगाया गया है

यदि ऐसा है तो पक्षकारों की सीमा क्या है?

VIII. चाहे उन्होंने या उनमें से किसी ने कोई अलगाव किया हो; किस हद तक, और हस्तांतरणकर्ताओं के मामले में इक्विटी कैसे

अभिलेख में समायोजन किया जाए?

चाहे मुकदमा पक्षकारों की गलती या कारणों के लिए बुरा हो

IX.

कार्रवाई।

X. क्या न्यायालय द्वारा भुगतान किया गया शुल्क सही है।

122. उपरोक्त 10 बिंदुओं में से कोई भी इस दावे से संबंधित नहीं है कि

(सरकार को छोड़कर) तृतीय पक्षों को संपत्तियों पर अधिकार देना।

123. इसलिए, जिस तरीके से निर्णय और

प्रारंभिक मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड के कुछ हिस्सों को खरीदकर 28.06.1963 दिनांकित नाइनरी डिक्री का उपयोग करने की मांग की गई थी, कार्यवाही के पक्षों के साथ-साथ गैर-पक्षों द्वारा दुरुपयोग किया गया था।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

आदेश और अदालत के माध्यम से उन्हें निष्पादित करने की मांग,

तृतीय पक्ष के अधिकारों ने ही उच्च न्यायालय की खंड पीठ को यह अभिनिर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है कि प्रारंभिक आदेश धोखाधड़ी से दूषित है। हालांकि हम उस हद तक नहीं जा सकते हैं, हम निश्चित रूप से मानेंगे।

कि, (i) विभाजन के लिए एक साधारण मुकदमा क्या था; और (ii) आकस्मिक निष्कर्ष में दर्ज किया गया है कि गुण मथुरका गुण थे, उनका उपयोग किया गया है। पक्षों और गैर-पक्षों द्वारा अजनबियों के खिलाफ संपत्तियों पर अधिकार का दावा करना। यह निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

124. दो और पहलू हैं जो इस मामले में कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को उजागर करते हैं। वे इस प्रकार हैं:

(i)

विभाजन के लिए प्रारंभिक आदेश पारित किया गया था

28.06.1963 ; निष्पादन न्यायालय ने 1996 के ई. पी. संख्या 3 में <आई. डी. 1 पर एक आदेश पारित किया जिसमें न्यायालय के बेलिफ को हैदरनगर के सर्वेक्षण संख्या 172 में भूमि का कब्जा डिक्री धारक को देने का निर्देश दिया गया। और उसके बाद एक अंतिम 1998 के आवेदन संख्या 517 में 24.04.1998 पर डिक्री पारित की गई थी। आम तौर पर एक अंतिम डिक्री एक प्रारंभिक डिक्री का अनुसरण करती है और निष्पादन अंतिम डिक्री का अनुसरण करता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, इस मामले में अंतिम आदेश निष्पादन के बाद आया।

(ख)

निष्पादन न्यायालय द्वारा 29.03.1996 पर पारित आदेश

1996 का ई. पी. सं. 3, न्यायालय के बेलिफ को हैदरनगर के सर्वेक्षण सं. 172 में भूमि का कब्जा देने का निर्देश देता है।

यह एक अद्वितीय प्रकार का नमूना था। यह स्मरणीय है कि

आवेदन प्राप्तकर्ता-सह द्वारा लिया गया था

आयुक्त ने 1973 में, 1973 के आवेदन संख्या 19 में, कलेक्टर को सर्वेक्षण संख्या में भूमि का कब्जा सौंपने के निर्देश के लिए प्रार्थना की थी। 145 , 163 और हैदरनगर के 172। इस आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने 05.07.1974 पर एक आदेश पारित किया, जिसमें सरकार को सर्वेक्षण संख्या में स्थित भूमि का प्रतीकात्मक कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया। 145 और हैदरनगर गाँव के 163 एकड़ में 220 गुंटा 18 और एकड़ 175 गुंटा 6 क्रमशः प्राप्तकर्ता को। लेकिन जहां तक अन्य भूमि का संबंध है (यानी सर्वेक्षण)

सं. 172), न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के आदेश में अभिलिखित किया कि सरकार प्रतीकात्मक कब्जा सौंपने की स्थिति में भी नहीं थी और इसलिए यह प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त पर है कि वह ऐसे कदम उठाए जो कानून में उपलब्ध हैं। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि प्रतीकात्मक अधिकार [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वेक्षण सं. 172 में भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1974 में संभव नहीं था, लेकिन आदेशों के माध्यम से बेचे जाने के बाद वर्ष 1996 में वास्तविक कब्जा संभव हो गया।

नियुक्तियाँ। हम नहीं जानते कि इस चमत्कार को संभव बनाने के लिए गोल्डस्टोन ने एक दार्शनिक के पत्थर की तरह क्या जादू किया था।

डिक्री के समनुदेशन हुए थे और समनुदेशनकर्ताओं ने अंतिम डिक्री के साथ-साथ वाद अनुसूची में वर्णित संपत्तियों के हिस्से पर कब्जा करने के लिए कई आवेदन किए हैं। डिक्री के नियुक्तकर्ताओं के साथ समझौता किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा अब तक निपटाये गए अंतिम डिक्री आवेदनों की संख्या और उच्च न्यायालय की फाइल पर अब लंबित अंतिम डिक्री आवेदनों की संख्या कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग की पर्याप्त गवाही देती है।

जिसने उच्च न्यायालय को प्रारंभिक डिक्री को धोखाधड़ी से दूषित और परिणामस्वरूप अमान्य घोषित करने के लिए प्रेरित किया है। वास्तव में, हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि आई. डी. 1 के दौरान, उच्च न्यायालय ने कुछ पक्षों के बीच कथित समझौतों के आधार पर दायर ऐसे सैकड़ों अंतिम डिक्री आवेदनों की सुनवाई और निपटान के लिए एक विशेष खंड पीठ का गठन किया था। इनमें से अधिकांश अभी भी लंबित हैं।

126. तकनीकी रूप से उच्च न्यायालय सही कानूनी अर्थों में, प्रारंभिक डिक्री को धोखाधड़ी से दूषित होने के रूप में ब्रांडिंग करने में सही नहीं हो सकता है। लेकिन द.

तथ्य यह है कि जहां तक खुर्शीद जाह के परिवार के तीसरे पक्षों (और उनके अधीन दावा करने वालों) का संबंध है, प्रारंभिक डिक्री केवल एक कागज के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उन तीसरे पक्षों का विभाजन के दावे से कोई लेना-देना नहीं है, हालांकि मुकदमा अनुसूची में वर्णित संपत्तियों पर उनका वैध दावा है। इसलिए, हम केवल प्रश्न संख्या कहेंगे और रखेंगे। (i) और (iv) कि 28.06.1963 दिनांकित निर्णय और प्रारंभिक डिक्री, हालांकि धोखाधड़ी से दूषित नहीं हो सकती है, निश्चित रूप से तीसरे पक्ष जैसे दावा याचिकाकर्ताओं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं जिन्होंने स्वतंत्र दावे किए हैं। हम यह भी मानते हैं कि आदेश XXI, नियम 97 से 101, सी. पी. सी. के तहत एक जांच में, निष्पादन न्यायालय तीसरे पक्ष द्वारा स्थापित स्वामित्व के प्रश्नों पर निर्णय नहीं ले सकता है, जो अपने आप में स्वतंत्र अधिकार का दावा करते हैं। मरीना बीच (चेन्नई में) या हुसैन सागर (हैदराबाद में) या इंडिया गेट (नई दिल्ली में) को शामिल नहीं किया जा सकता है

16 एक पौराणिक पदार्थ जो किसी भी धातु को सोने या चांदी में बदल देता है या सभी बीमारियों को ठीक करने और जीवन को अनिश्चित काल तक बढ़ाने के लिए माना जाता है।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

याचिका अनुसूची में संपत्तियों की वस्तुओं में से एक के रूप में, परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन के मुकदमे में और इन संपत्तियों के स्वामित्व के प्रश्नों को आदेश XXI, नियम 97-101, सी. पी. सी. के तहत दावा याचिकाओं में निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

127. जहाँ तक सरकार का संबंध है, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस तथ्य पर भारी निर्भरता रखी जाती है कि

128. यह सच है कि प्रारंभिक डिक्री के समर्थन में निर्णय में, मुद्दा संख्या के तहत, शिकायत अनुसूची IV की वस्तु Nos.35 से 40 पर विचार किया गया था। 13 (ग) और 14 (क)। यह भी सच है कि न्यायालय ने डी. डब्ल्यू. 26 और 32 से 34 के साक्ष्य पर विचार किया। आखिरकार, अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे (प्रारंभिक डिक्री के समर्थन में निर्णय में) कि हालांकि मद Nos.38 और 39 स्वीकार्य रूप से खुर्शीद जाह के समय से आए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि एकीकरण के समय उन्हें सरकार द्वारा ले लिया गया था। यही नहीं रुकते हुए, न्यायालय ने निर्णय और प्रारंभिक डिक्री में एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रतिवादी No.1 would का केवल इनकार वादी के दावे को विफल नहीं करता है। इस तरह का निष्कर्ष प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लिए गए एक स्पष्ट रुख के आधार पर दर्ज किया गया था कि वस्तु Nos.38 और 39 राज्य सरकार के कब्जे में हैं।

130. जैसा कि हमने कहीं और कहा है, इसे वाद अनुसूची IV से देखा जा सकता है जिसे दिनांकित निर्णय और डिक्री का हिस्सा बनाया गया था। 28.06.1963 , कि वह संपत्ति जो मुकदमे की विषय वस्तु है, निर्णय और डिक्री के लिए अनुलग्नक IV के क्रम No.32 में जगह पाती है और यह याचिका अनुसूची IV की वस्तु No.38 से मेल खाती है। अभियोग अनुसूची IV में इस संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:

" हैदरनगर पट्टा भूमि। 1210 एकड़ का सघन क्षेत्र "

131. जिसे याचिका अनुसूची IV के मद No.38 के रूप में शामिल किया गया था और निर्णय और डिक्री के अनुलग्नक IV के क्रम No.32 में सूचीबद्ध किया गया था, उसमें (i) पट्टा भूमि की सर्वेक्षण संख्या; या (ii) भूमि की सीमाएँ शामिल नहीं थीं। [2023] 8 एस. सी. आर. के अनुलग्नक IV में तालिका का कॉलम संख्या 4।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्णय और डिक्री में महल्ला या स्थान के नाम का विवरण होता है। जहाँ तक हैदरनगर पट्टा भूमि का संबंध है, कॉलम संख्या 4 में क्या संकेत दिया गया था

हैदरनगर तालुक: गरबी "। किसी को नहीं पता था और न ही किसी ने यह पता लगाने की परवाह की कि क्या हैदरनगर एक गाँव था या तालुक और क्या पूरा हैदरनगर भूमि से बना था, केवल 1210 एकड़ के कुल क्षेत्र में से या कुछ और। यदि हैदरनगर में उपलब्ध भूमि का कुल विस्तार केवल 1210 एकड़ था, तो इसे याचिका अनुसूची में "पूरे हैदरनगर" के रूप में उल्लेख किया गया होगा। दूसरी ओर, यदि जो शामिल किया गया था वह केवल हैदरनगर का हिस्सा था, तो सर्वेक्षण संख्या और सीमाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

132. वास्तव में, प्रारंभिक डिक्री के समर्थन में निर्णय में एक पहली है। न्यायालय ने पहले दर्ज किया कि मुकदमे में विचार के लिए 50 मुद्दे उठे। मूल रूप से विचार के लिए बनाए गए 50 मुद्दों में से, मुद्दा No.14 (a) विशेष रूप से संबंधित वस्तु No.38 (हैदरनगर) से संबंधित है। यह मुद्दा इस प्रकार है:

" 14 (ए)। क्या अनुसूची IV की मद 37 से 40 में उल्लिखित गुण, मकता और इनाम गुण हैं और, यदि ऐसा है,

क्या दीवानी अदालत के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है

वही? "

133. उपरोक्त मुद्दा No.14 (ए) जो सीधे तौर पर शिकायत अनुसूची IV की वस्तु No.38 से संबंधित है, विद्वान न्यायाधीश द्वारा साथ में लिया गया था।

अंक No.13 (सी) के साथ, जो मद संख्या से संबंधित है। 35 और 36, जिसमें सरकार के कब्जे में कुछ कार्यालय भवन मौजूद थे।

134. इन दो मुद्दों पर, अर्थात् अंक संख्या। 13 (ग) और 14 (क), जिन्हें एक साथ लिया गया था, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया: निष्कर्षो:

वह वस्तु संख्या। 35 और 36 शाहबाद में कार्यालय भवन हैं।

(i)

और भाल्की, जागीर के बाद सरकार द्वारा लिया गया

उन्मूलन विनियम और राज्यों के बाद

पुनर्गठन, ये इमारतें मैसूर राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित हुईं और उन्हें मैसूर सरकार को सौंप दिया गया था;

((ख)

कि चूंकि ये संपत्तियाँ सरकार के पास निहित हैं
जागीर उन्मूलन विनियमों के प्रावधानों के आधार पर, मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रैवेंचर लिमिटेड।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

पक्षों को खुर्शीद के समान दावा करने का अधिकार नहीं था

जाह का मथरुक;

(iii)

कि वस्तु Nos.37,38 और 40 क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर हैं
हैदराबाद जिले का और वस्तु No.39 नलगोंडा जिले में है;

(iv)

कि सरकार द्वारा इस संबंध में कोई दावा नहीं किया गया था

मद Nos.38 और 39 और गवाह यह नहीं कहते हैं कि वे मकता भूमि थीं या उन्हें
सरकार द्वारा ले लिया गया था;
कि आइटम No.40 के संबंध में, शीर्षक संदेह में था;

(v)

(vi)

कि इसलिए वस्तु Nos.35,36,37 और 40 को हटा दिया जाना चाहिए
अभियोग अनुसूची IV से;

(vii) यदि सरकार जांच के परिणामस्वरूप इसे जारी करती है तो मद Nos.37 और 40
विभाजन के लिए उपलब्ध होंगे;

(viii) कि इनामों या मक्तों की जांच निश्चित रूप से इसके दायरे में नहीं है।

सिविल न्यायालय की अनन्य अधिकारिता; और

(ix)

कि इसलिए, मुद्दे No.14 (a) का उत्तर में दिया जाना चाहिए

वादी के खिलाफ सकारात्मक और जारी No.13 (c)।

135. मुद्दा Nos.13 (सी) और 14 (ए) पर पूरी चर्चा से पता चलता है कि निचली अदालत ने वास्तव
में एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि कैसे आइटम

अभियोग अनुसूची IV का No.38 परिवार से संबंधित था और विभाजन के लिए उत्तरदायी हो गया। पूरी
चर्चा आइटम Nos.35 से 40 के इर्द-गिर्द घूमती थी। उन्मूलन की प्रक्रिया द्वारा, न्यायालय ने पहले वस्तु
Nos.35 और 36 को हटा दिया,

इस आधार पर कि जागीर उन्मूलन विनियमों के बाद सरकार ने उन पर कब्जा कर लिया था और वे संपत्तियां मैसूर राज्य में निहित थीं। फिर अदालत ने आइटम Nos.37 और 40 को इस आधार पर हटा दिया कि उसी का शीर्षक निलंबन में था और सवाल का जवाब संबंधित अधिकारियों के फैसले पर निर्भर करेगा। इस प्रकार आइटम संख्या को समाप्त करने के बाद। 35 , 36 , 37 और 40, न्यायालय बस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मद संख्या। 38 और 39 विभाजन के लिए उपलब्ध थे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार भी ये वस्तुएं सरकार के कब्जे में थीं। यह तर्क कि न्यायालय ने वस्तु Nos.35 और 36 पर लागू किया था, वस्तु पर लागू नहीं हुआ था।

Nos.38 और 39।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

136. दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से इश्यू No.14 (a) तैयार किया गया था और जिस तरह से इसका जवाब दिया गया था। पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम करेंगे

137. अंक No.14 (a) निकालें जो इस प्रकार है:

" 14 (ए)। क्या अनुसूची IV की मद 37 से 40 में उल्लिखित संपत्तियां, मकता और इनाम संपत्तियां हैं और, यदि हां, तो क्या दीवानी अदालत का इस संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है -

वही? "

इस प्रश्न का उत्तर न्यायालय ने इस प्रकार दिया:

" इश्यू No.14 (a) का जवाब सकारात्मक होना चाहिए।

138. यदि इश्यू No.14 (a) का उत्तर सकारात्मक में दिया जाता है, तो आइटम संख्या में सभी गुण। 37 40 तक मकता और इनाम की संपत्तियाँ हैं और

दीवानी न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रारंभिक आदेश द्वारा प्रस्तुत पहेली है। इसलिए, प्रारंभिक डिक्री के धारक और उनके समनुदेशक और खरीदार यह दावा नहीं कर सकते हैं कि सरकार

पहले से ही एक अवांछित व्यक्ति बन गया था।

139. इसलिए, जर्मनी में, हम निर्गम संख्या (i) पर मानते हैं कि निर्णय और प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.06.1963, हालांकि हो सकता है

धोखाधड़ी से दूषित नहीं होते हैं, निश्चित रूप से तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी नहीं हैं

जैसे दावा याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सरकार जिन्होंने स्वतंत्र दावे किए हैं और जो कुछ भी अनुसरण में किया गया था

प्रारंभिक डिक्री कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। हम.

अंक संख्या (iv) में यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश XXI के तहत एक जांच में,

नियम 97 से 101, सी. पी. सी., निष्पादन न्यायालय तीसरे पक्ष द्वारा स्थापित स्वामित्व के प्रश्नों पर निर्णय नहीं ले सकता है (इसके माध्यम से या इसके तहत दावा नहीं कर सकता है)

मुकदमे के पक्षकार या उनके परिवार के सदस्य), जो अपने आप में स्वतंत्र अधिकार का दावा करते हैं। निष्पादन के चरण में ऐसे मामलों में केवल यह पता लगाया जा सकता है कि क्या बाधा डालने वाले/दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं के पास विभाजन मुकदमे के पक्षकारों के अधिकारों से स्वतंत्र, स्वामित्व का प्रामाणिक दावा है या नहीं। यदि उनके पास स्वामित्व का स्वतंत्र दावा पाया जाता है, तो विभाजन के लिए

डिक्री के धारक को इन कार्यवाही में तीसरे पक्ष के अधिकारों को पराजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मुद्दा संख्या। (ii) और (iii)

(ii) क्या एकल न्यायाधीश के समवर्ती निष्कर्ष

और उच्च न्यायालय की खंड पीठ जो खुर्शीद जाह ने की थी

कोई भी मथरुका संपत्ति नहीं छोड़ना, मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रैवेंचर लिमिटेड के विपरीत है।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

निर्णय और प्रारंभिक डिक्री में अभिलिखित निष्कर्ष जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है? और

((ग) क्या निर्णय में अभिलिखित निष्कर्ष और

प्रारंभिक आदेश कि हैदरनगर की भूमि मातृका की संपत्ति है, तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी है?

140. अंक संख्या (iii) का उत्तर खोजना बहुत कठिन नहीं है। मुद्दा संख्या से निपटते समय। (i) और (iv), हम पहले ही यह मान चुके हैं कि किसी संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित कोई भी निष्कर्ष, जो विभाजन के लिए एक साधारण मुकदमे में दर्ज किया गया है, तीसरे पक्ष पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है। प्रारंभिक डिक्री में इस निष्कर्ष के संबंध में भी यही बात अच्छी होगी कि अधिकांश वाद अनुसूची संपत्तियां मातृका संपत्तियां थीं। इसे स्पष्ट करते हुए आइए हम अंक संख्या (ii) पर वापस जाएं।

141. हमारे समक्ष उद्भूत मुद्दा संख्या (ii) यह है कि क्या 1995 के आवेदन No.994 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष और

खंड पीठ द्वारा विवादित फैसले में दर्ज किया गया निष्कर्ष कि खुर्शीद जाह ने कोई मातृका संपत्ति नहीं छोड़ी, इसके विपरीत है प्रारंभिक डिक्री में दर्ज निष्कर्ष जो अंतिमता प्राप्त कर चुका है?

142. इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, आइए हम पहले प्रारंभिक डिक्री के समर्थन में निर्णय पर वापस जाएं और देखें कि क्या ट्रायल जज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई अधिकांश सूट संपत्तियां मथरुका संपत्तियां थीं।

143. प्रारंभिक डिक्री के समर्थन में निर्णय में,

ट्रायल जज ने दो मुद्दों को इश्यू Nos.7 (ए) और 7 (बी) के रूप में तैयार किया। मुद्दा संख्या 7 (ए) इस बारे में था कि क्या वाद संपत्ति का विवरण वाद अनुसूची IV, IVA में दिया गया है।

डिक्री में लिखा है कि मुद्दा संख्या 7 (ए) पर विचार करते समय अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार करना आवश्यक होगा, जैसे कि मुद्दा संख्या 8 (ए) जो खुर्शीद जाह द्वारा किए गए समझौते से संबंधित था; अंक संख्या 9 जो [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी संख्या 1 के संपत्ति की कुछ वस्तुओं के एकमात्र मालिक होने के दावे से निपटा गया; मुद्दा संख्या। 10 और 11 जो क्रमशः दो वस्तुओं और संपत्ति की चार वस्तुओं के स्वामित्व से संबंधित थे; जारी करें No.12 जो संपत्ति की विशिष्ट वस्तुओं के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के दावे से संबंधित है; और मुद्दा संख्या 1 जो प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिकूल कब्जे के दावे से संबंधित है।

145. इसलिए, मुद्दा Nos.7 (ए) और 7 (बी) पर चर्चा को ट्रायल जज द्वारा अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला भाग संबंधित था।

अंक Nos.8 (a), 11 और 12 के साथ और अंक Nos.9 से संबंधित अगला भाग और अंक Nos.7 (a) और (b) के साथ 20।

146. इन सभी मुद्दों को अंक संख्या के साथ जोड़कर। 7 (क) और (ख), ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायाधीश ने अपना रास्ता खो दिया है, जिसके परिणामस्वरूप नहीं

अंक Nos.7 (a) और 7 (b) पर प्रत्यक्ष निष्कर्ष।

147. परीक्षण न्यायाधीश द्वारा शीर्षक के तहत दर्ज किए गए निष्कर्ष

" अंक 7 (ए) और 7 (बी) जिसमें अंक 8 (ए) और 8 (बी), 9,11,12 और 20 शामिल हैं, इस प्रकार हैं:

कि दो दस्तावेज थे, एक विभाजन का और दूसरा

(i)

प्रदर्शनी डी. 1 (6) और डी. 1 (29) के रूप में चिह्नित उपहार

प्रतिवादी सं। 1 और 2;

((ख)

कि इन दस्तावेजों के तहत, खुर्शीद जाह ने एक

उसकी सभी संपत्तियों का निपटान;

(iii) कि दस्तावेज़ में निहित पाठों में से एक में, उन्होंने निर्देश दिया कि अचल संपत्तियों को उनके बीच विभाजित किया जाए।

दो पुत्र उसके अधिकार में और उसके अधिकार में रहेंगे।

((iv)

कि इस पाठ ने दस्तावेज़ को एक वसीयत का रंग दिया;

(v)

कि दूसरा दस्तावेज़ कोडिसिल की प्रकृति का था;

(vi)

कि मुस्लिम कानून के तहत, एक वसीयती स्वभाव हो सकता है

एक तिहाई से अधिक संपत्तियों के संबंध में नहीं किया गया;

(vii) कि यदि स्वभाव किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में है, तो यह अमान्य है।

जब तक कि अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा सहमति न दी जाए;

(viii) कि खुर्शीद जाह के उत्तराधिकारियों में से एक ने अपनी सहमति नहीं दी

और इसलिए वसीयत का कोई फायदा नहीं हुआ;

(ix) कि डी. डब्ल्यू.-25 (विट्टल राय, पैगाह के एक पुराने कर्मचारी) की गवाही के अनुसार, खुर्शीद ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड की मृत्यु के बाद।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. यू. आर. टी. एच. वाई एंड ओ. आर. एस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

हाँ, पैगाह की संपत्ति के तहत रखा गया था

जफर जंग की देखरेख जिन्हें कभी नामित नहीं किया गया था

अमीर पैगाह;
के बाद, की पूरी संपत्ति

कि जफर जंग की मृत्यु

x)

खुर्शीद जाह को कोर्ट ऑफ वाड्स द्वारा ले लिया गया था, जिसने 1338 ई. तक इसका प्रबंधन किया था।

xi) कि 1338 एफ के फरमान के बाद, सभी संपत्तियों को घोषित किया गया था

खुर्शीद जाह की संपत्ति से संबंधित संपत्तियों के रूप में;

xii) कि पैगाह के उन्मूलन तक संपत्तियों का प्रबंधन किया गया था

समिति इंतेज़ामी पैगाह द्वारा;

xiii) कि प्रदर्शनी पी. 7 (ए) भूमि और मकतजात से संबंधित है;

xiv) कि वे हशमतपेट, हफीजपेट, हैदरनगर आदि थे; xv) कि दस्तावेज़ों में पी. 2 (ए), पी. 3 (ए), पी. 4 (ए), पी. 6 (ए) और

पी. 7 (ए) आय के विवरणों की सभी प्रतियां थीं और

केंद्रीय अभिलेख कार्यालय से प्राप्त व्यय;

xvi) कि प्रतिवादी संख्या 1 का दावा कि डी. 1 (6) और डी. 1 (29) के तहत खुर्शीद जाह की संपत्तियों को उपहार में दिया गया था और विभाजित किया गया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है; xvii) कि खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का कभी विभाजन नहीं किया गया था

और वे लगातार अमीर के कब्जे में बने रहे
पैगाह;

xviii) कि पैगाहों के उन्मूलन तक, ये गुण थे

अमीर पैगाहों की समिति द्वारा प्रबंधित;

xix) कि खुर्शीद जाह की संपत्ति, कुछ समय पहले के लिए

जागीरों का उन्मूलन, एक विशेष अदालत के तहत रखा गया था

वार्ड;

xx) कि हालांकि प्रदर्शनी डी. 1 (3) दिनांक 25.04.1950 के तहत,

संपत्ति को फरमान के तहत जारी करने का निर्देश दिया गया था, फिर भी आदेशों के तहत संपत्ति का पर्यवेक्षण जारी रहा

खुर्शीद जाह पैगाह के मुख्यमंत्री;

xxi) कि केवल इसलिए कि सरकार ने अमीर पैगाह के रूप में उनके अधिकार की मान्यता में हिमायत नवाज जंग को संपत्ति सौंप दी, उन्हें अनन्य मालिक नहीं माना जा सकता है; और [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xxii) कि प्रतिवादी संख्या 1 संभवतः खुर्शीद जाह के उत्तराधिकार की पंक्ति में आने वाले किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत अनुसूची IV की वस्तु संख्या 1 का अधिकार स्थापित नहीं कर सकता है।

148. पिछले पैराग्राफ में, हमने मुकदमे के न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए सभी निष्कर्षों को अंक Nos.7 (a) और 7 (b) के तहत अंक Nos.8 (a) और 8 (b), 9,11,12 और 20 के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में, मुद्दा संख्या पर चर्चा। 7 (a) और 7 (b) दिनांकित 28.06.1963 निर्णय की प्रमाणित प्रति (फोटोकॉपी) के आंतरिक पृष्ठ No.198 से शुरू होता है और यह

आंतरिक पृष्ठ No.224 तक जाता है। इन सभी 27 पृष्ठों में, 'मथरुका' शब्द शायद केवल एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जिसका नाम पृष्ठ No.212 है और वह भी एक गवाह द्वारा इस आशय के बयान के रूप में कि मथरुका को कभी भी जफर जंग और इमाम जंग के बीच विभाजित नहीं किया गया था।

149. दूसरे शब्दों में, परीक्षण न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांक 28.06.1963 के फैसले में कभी भी कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि संपत्तियों को छोड़ दिया गया था

खुर्शीद जाह के पीछे मथरुका की संपत्तियाँ थीं। इसलिए,

यह तर्क मानो कि ऐसा कोई निष्कर्ष था और निष्कर्ष ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और यह कि विवादित निर्णय इस तरह के निष्कर्ष के विपरीत है, पूरी तरह से गलत धारणा है।

150. 28.06.1963 दिनांकित निर्णय के कुछ हिस्सों पर भरोसा किया गया

अपीलकर्ताओं द्वारा यह दिखाने के लिए कि संपत्तियाँ खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई मथरुका संपत्तियाँ थीं, सभी निष्कर्ष अंक संख्या के तहत दर्ज नहीं किए गए थे। 7 (ए) और 7 (बी)। वे या तो दलीलों का हिस्सा थे या अंक संख्या 6 (बी) के तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों का हिस्सा थे, जो मिर्जा यार जंग समिति की रिपोर्ट से संबंधित थे, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि जीवित वैध उत्तराधिकारियों का गठन किसने किया था। इसलिए, अपीलार्थियों द्वारा दिनांकित 28.06.1963 के निर्णय के कुछ हिस्सों पर यह कहने के लिए की गई निर्भरता कि संपत्ति को मथरुका माना गया था, गलत है।

151. यह दावा करने के लिए कि मुकदमे की संपत्तियाँ मथरुका थीं

अपीलार्थियों द्वारा निम्नलिखित गुणों पर भी निर्भरता रखी जाती है:

सनद दिनांकित 03.12.1877;

राज्य द्वारा जारी जीओएमएस No.1106 दिनांकित 06.06.1959

आंध्र प्रदेश ने इनाम जाँच का आदेश दिया,

नाजिम अतियत अदालत द्वारा पहले पारित आदेश

11.09.1959 और फिर 30.10.1968 पर; और

आयुक्त द्वारा 14.02.1983 पर जारी किया गया मुंतखाब।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्ठी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

152. लेकिन हम नहीं जानते कि अपीलार्थी कैसे निर्भरता रख रहे हैं।

इन दस्तावेजों पर इस तर्क के समर्थन में कि खुर्शीद जाह द्वारा छोड़ी गई संपत्तियां मथरुका संपत्तियां हैं। यदि हम घटनाओं के कालक्रम पर एक नज़र डालते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किया गया सनद केवल निम्नानुसार बताता है:

" यह कहा गया है कि पुराने के अनुसार, हाफ़िज़ पेठ की नज़रा (यानी कृषि भूमि) और हैदरनगर की मज़रा (यानी कृषि भूमि)

उक्त परगना सरकार के गांव मियांपुर के सीवर (यानी सीमाएं) और नाहसिल के साथ उक्त एस. बी. ए. की सीमाएं, यानी परगना के गांव अमीर खंगुडा के सीवर के मजना तिममईपल्ली के बदले में दिए गए एक हजार एक सौ चौंतीस रुपये और दस साल के भूमि राजस्व का आकलन।

इब्राहिमपटन जिसे "खालसा" में शामिल किया गया है, अर्थात् सरकारी भूमि और खुर्शीद नगर की भूमि जिसके पास है

रेलवे रोड के अंतर्गत चला गया, जो दोनों खुर्शीद जाह के खरीदे गए थे (यानी उनकी 'ज़ार खरीद यानी खरीदी गई ज़मीन) और' खरीज " जामा 'यानी सरकारी माँग से बाहर थे। इसलिए वर्ष 1286 की शुरुआत से फसली थे

उक्त बहादुर यानी खुर्शीद जाह बहादुर और उनके वंशजों के नाम पर 'इनाम अलतमघा' और खरिज 'जामा' (यानी सरकारी मांग से बाहर) शीर्षक के तहत निर्धारित किया गया और

असमिया की शर्त के बिना उत्तराधिकारी अर्थात् किसी का विशेष रूप से नाम लिए बिना, 'चौथ' आदि वस्तुओं की छूट के साथ।

आपको उक्त बहादुर यानी खुर्शीद जाह बहादुर के डिप्टी के नायब का अनुबंध करके भुगतान करना जारी रखना चाहिए।

समय पर और समय पर राजस्व निधरिण की देय राशि। इसे एक सख्त आदेश मानते हुए, यानी इस मामले में 'लिया गया', कार्रवाई जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसे लिया जाए।

153. सनद में केवल यह कहा गया है कि रेलवे रोड के लिए खुर्शीद नगर की सरकारी भूमि और भूमि का अधिग्रहण किया गया था और

अधिग्रहित भूमि खुर्शीद जाह की खरीदी गई भूमि थी। यदि उक्त कथन के कारण, भूमि को मथरुका के रूप में माना जाना है, तो हम नहीं जानते कि खुर्शीद जाह की मृत्यु के बाद ये भूमि भी पैगाह समिति के हाथों में कैसे और क्यों चली गई। किसी भी मामले में, ये वे प्रश्न हैं जिनका निर्णय न्यायालय द्वारा विभाजन के मुकदमे में नहीं किया जा सकता था।

154. नाजिम अतियत के दिनांकित 30.10.1968 और आयुक्त द्वारा 14.02.1983 पर जारी किए गए मुंतखाब के आदेश में [2023] 8 एस. सी. आर. नहीं हो सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1958 के सी. एस. No.14 में विचारण न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि ये दस्तावेज निर्णय और प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.06.1963 के बाद अस्तित्व में आए थे।

155. यह याद रखना चाहिए कि अपीलार्थियों के दावे का पूरा आधार यह है कि प्रारंभिक डिक्री के अनुसार ये संपत्तियां मातृका संपत्तियां थीं। लेकिन यह बात मुकदमे के न्यायाधीश द्वारा अंक संख्या पर अपने 27 पृष्ठों के फैसले में दर्ज किए गए निष्कर्षों से साबित नहीं होती है। 7 (ए) और 7 (बी)। 156. नज़ीम अतियत अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से बहुत कुछ करने की कोशिश की गई थी कि हफीज़पेट और हैदरनगर में भूमि

नाजिम अतियत के आदेश के परिशिष्ट 'एफ' के अनुसार अधिसूचना में सीरियल Nos.380 और 381 में शामिल इनाम-अल-तमघा था। नज़ीम अतियत के क्रम के अनुलग्नक में इनाम-अल-तमघाइस का वर्णन किया गया है। वह इस प्रकार है:

" 1. S.No.380 और No.381 के गाँवों को इस प्रकार सत्यापित किया गया है

" खुरशीद जाह बहादुर के नाम पर इनाम अल-तमाघा

1296 एच के "कैफ़ीयत-I-जिगरदारन" के अनुसार।

"तमघा" शब्द का अर्थ है "शाही चार्टर"। जागीरदारों या किसी और को जागीर या इनाम देने के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों में जागीर/इनाम/के बारे में जानकारी की एक चेकलिस्ट होती थी।

अनुदान, इसकी प्रकृति का वर्णन करने के लिए, भूमि के "जागीर/इनाम/अनुदान के प्रकार" के रूप में लेबल किया गया है। नवाब खुरशीद जाह बहादुर को दी गई जागीर थी

" इनाम-अल-तमघा ", जो उन्हें उनकी सेवाओं की मान्यता में या सरकार द्वारा अधिग्रहित किसी जागीर/भूमि या भूखंड के बदले में दिया गया था। सड़क/रेलवे लाइन बिछाने या किसी सार्वजनिक सुविधा के निर्माण जैसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से बाहर आदि। "

157. जैसा कि हमने कहीं और कहा है, नज़ीम अतियत का आदेश विचारण न्यायाधीश के समक्ष नहीं था। ट्रायल जज ने कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि यह इनाम-अल-तमघा था। किसी भी मामले में, यह केवल विभाजन के लिए एक मुकदमा था।

158. अगर हम यह भी मान लें कि यह इनाम-अल-तमघा था, तो सवाल यह उठता है कि क्या आगमन के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। हैदराबाद इनाम उन्मूलन अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम No.VIII) 1. यह अधिनियम धारा 2 (1) (सी) के तहत "इनाम" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है निजाम या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए उपहार या अनुदान के तहत रखी गई भूमि।

17 संक्षेप में "1955 अधिनियम" मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

जागीरदार, संस्थान या अन्य सक्षम अनुदानकर्ता का धारक और सेवा की शर्त के साथ या उसके बिना, मुंतखाब या अन्य स्वामित्व विलेख के आधार पर जारी या पुष्टि करता है। इसलिए, यदि कम से कम नाजिम अतियत और मुंतखाब का आदेश प्रारंभिक डिक्री से पहले अस्तित्व में आया होता और उन्हें मुकदमे में प्रदर्शन के रूप में पेश किया गया होता, तो ट्रायल जज को इनाम-अल-तम्बा पर 1955 के अधिनियम के प्रभाव का पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाने का अवसर मिल सकता था।

जागीर उन्मूलन विनियमों के तहत गिलोटिन, यह 1955 के अधिनियम के तहत अपने भाग्य का सामना कर सकता है। 160. इसलिए हम अंक संख्या का पालन करते हैं। ((ii) और (iii) कि एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ (विवादित मामले में)

निर्णय) यह अभिनिर्धारित करने में सही थे कि संपत्तियां मातृका संपत्तियों के रूप में स्थापित नहीं की गई थीं। नज़ीम अतियत के आदेश के प्रभाव की जाँच विचारण न्यायाधीश द्वारा नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, इस तरह की जांच स्वतंत्र रूप से की जानी थी, न कि विभाजन के मुकदमे में, 1955 के अधिनियम और कृषि भूमि सुधारों और शहरी भूमि से संबंधित विभिन्न बाद के अधिनियमों को ध्यान में रखते हुए।

छता।

मुद्दा सं. (v):

क्या दावा याचिकाकर्ताओं के दावे कायम रहे

स्थापित?

161. अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि दावा याचिकाकर्ता (निष्पादन में बाधा डालने वाले) यह दिखाने के लिए कागज का एक भी टुकड़ा पेश नहीं कर सके कि उन्होंने सर्वेक्षण No.172 में भूमि के कुछ हिस्सों का स्वामित्व कैसे प्राप्त किया।

162. लेकिन उक्त तर्क पूरी तरह से सही नहीं लगता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 26.10.2004 के आदेश का अनुच्छेद 58, जिसका एक हिस्सा खंड पीठ के विवादित फैसले में निकाला गया है, में कहा गया है कि इन दावे याचिकाकर्ताओं ने अपने पूर्ववर्तियों के पक्ष में दिए गए पट्टों की मूल या प्रमाणित प्रतियां दायर की थीं। पैराग्राफ 59 से पैराग्राफ 61 तक, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुद्दा संख्या 4 पर विचार किया कि क्या बोर्डु [2023] 8 एस. सी. आर. के पक्ष में पट्टा दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वीरास्वामी और अन्य। उन्होंने अतिरिक्त अंक संख्या 2 पर भी विचार किया कि क्या दावेदारों ने अन्यथा प्रतिकूल कब्जे द्वारा अधिकार को परिपूर्ण किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिलिखित किया कि बोर्डू वीरास्वामी और अन्य को वर्ष 1947 में पट्टा प्रदान किया गया था और चूंकि ये दस्तावेज 30 साल से अधिक पुराने थे, इसलिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 को देखते हुए इन दस्तावेजों के आगे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी दर्ज किया कि सेठवार, फैसल पट्टी, जमाबंदी, कर प्राप्तियों के रूप में पर्याप्त सबूत थे।

और विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही। अंततः, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने फैसले के पैराग्राफ 61 में निष्कर्ष निकाला कि भले ही दावेदारों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेज दोषपूर्ण पाए गए हों, दावेदारों का कब्जा यहां अपीलार्थियों के लिए प्रतिकूल हो गया है।

163. उक्त निष्कर्ष पर जोर देते हुए, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि

धारा 90 के तहत अनुमान केवल तभी लागू होगा जब एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है और यह साबित होने के बाद ही कि यह उचित अभिरक्षा से आया है। 164. लेकिन धारा 90 के तहत स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है यदि यह साबित हो जाता है कि इसका मूल वैध था या

विशेष मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो ऐसी उत्पत्ति को संभावित बनाती हैं।

165. किसी भी मामले में, विद्वान न्यायाधीश मालिकाना हक के मुकदमे पर विचार नहीं कर रहे थे। यह मानते हुए कि दावा याचिकाकर्ता स्वामित्व के प्रवाह को साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, वे स्वीकार्य रूप से कब्जे में थे और उन्हें जिला न्यायालय, रंगा रेड्डी जिले के माध्यम से बेदखल करने की मांग की गई थी।

166. जब अपीलार्थियों का पूरा दावा है कि संपत्तियाँ

कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में मिली मातृका संपत्तियाँ विफल हो गई थीं, इस दलील के बल पर एक डिक्री को निष्पादित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि संपत्ति एक मातृका संपत्ति है।

167. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से उप-धारा (2) और (3) पर भरोसा किया।

दावेदारों को पट्टादार का दर्जा प्रदान करने के लिए हैदराबाद भूमि राजस्व अधिनियम, 1317 एफ. (1907 ई.) की धारा 86। विद्वान वरिष्ठ वकील ने बताया कि ए. पी. अनुकूलन आदेश, 1957 द्वारा धारा 86 की उप-धारा (2) और (3) को हटा दिया गया था।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

168. लेकिन उपरोक्त तर्क अपीलार्थियों के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है। जिस क्षण अपीलार्थियों का दावा कि यह एक था

169. सर्वेक्षण और भूमि अभिलेख विभाग द्वारा सत्यापित हैदरनगर का एक मूल मानचित्र हमारे समक्ष प्रस्तुत करने की मांग की गई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि सर्वेक्षण में भूमि को वर्ष में 24/25 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता था, जैसा कि दावा याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया था। लेकिन यह मानचित्र, जो हाल ही में सुरक्षित किया गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश या खंड पीठ के समक्ष नहीं था। इसलिए, हम विवादित निर्णय की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए इस पर विचार नहीं कर सकते। 170. इसके अलावा, यह तर्क कि सर्वेक्षण No.172 को वर्ष 1978 में 24/25 भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता था, एक आत्म-पराजित तर्क है। अधिकार का दावा करते समय, कुछ अपीलार्थी और उनके पूर्ववर्तियों ने प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त की एक रिपोर्ट पर भरोसा किया

और 1971 के आवेदन संख्या 139 दिनांक 31.01.1976 में विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश। यह इस दस्तावेज़ के तहत था कि प्रतिवादी Nos.50,51 और 52 के साथ-साथ प्रतिवादी No.116 ने सर्वेक्षण No.172 में उप-विभाजित भूमि के कुछ हिस्सों पर अधिकार का दावा किया। यह सच है कि साइरस/गोल्डस्टोन/ट्रिनिटी ने 1971 के आवेदन No.139 के आदेश पर भरोसा नहीं किया था। वे दावा करते हैं

कमिश्नर। यह या तो सी. पी. सी. की धारा 54 के संदर्भ में कलेक्टर के आदेश के तहत राजस्व मंडल अधिकारी द्वारा कथित रूप से किए गए विभाजन पर आधारित था या उनके द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर था। प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त। प्रतिवादी सं। 51 और 52 प्रतिवादी संख्या 1 के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। अपीलकर्ता साइरस/गोल्डस्टोन/ट्रिनिटी के पास कोई दावा नहीं हो सकता था, लेकिन एच. ई. एच. निजाम द्वारा अविभाजित शेयरों के 80 प्रतिशत की खरीद के लिए, जिसे बाद में प्रतिवादी No.156 के रूप में शामिल किया गया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती इन उपखंडों पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपीलकर्ता इसे नकारते हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी अनुमोदन और खंडन करने के दोषी हैं।

171. अपीलार्थियों के पूर्ववर्तियों को जानकारी थी कि 1978 में दावा याचिकाकर्ताओं के नाम पर फैसल पट्टी दर्ज की गई थी

स्वयं। यहाँ तक कि प्राप्तकर्ता को भी इसके बारे में पता था, जैसा कि प्राप्तकर्ता द्वारा 09.04.1980 पर कलेक्टर को लिखे गए पत्र से देखा जा सकता है। फिर भी प्राप्तकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि सर्वेक्षण No.172 में भूमि का कब्जा [2023] 8 एस. सी. आर. हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी संख्या को प्रदान किया जाए। 157 और 206। इस संबंध में प्राप्तकर्ता सह-आयुक्त की रिपोर्ट और उस पर न्यायालय द्वारा कब्जा सौंपने के लिए दिनांक 20.01.1984 पर पारित आदेश चौंकाने वाला है।

इस तथ्य के आलोक में कि प्राप्तकर्ता ने स्वयं अपने दिनांकित 09.04.1980 पत्र में दर्ज किया कि फैसल पट्टी दावा याचिकाकर्ताओं के नाम पर थी। इसलिए, अपीलार्थियों के लिए यह सवाल करने में बहुत देर हो चुकी है कि दावा याचिकाकर्ताओं का दावा कैसे स्थापित हुआ। हम तदनुसार दावा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में इस मुद्दे संख्या (v) का जवाब देते हैं।

मुद्दा सं. (vi):

क्या तेलंगाना राज्य का कोई वैध दावा है

और क्या न्यायालय कक्ष में राज्य सरकार को कई बार झटका लगने के बाद भी ऐसा कोई दावा कायम रहेगा?

173. उपरोक्त निष्कर्ष के बाद, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 414 (डी) में घोषणा की कि भूमि राज्य सरकार में निहित नहीं है। हैदराबाद जागीर उन्मूलन विनियमों के बाद। इस तरह के निष्कर्ष और निष्कर्ष से व्यथित, तेलंगाना राज्य मूल रूप से 2022 के आई. ए. संख्या 75869 में एस. एल. पी. (सिविल) संख्या के पक्षकारों के रूप में खुद को शामिल करने के लिए एक आवेदन के साथ आया। 2373-2377 2020 से। लेकिन बाद में, राज्य ने 2022 की एसएलपी (डायरी) संख्या 19266 में एक स्वतंत्र अपील दायर की है।

इसलिए, अभियोग के लिए आवेदन अनावश्यक है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

174. तेलंगाना राज्य द्वारा दायर अपील पर आते हुए, इस विवादित फैसले से यह देखा जाता है कि राज्य पहले पक्षकार नहीं था

उच्च न्यायालय की खंड पीठ। अतः उपरोक्त निष्कर्ष

तेलंगाना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। वास्तव में, तेलंगाना राज्य को विवादित फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ 414 (डी) में घोषणा को अपीलार्थियों के दावे के संबंध में एक निष्कर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए।

175. चूंकि तेलंगाना राज्य अपीलों के साथ आया है, इसलिए अपीलकर्ताओं (डिक्री धारकों) के साथ-साथ दावा याचिकाकर्ताओं ने मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर लिमिटेड को लिया है।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

1985 24.12.1999 पर खारिज कर दिया गया था। उसी के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को नियमित रूप से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ 05.05.2000 पर वापस ले लिया गया था। प्रारंभिक डिफेंडी के खिलाफ अपील। लेकिन प्रारंभिक आदेश के खिलाफ वर्ष 2000 में दायर की गई अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि

38 साल की देरी। उक्त आदेश की पुष्टि इस अदालत ने की थी। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि राज्य के दावे के भाग्य को कम से कम अब सील कर दिया जाना चाहिए।

176. लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हंस के लिए चटनी क्या है?

गैंडर के लिए एक चटनी होनी चाहिए। यदि विभाजन के मुकदमे में, किसी संपत्ति का स्वामित्व विभाजन का दावा करने वाले पक्षों के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है

अगर कोई अजनबी है, तो वही तर्क दावा याचिकाकर्ताओं पर भी लागू होगा। राज्य सरकार।
जैसा कि श्री सी. एस.

वैद्यनाथन, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील, इस संबंध में बहुत सारे मुद्दे अनसुलझे हैं। न्यायालय के लिए अब तक 1955 के अधिनियम के प्रभाव पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। यह मानते हुए कि दावा याचिकाकर्ताओं के पास हैदरनगर के सर्वेक्षण में भूमि के एक हिस्से का स्वामित्व था (कुल एकड़ में से लगभग 11 एकड़), यह सवाल अभी भी बना रहेगा कि भूमि के शेष हिस्से का स्वामित्व किसके पास है, अगर डिफेंडी के असाइनी बाहर जाते हैं। यदि जागीर उन्मूलन विनियमों के कारण अपीलार्थियों का शेष भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और यदि दावा याचिकाकर्ताओं का भूमि के केवल एक हिस्से पर अधिकार है

1948 से पहले दिए गए पट्टों में से, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भूमि के शेष हिस्से का मालिक हो। यह मानते हुए कि जमीन का मालिक कोई और है, कृषि भूमि सुधारों और शहरी भूमि सीमा का प्रभाव

अधिनियमों पर अभी भी विचार किया जाना बाकी था।

177. लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, हम इन कार्यवाही में अधिकार प्राप्त करने का निर्णय नहीं ले रहे हैं। इसलिए, जो कुछ भी हम जवाब में रखेंगे

मुद्दा सं. (vi) के लिए यह है कि पैराग्राफ 244 में दर्ज निष्कर्ष और आक्षेपित के अनुच्छेद 414
(घ) में पहुँचा गया निष्कर्ष

निर्णय, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भाग-V:

उन व्यक्तियों द्वारा अपीलें जिनके अभियोग आवेदन थे

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, लेकिन जिनके मामले दावा याचिकाकर्ताओं के समान हैं

178. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित फैसले में 24 अभियोग आवेदनों को खारिज कर दिया।

इस आधार पर कि कोई तीसरा पक्ष द्वारा दायर दावा याचिका में शामिल नहीं हो सकता है

और यह कि ऐसे पक्षों का एकमात्र उपाय अलग-अलग दावा याचिकाएं दायर करना है।

179. सभी 24 अभियोग आवेदन अलग-अलग के अंतर्गत आते हैं।

श्रेणियाँ अर्थात्:

जो भूमि के एक हिस्से पर अधिकार होने का दावा करते हैं

(i)

हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में साइरस/गोल्डस्टोन/ट्रिनिटी द्वारा कथित रूप से खरीदे गए आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करना;

((ख)

जो भूमि के एक हिस्से के कब्जे में होने का दावा करते हैं

हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 का दूसरा आधा;

((iii) वे जो अन्य सर्वेक्षण में भूमि के कब्जे में होने का दावा करते हैं।

संख्याएँ;

(iv) परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो होने का दावा करती है

गिरवीदार; और

(iv) ओ. एस. ए. No.59 में अभियोग लगाने के लिए आवेदन दायर करने वाले लोग।

2004 से।

180. उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्तियों में से जिनके अभियोग आवेदन खारिज कर दिए गए थे, संपत्ति पुनर्निर्माण का मामला कंपनी के बारे में निर्णय के अगले भाग में हमारे द्वारा चर्चा की गई है।

181. जहाँ तक अन्य व्यक्तियों का संबंध है जिनके अभियोग आवेदन

जिन्हें बर्खास्त किया गया है, वे चिंतित हैं, हम नहीं जानते कि वे खुद को विवादित फैसले से क्यों प्रभावित मानते हैं। पैराग्राफ 414 (ई) में

विवादित निर्णय के संबंध में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस न्यायालय द्वारा गैर-न्यायिक के सिद्धांत पर इसे दरकिनार करने के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती पीठ के दिनांकित पूरे आदेश को अमान्य करार दिया है। पैराग्राफ 414 (एफ) में, उच्च न्यायालय ने हैदरनगर गांव में भूमि के संबंध में पूरे प्रारंभिक आदेश की घोषणा की थी।

(किसी विशेष सर्वेक्षण संख्या तक सीमित नहीं) शून्य के रूप में। पैराग्राफ 414 (जी) में, आवेदन मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड में 20.01.1984 दिनांकित आदेश।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

1983 का No.266 और आवेदन में दिनांकित 28.12.1995 आदेश

1995 के No.994 को न केवल दावा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बल्कि तीसरे पक्ष के खिलाफ भी अनिर्णायक माना गया है। पैराग्राफ 414 (एच) में, उच्च न्यायालय ने अंतिम डिक्री को भी घोषित किया है

शून्य और शून्य। पैरा 414 (i) में, जिला न्यायालय द्वारा पारित 1996 के ई. पी. सं. 3 में दिनांकित 29.03.1996 आदेश और दिनांकित 19.04.1996 बेलिफ की रिपोर्ट को न केवल दावा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बल्कि किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ भी गैर-मौजूद और अमान्य माना गया है। दूसरे शब्दों में, अभियोग आवेदनों को खारिज करने के बावजूद, उच्च न्यायालय ने उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा की है जिनके खिलाफ डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई है। किसी भी मामले में, उन व्यक्तियों

जिनके पास बाधा डालने वालों के समान दावा है, जिन्होंने विवादित फैसले के खिलाफ स्वतंत्र अपील दायर की है, उनके पास होगा निर्णय का लाभ। लेकिन इस निर्णय का लाभ (i) 1958 के सी. एस. No.14 के किसी भी पक्ष के तहत अधिकार का दावा करने वाले उन तीसरे पक्षों और (ii) 1958 के सी. एस. संख्या 14 में फरमान या फरमानों के समनुदेशन का दावा करने वालों को नहीं मिलेगा।

भाग-VI:

विवादित निर्णय के लिए गैर-पक्षों द्वारा अपील,

विवादित फैसले के केवल एक हिस्से को चुनौती देना 182. कुछ लोग, अर्थात् समीना कौसर और चार अन्य, जो सभी स्वर्गीय मिर्जा मजहर बेग की बेटियाँ हैं, आए हैं।

ओएसए Nos.54,56,58 में फैसले के खिलाफ अलग-अलग अपीलों के साथ और 2004 का 59 (सिविल अपील के पैराग्राफ 1 के अनुसार) केवल पैराग्राफ 414 (एफ) में पाए गए विवादित फैसले के उस हिस्से को चुनौती देता है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रारंभिक निर्णय घोषित किया था।

धोखाधड़ी से दूषित होने का आदेश।

ओ. एस. ए. सं. 54 में निर्णय को चुनौती देने वाली एक अलग अपील 2004. जैसा कि सिविल अपील के पैराग्राफ 1 से देखा गया है, यह अपीलार्थी पैराग्राफ 414 (एफ) में पाए गए विवादित फैसले के केवल उसी हिस्से को चुनौती देता है।

184. इन अपीलों में अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के पक्षकार नहीं थे। उनका दावा है कि प्रतिवादी

No.52 सूट में एक नवाब गौसुद्दीन @मोहम्मद था। गौस मोहिउद्दीन खान। उनकी पत्नी साहेबज़ादी हमीदुन्निसा बेगम [2023] 8 एस. सी. आर. थीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी No.58। गौसुद्दीन खान पहले प्रतिवादी का बेटा था। यह अपीलार्थियों का मामला है कि गौसुद्दीन खान (प्रतिवादी No.52) को 1971 के आवेदन No.139 और 1973 के आवेदन संख्या 185 में उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में एकड़ 62.02 गुंटा की सीमा की भूमि आवंटित की गई थी। अपीलार्थियों के अनुसार, सरकार ने नाजिम अतियत अदालत की दिनांकित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया

30.10.1968 और 1983 का मुंतखाब सं. 4 दिनांक 14.02.1983 जारी किया। यह घोषणा करते हुए कि गौसुद्दीन खान और उनके दो भाई हैदरनगर गाँव में दो तिहाई हिस्से के हकदार थे। इसके बाद, गौसुद्दीन खान (प्रतिवादी No.52) ने महबूब बेग के पक्ष में एकड़ 60.00 गुंटा की भूमि उपहार में दी, जैसा कि दिनांकित पुष्टिकरण दस्तावेज से देखा जा सकता है।

19.12.1978. समीना कौसर और अन्य (चार अपीलों में अपीलार्थी) महबूब बेग की पोतियाँ हैं। वे, मिर्जा महबूब बेग के अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ, हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में 60 एकड़ की भूमि विरासत में मिलने का दावा करते हैं। इसके बाद, उन्होंने कुल एकड़ 60.00 में से 30 एकड़ को मेसर्स को बेच दिया। जयाहो एस्टेट्स। 185. संक्षेप में कहें तो समीना कौसर और चार अन्य, जो चार अपीलों में अपीलकर्ता हैं, गौसुद्दीन खान (प्रतिवादी No.52) द्वारा दिए गए उपहार के आधार पर हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में एकड़ 60.00 की भूमि पर अधिकार का दावा करते हैं। साहेबज़ादी हमीदुन्निसा बेगम, जो एक अपील में अपीलार्थी हैं, मुकदमे में प्रतिवादी No.58 थीं। ये सभी अपीलार्थी विवादित निर्णय में निहित इस घोषणा से व्यथित हैं कि प्रारंभिक डिक्री धोखाधड़ी से दूषित है और

अतः शून्य और शून्य।

186. दिलचस्प बात यह है कि इन व्यक्तियों द्वारा दायर दीवानी अपीलों के पैराग्राफ नंबर 1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपील केवल एक

विवादित निर्णय के पैरा सं. 414 (च) को चुनौती देना। लेकिन बहस के दौरान, श्री वी. वी. एस. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए अपीलार्थियों ने अनुच्छेद संख्या पर भी हमला किया। 414 (ग) और (घ) विवादित निर्णय का। पैराग्राफ 414 (सी) में, उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे थे कि भूमि

हैदरनगर गाँव में खुर्शीद जाह की मथरुका संपत्ति थी। पैराग्राफ No.414 (डी) में, उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि हैदरनगर गाँव की भूमि जागीर भूमि थी, लेकिन 1948 से पहले रैयतों की खेती के लिए पट्टा दिए गए थे और इसलिए भूमि का अधिकार 1948 से पहले ही खेती करने वाले रैयतों को दे दिया गया था।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

उत्परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए राजस्व प्राधिकरण, जिस तरह से कब्जा लेने का दावा किया गया था, अंतिम डिक्री के पारित होने से पहले भी निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से या अन्यथा, यह दर्शाता है कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और दुरुपयोग किया गया था। आज स्थिति यह है कि हैदराबाद शहर और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में किसी भी संपत्ति का पता शिकायत अनुसूची IV में शामिल किसी भी संपत्ति से लगाया जा सकता है। शिकायत अनुसूची IV में सर्वेक्षण के बिना गाँव और गाँव शामिल थे। संख्याएँ और सीमाएँ। आज भी, बाद अनुसूची में वर्णित संपत्तियों के कुछ हिस्सों के संबंध में बहुत सारे अंतिम डिक्री आवेदन लंबित हैं। समझौते की कोई भी संख्या, अंतिम फरमानों की कोई भी संख्या और कोई भी

1958 के सी. एस. सं. 14 में कई लोगों को फांसी दी गई है। जैसा कि श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने सही तर्क दिया है, वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए राज्य के लिए जो एक दीवानी मुकदमे (सी. एस.) के रूप में शुरू हुआ वह वास्तव में एक दीवानी घोटाला साबित हुआ। हवा में महलों का निर्माण करने के बजाय, दल वास्तव में 1958 के सी. एस. संख्या 14 से महलों का निर्माण कर रहे थे।

188. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. वी. एस. राव का तर्क है कि प्रारंभिक आदेश पहले ही अंतिम रूप ले चुका है। ए. पी. द्वारा प्रारंभिक डिक्री से शिकायत अनुसूची IV की वस्तु Nos.35 को 38 और 40 में हटाने के लिए आवेदन दायर करना। उक्त आवेदन को 18.12.1982 पर खारिज कर दिया गया था। 1985 के ओएसए नंबर 1 में उसी से उत्पन्न अपील को 24.12.1999 पर खारिज कर दिया गया था। हालाँकि राज्य ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, लेकिन उसे 05.05.2000 पर वापस ले लिया गया, लेकिन उच्च न्यायालय में वापस जाने की स्वतंत्रता के साथ। इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता के आधार पर, राज्य ने प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ 2000 के ओएसए एसआर No.3526 में फिर से अपील दायर की। लेकिन इसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 07.02.2001 पर खारिज कर दिया था। विशेष अवकाश

एस. एल. पी. (सी) सं. में उसी से उत्पन्न याचिका। 10622-23 2001 को इस न्यायालय द्वारा 16.07.2001 पर खारिज कर दिया गया था। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. वी. एस. राव द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि एक प्रारंभिक डिक्री जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली थी, उसे बाद में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जैसा कि इस [2023] 8 एस. सी. आर. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेंकट रेड्डी बनाम पेथी रेड्डी 18 में न्यायालय। विद्वान वरिष्ठ वकील ने नारायण सरमा (उपरोक्त) में की गई टिप्पणी की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि प्रारंभिक डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई है, यह अंतिम हो गई है।

189. लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया है, निर्णय और प्रारंभिक डिक्री दिनांक 28.06.1963 और उसके बाद जो कुछ भी हुआ इसके लिए, (i) विभाजन वाद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और (ii) विभाजन के लिए वाद में जांच की गुंजाइश के अनुसार नहीं थे।

190. 1958 के सी. एस. No.14 में कार्यवाही के आगे बढ़ने के तरीके पर सावधानीपूर्वक नज़र डालने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय ने

अपने लिए अलग संहिता, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

191. यह याद रखना चाहिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XX नियम 18 में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपनाया जाना चाहिए।

विभाजन के लिए एक मुकदमे में एक डिक्री पारित करते समय न्यायालय। आदेश XX के नियम 18 के दो उप नियम हैं। प्रथम उप-नियम के अनुसार, विभाजन के लिए डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कलेक्टर या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा किए जाने वाले विभाजन या पृथक्करण का निर्देश दे सकता है, यदि डिक्री राजस्व के भुगतान के लिए मूल्यांकन की गई संपत्ति से संबंधित है।

सरकार। यह पहले संपत्ति में रुचि रखने वाले कई पक्षों के अधिकारों की घोषणा करने के बाद किया जाएगा। दूसरे उप-नियम के तहत, न्यायालय, यदि वह सोचता है कि विभाजन और अलगाव को आगे की जांच के बिना आसानी से नहीं किया जा सकता है, तो कई पक्षों के अधिकारों की घोषणा करते हुए एक प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है और ऐसे आगे के निर्देश दे सकता है जो हो सकता है

आवश्यक है, यदि डिक्री किसी अन्य अचल संपत्ति से संबंधित है जो उप-नियम (1) के अंतर्गत नहीं आती है।

193. ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में संहिता के आदेश XXVI नियम 13 में प्रावधान किया गया है। आदेश 26 नियम 13 में कहा गया है कि विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री पारित की गई है, किसी भी मामले में जो धारा 54 [और आदेश XX नियम 18 (1)] द्वारा कवर नहीं किया गया है, न्यायालय को ऐसे व्यक्ति को आयोग जारी करना चाहिए जो वह उचित समझे, इस तरह के डिक्री में घोषित अधिकारों के अनुसार विभाजन और अलगाव करने के लिए। द.

18 एयर 1963 एससी 992 एम/एस ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

इस प्रकार नियुक्त आयुक्त को जांच करनी चाहिए, संपत्ति को विभाजित करना चाहिए।

आदेश XXVI के तहत, जहां भी आवश्यक और अधिकृत हो, शेयरों के मूल्य को बराबर करने के उद्देश्य से भुगतान की जाने वाली ऐसी राशि प्रदान करते हुए, जितना हो सके उतने शेयरों में और पक्षों को ऐसे शेयरों का आवंटन करें।

नियम 14 (1)। इसके बाद आयुक्त को आदेश XXVI के नियम 14 के उप-नियम (2) के तहत अदालत में एक रिपोर्ट दायर करनी चाहिए। न्यायालय एक दे सकता है

पक्षकारों को रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करने और उसके बाद आयुक्त की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की पुष्टि करने, उनमें बदलाव करने या उन्हें दरकिनार करने का अवसर। न्यायालय द्वारा ऐसा किए जाने के बाद, न्यायालय द्वारा संहिता के आदेश XXVI नियम 14 (3) के तहत एक डिक्री पारित की जानी चाहिए।

194. इसलिए, विभाजन और अलग कब्जे के मामले में नहीं

संहिता की धारा 54 द्वारा कवर किया गया, एक प्रारंभिक डिक्री पहले है

पास हो गया।

संहिता के आदेश XX नियम 18 (2) के संदर्भ में, एक आयुक्त को आदेश XXVI नियम 13 के तहत बाद की कार्यवाही में नियुक्त किया जाता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आदेश XXVI के तहत एक अंतिम डिक्री पारित की जाती है।

संहिता का नियम 14 (3)। इसके बाद, ऐसी संपत्ति का कब्जा, यदि यह एक अचल संपत्ति है, तो संहिता के आदेश XXI नियम 35 के संदर्भ में इस तरह के अंतिम डिक्री को निष्पादित करके लिया जाता है।

195. इसलिए, विशिष्ट अचल संपत्तियों का प्रश्न या

किसी भी व्यक्ति को आवंटित की जाने वाली अचल संपत्तियों के विशेष रूप से पहचाने गए हिस्से जो केवल एक प्रारंभिक डिक्री रखते हैं

अविभाजित हिस्सा उत्पन्न नहीं होता है। विभाजन के लिए एक मुकदमे में एक प्रारंभिक डिक्री केवल उन शेयरों की घोषणा करती है जो पक्षकारों को वाद अनुसूची में शामिल किसी भी संपत्ति में हकदार हैं और विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं। प्रारंभिक डिक्री के तहत होने वाले अधिकारों की मात्र घोषणा के आधार पर, पक्ष संपत्तियों की विशिष्ट वस्तुओं या सूट अनुसूची संपत्तियों के विशिष्ट हिस्सों पर व्यापार नहीं कर सकते हैं। चूंकि विभाजन मुकदमे में तीन चरण होते हैं, अर्थात् (i) आदेश XX नियम 18 (2) के संदर्भ में प्रारंभिक डिक्री पारित करना; (ii) एक आयुक्त की नियुक्ति और आदेश XXVI नियम 14 (3) के संदर्भ में अंतिम डिक्री पारित करना; और (iii) आदेश XXI नियम 35 के तहत ऐसी डिक्री के निष्पादन में कब्जा करना, विभाजन के मुकदमे का कोई भी पक्ष, समझौते के माध्यम से भी, संपत्ति की किसी विशिष्ट वस्तु या किसी विशिष्ट संपत्ति के किसी विशेष हिस्से पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है, यदि ऐसा है -

समझौता केवल मुकदमे के कुछ पक्षों के साथ किया जाता है।

196. वास्तव में समीना कौसर और अन्य लोग इस भूमि पर अपना दावा करते हैं

हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में एकड़ 60.00 की सीमा, प्रतिवादी No.52 द्वारा दिए गए उपहार के आधार पर। यहाँ तक कि मान लीजिए, समीना [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कौसर और अन्य लोगों ने उस भूमि का आधा हिस्सा 1997 में मेसर्स जयाहो एस्टेट्स को बेच दिया था। फिर भी समीना कौसर और अन्य लोगों ने अपील की है।

197. जो भी हो, मौखिक उपहार के ज्ञापन पर एक नज़र

घोसुद्दीन खान (प्रतिवादी No.52) द्वारा निष्पादित दिनांक 19.12.1978 से पता चलता है कि उक्त दस्तावेज़ पहले से ही 10.10.1978 पर किए गए मौखिक उपहार (हिबा) का रिकॉर्ड होने का तात्पर्य है। मौखिक उपहार के इस ज्ञापन में घोषणा की गई है कि दाता ने उपहार में दी गई संपत्ति का कब्जा भी दानकर्ता को सौंप दिया है। दिलचस्प बात यह है कि मौखिक उपहार के इस ज्ञापन में संपत्ति की कोई अनुसूची नहीं है, लेकिन इसमें बहुत अजीब बात है, अकेले सीमाएँ। इस मौखिक उपहार ज्ञापन दिनांक 19.12.1978 के अंतिम भाग को निकालना उपयोगी होगा। वह इस प्रकार है:

" आज 19 दिसंबर 1978 को मैंने मौखिक रूप से पुष्टि की है।

10 अक्टूबर 1978 को डोनी के पक्ष में उपहार दिया गया और निष्पादित किया गया

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में यह उपहार ज्ञापन।

इसलिए ये कुछ शब्द मेरे द्वारा लिखे गए हैं

उपहार का स्मारक ताकि यह एक प्राधिकरण के रूप में बना रहे

आवश्यकता के समय उपयोग किया जाता है।

सीमाएँ:

उत्तर दिशा: निजामपेट गाँव

दक्षिण: बॉम्बे हाई वे

पूरब: हैदरनगर गाँव,

पश्चिम: जिलानी बेगम का सर्वेक्षण सं. 28 लैंड।

सरदार/- डोनर हाउस मोहिउद्दीन खान।

एसडी/- गवाह "

एसडी/- गवाह

198. यह सच है कि ज्ञापन के मुख्य भाग में, दाता

हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में 60 एकड़ जमीन के कब्जे में मालिक होने का दावा करता है। लेकिन हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 के पास कुल एकड़ 196.20 भूमि है। कुल सीमा में से 60 एकड़ के लिए प्रतिवादी का दावा, 1971 के आवेदन संख्या 139 में कथित रूप से पहले पारित एक आदेश के आधार पर

है। लेकिन इस आवेदन में पारित एकमात्र आदेश इस आशय का है कि पक्ष शेयरों के आवंटन पर सहमत नहीं हो पाए हैं और इसलिए, मैसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रैक्चर लिमिटेड।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

सी. पी. सी. की धारा 54 के तहत मामले को कलेक्टर को भेजा जाना था। लेकिन अचानक, पी. नरसिम्हा राव रिसीवर/कमिश्नर द्वारा दायर एक अंतिम रिपोर्ट, कथित रूप से 1973 के ApplicationNo.185 में एक समझौते के आदेश के आधार पर सामने आती है। उक्त अंतिम रिपोर्ट में निहित तालिका में सर्वेक्षण No.172 को सर्वेक्षण संख्या वाले 25 अलग-अलग भागों में उप-विभाजित किया गया है। 172/1 172/25 तक। प्रतिवादी No.52 को आवंटित किए जाने के लिए इसमें जो दिखाया गया है वह निम्नलिखित था:

सर्वेक्षण सं।

डी-52 को आवंटित किया गया

से बाहर

172/8

0.2 जी.

9 39 एकड़

गुंटा

10 एकड़ 02

गुंटा

10.02 जी.

172/9

172/17

7 एकड़ 08

गुंटा

7.08 जी.

172/18

10.00 जी.

10 एकड़ 00

गुंटा

172/19

10 एकड़ 07

गुंटा

10.07 जी.

9.34 जी.

172/20

9 34 एकड़

गुंटा

5 एकड़ 04 गुंटा

172/21

5.04 जी.

5.38 जी.

172/22

5 38 एकड़

गुंटा

172/23

5.00 जी.

5 25 एकड़

के गुंटा

62.13 जी.

199. दिलचस्प बात यह है कि 1971 के आवेदन संख्या 139 में पारित आदेश

दिनांकित 21.01.1976 है। यदि उक्त आदेश के अनुसार, सर्वेक्षण No.172 को उप-विभाजित किया गया था और सर्वेक्षण No.172 के विभिन्न उप-प्रभागों में भूमि के विभिन्न टुकड़े प्रतिवादी No.52 को आवंटित किए गए थे, तो दिनांकित 19.12.1978 के उपहार ज्ञापन में सर्वेक्षण संख्या के इन सभी उप-विभाजन और एक उचित विवरण होना चाहिए था। सर्वेक्षण No.172 के उप-विभाजन संख्या दिए बिना और कथित रूप से अधिवक्ता आयुक्त द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार भूमि के विभिन्न भागों का वर्णन किए बिना, उपहार ज्ञापन में केवल सीमाओं का उल्लेख किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तरी सीमा निजामपेट गाँव, दक्षिणी सीमा बॉम्बे राजमार्ग और पश्चिमी सीमा है।

सर्वेक्षण No.28 को जिलानी बेगम से संबंधित बताया गया। इसलिए, प्रतिवादी No.52 के तहत दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया पूरा दावा एक धोखा प्रतीत होता है।

200. वास्तव में, श्री वी. वी. एस. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रयास किया

नज़ीम अतियत अदालत की रिपोर्ट और सर्वेक्षण, बस्तियों और भूमि अभिलेख आयुक्त द्वारा जारी मुंतखाब में अपीलार्थियों के नाम का पता लगाएं। लेकिन जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सूट खिताब के लिए नहीं था।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

201. दिलचस्प बात यह है कि इन अपीलों में श्री वी. वी. एस. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील, द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपीलकर्ता भी उनके द्वारा किए गए दावे पर हमला करते हैं।

17.03.1967 पर तारापोरवाला। इसलिए, अपीलार्थियों के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 201 के तहत अपनी एजेंसी की समाप्ति के बाद एजेंट द्वारा की गई बिक्री पूरी तरह से अमान्य है।

202. यदि अपीलकर्ता जो कहते हैं वह सच है, तो कोई भी विपणन योग्य शीर्षक निजाम से साइरस से गोल्डस्टोन तक नहीं जा सकता था। इसलिए ऐसा नहीं है।

केवल वे जो प्रतिवादी No.52 के तहत दावा करते हैं, लेकिन साइरस/गोल्डस्टोन/ट्रिनिटी को भी एक साथ डूबना चाहिए।

203. कुछ अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वी. वी. एस. राव के साथ उपस्थित होते हुए, श्री के. एस. मूर्ति ने यह तर्क दिया कि हैदरनगर गाँव को अनुदान गाँव घोषित किया गया था और यह अल्लमाघा द्वारा कवर किया गया था जो एक शाही फरमान है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इनाम जांच और राजस्व बोर्ड और मुंतखाब के आदेश की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया।

204. लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जो हाथ में था वह विभाजन का मुकदमा था और सभी पक्षों ने न केवल भ्रम पैदा किया है, बल्कि भ्रम भी पैदा किया है परेशान पानी में मछली पकड़ना शुरू कर दिया।

205. श्री वी. वी. एस. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील भी पेश होते हैं।

अपीलार्थियों का एक अन्य समूह, अर्थात् फरीदुद्दीन खान और दो अन्य, जिन्होंने विवादित फैसले को चुनौती दी है। ये अपीलार्थी हैदरनगर गाँव के सर्वेक्षण No.145/2 में एकड़ 30.00, सर्वेक्षण No.145/1 में एकड़ 62.00 और सर्वेक्षण No.163/3 में एकड़ 30.00 की भूमि के स्वामित्व का दावा करते हैं। 2022 के एसएलपी (सी) Nos.8888-8891 से उत्पन्न होने वाली इन चार अपीलों में तीन अपीलार्थी हैं। लेकिन अपीलार्थी सं. 2 ने सर्वेक्षण सं. <आई. डी. 1 में कुल 62 एकड़ में से 42 एकड़ की भूमि को-ऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी को बेच दी है। अपीलकर्ता संख्या 3 का दावा है कि उसने एकड़ का पूरा हिस्सा 30.00 में बेच दिया है।

हैदरनगर गाँव का सर्वेक्षण No.163/3 तीसरे पक्ष को।

मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्ठी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

206. हम नहीं जानते कि व्यक्ति विभाजन मुकदमे में भूमि के अविभाजित शेयरों में से कथित रूप से उन्हें आवंटित भूमि के चिन्हित अंशों को कैसे बेच सकते हैं, जिसमें अंतिम आदेश और प्राप्तकर्ता की रिपोर्ट प्रचुर मात्रा में होती है।

207. श्री वी. वी. एस. राव का तर्क, इन अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील, जो प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं।

208. इस तर्क के जवाब में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि पक्ष अदालत को धोखा दे सकते हैं और अदालत को एक मोड़ पर ले जा सकते हैं मैसूर (दो वाद अनुसूची संपत्तियाँ मैसूर में स्थित थीं) और सभी प्रकार के विवादों के लिए एक मुकदमे में विभाजन के लिए एक साधारण मुकदमा बनाते हैं, अकेले न्यायालय सीमाओं पर नहीं टिक सकता है।

209. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2022 की एसएलपी (सी) Nos.8884-8887,2022 की एसएलपी (सी) Nos.8888-8891 से उत्पन्न होने वाली सभी अपीलों और

2022 की एसएलपी (सी) No.24098 को खारिज किया जा सकता है। तदनुसार, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है।

भाग-VII:

2022 की आई. ए. संख्या 118143,2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 8884 में

210. यह आवेदन मोहम्मद द्वारा दायर किया गया है। मुस्तफुद्दीन खान और एक अन्य ने एसएलपी (सी) से उत्पन्न अपील में हस्तक्षेप की मांग की

समीना कौसर और अन्य लोगों द्वारा 2022 का No.8884 दाखिल किया गया।

211. इसमें आवेदक मोहम्मद के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। गौसुद्दीन खान, जो मुकदमे में प्रतिवादी No.52 था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि

प्रतिवादी No.52 को हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में 62 एकड़ की भूमि आवंटित की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि वे उसी बिक्री विलेख पर हमला करते हैं जिसकी तारीख 30.08.1964 है जिसके तहत एच. ई. एच. निजाम ने कथित रूप से उक्त संपत्ति पर अवैध अधिकार खरीदे थे। आवेदकों के अनुसार, प्रतिवादी No.52 ने कभी भी एच. ई. एच. निजाम और खासिम नवाज जंग के पक्ष में अपना हिस्सा नहीं बेचा। उनका यह भी तर्क है कि बिक्री किसी भी विचार द्वारा समर्थित नहीं थी और किसी भी मामले में आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) कृषि भूमि अधिनियम, 1950 की धारा 47 और 48 के तहत अनुमति के अभाव में बिक्री अमान्य है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

212. इन आवेदकों द्वारा सामने लाया गया एक और दिलचस्प पहलू यह है कि एच. ई. एच. निजाम की मृत्यु आवेदन के लंबित रहने के दौरान भी हो गई थी।

1966 के आवेदन No.109 में अभियोग के लिए और इसलिए कि अभियोग के अनुसार जो कुछ भी हुआ वह शून्य था।

213. दुर्भाग्य से, जिस तारीख को एच. ई. एच. निजाम को प्रतिवादी No.156 के रूप में शामिल किया गया था, वह हमारे सामने रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। लेकिन यह रिकॉर्ड में है कि उनकी मृत्यु 24.02.1967 पर हुई थी। उनकी मृत्यु से पहले, उनके शक्ति एजेंट, तारापोरवाला ने उनके पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था।

दिनशाँ कंपनी (बाद में साइरस)। हालाँकि, बिक्री विलेख निजाम की मृत्यु के बाद पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, हम इस तर्क की शुद्धता को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं हैं कि प्रतिवादी No.156 (निजाम) की मृत्यु हो गई थी, इससे पहले कि उसे एक व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया था। सूट के लिए पार्टी। यदि आवेदक जो कहते हैं वह सच है, तो वे इस तर्क में सही हो सकते हैं कि मृत व्यक्ति के नाम पर जो कुछ भी किया गया था वह अमान्य है।

214. लेकिन एच. ई. एच. निजाम को प्रतिवादी No.156 के रूप में आरोपित करने के आदेश की तारीख के बारे में विवरण के अभाव में, हम इस पहलू पर अपना अंतिम शब्द नहीं बोल रहे हैं। वर्तमान में यह ध्यान देने योग्य है कि समीना कौसर और अन्य लोगों द्वारा दायर अपीलों को खारिज किए जाने के मद्देनजर, यह हस्तक्षेप आवेदन उनके तर्क के गुण-दोष में पड़े बिना खारिज किया जा सकता है।

भाग-VIII

विशेष अवकाश याचिका (सी) में 2022 का आई. ए. No.112090

2020 का Nos.2373-2377

215. यह आवेदन एक परिसंपत्ति द्वारा लिया गया है

पुनर्निर्माण कंपनी, मेसर्स रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (पूर्व में रेथियॉन एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड) के नाम से। लिमिटेड)। वे इस आधार पर विशेष अनुमति याचिकाओं में पक्षकारों के रूप में खुद को शामिल करना चाहते हैं कि मैसर्स एमबीएस ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। लिमिटेड ने लाभ उठाया पंजाब नेशनल बैंक, आंध्र बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) और इंडियन ओवरसीज बैंक से कुछ ऋण सुविधाएँ और ऋणों के उचित पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, तीसरे पक्ष ने हैदरनगर गाँव में एकड़ 196.20 गुंटा मापने के लिए सर्वेक्षण No.172 में भूखंड No.10 से संबंधित स्वामित्व विलेखों को जमा करके एक न्यायसंगत बंधक बनाया। इस तरह के न्यायसंगत बंधक बनाने वाले तीसरे पक्ष मेसर्स इंडिया टेलीकॉम फाइनेंस कॉर्पोरेशन थे।

लिमिटेड, मेसर्स साई अनुपमा एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड।

लिमिटेड, मेसर्स कीर्ति अनुराग मेसर्स ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

निवेश प्रा. लिमिटेड, मेसर्स जयश्री एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, मेसर्स साई कीर्ति कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, मेसर्स साई पवन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और मेसर्स ग्रेटर गोलकोंडा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड। लि. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के अनुसार

कंपनी, स्वामित्व विलेखों की जमा राशि 25.03.2009 पर हुई। बैंकों के संघ को देय कुल राशि लगभग Rs.550 करोड़ थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों ने डी. आर. टी., हैदराबाद के समक्ष आवेदन दायर किए और ये आवेदन लंबित हैं। इसलिए, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण

कंपनी का दावा है कि यदि बंधककर्ताओं को इस अदालत के आदेश का सामना करना पड़ता है, तो यह बैंकों से संबंधित सार्वजनिक धन है जो अंततः प्रभावित होगा।

216. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि निजी पक्षों के बीच विवाद, यह सार्वजनिक धन है जो दांव पर है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के समर्थन में कई प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

उनका यह तर्क कि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी वर्जित है और इन दोनों अधिनियमों के प्रावधान अन्य सभी अधिनियमों पर हावी होंगे

अधिनियम।

217. लेकिन परिसंपत्ति के लिए दो बड़ी बाधाएं हैं

पुनर्निर्माण कंपनी जो इस आई. ए. में आवेदक है, पहला यह है कि इस परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने वास्तव में 2004 के आई. डी. 1 में 2019 का आई. डी. 2 दाखिल किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष 2004 के OSANo.56 में 2019 का <ID4 और 2004 के OSANo.59 में 2019 का <ID3। अभियोग के लिए इन सभी आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था

इन अपीलों में आरोपित आदेश। अन्य व्यक्ति जिन्होंने इसी तरह के भ्रामक आवेदन दायर किए थे जिन्हें उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया था, वे पूरे विवादित फैसले के खिलाफ स्वतंत्र अपील लेकर आए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अभियोग आवेदनों को खारिज करने का आदेश पूरे विवादित फैसले के संचालन भाग का हिस्सा है। इसलिए, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को उच्च न्यायालय द्वारा उनके अभियोग आवेदनों को खारिज करने के खिलाफ स्वतंत्र अपील दायर करनी चाहिए थी। वे अब दूसरों द्वारा दायर अपीलों पर पिग्मी-बैक राइड नहीं कर सकते हैं।

218. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की दूसरी कठिनाई यह है कि छह अलग-अलग कंपनियों ने एक न्यायसंगत बंधक बनाया

स्वामित्व विलेखों का जमा। 2022 के I.A.No.110290 के पैरा 2 में निहित अनुमान के अनुसार, स्वामित्व विलेखों की जमा राशि 25.03.2009 पर हुई।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे जमा किया गया कहा जाता है वह 1958 के सीएस No.14 में 1998 के आवेदन No.517 में अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रतियां हैं। 24.04.1998 .

219. हम नहीं जानते कि विभाजन मुकदमे में अंतिम आदेश कैसे दिया जाता है और वह भी सी. एस. एन. ओ. जैसे कुख्यात मुकदमे में। 14 1958 को स्वामित्व का एक दस्तावेज माना जा सकता था जिसे न्यायसंगत बंधक के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। किसी भी मामले में, स्वामित्व विलेखों की जमा राशि को लिया गया कहा जाता है 25.03.2009 पर रखें। इस समय तक, विद्वान एकल न्यायाधीश (एल. नरसिम्हा रेड्डी, जे.) का दिनांक 26.10.2004 का आदेश अस्तित्व में आ गया था जिसमें बाधा डालने वालों के दावों की अनुमति दी गई थी। यद्यपि एकल न्यायाधीश दिनांक 1 के उक्त आदेश को डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 2 के आदेश द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, डिवीजन बेंच का उक्त आदेश उस समय भी दीवानी अपीलों का विषय बन गया था। इन दीवानी अपीलों को अंततः इस न्यायालय द्वारा 05.03.2014 दिनांकित एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। हम नहीं जानते कि इस अंतराल अवधि के दौरान, बैंक इस संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते थे, इसके बावजूद

यह एक गंभीर लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी का विषय है।

220. किसी भी मामले में, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा लगाए गए अभियोगों को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है इन अपीलों में आक्षेपित आदेश द्वारा। उसी को चुनौती दिए बिना, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी तीसरे पक्ष और बंधककर्ताओं द्वारा दायर अपीलों में खुद को शामिल करने की कोशिश नहीं कर सकती है। इसलिए, 2022 का आई. ए. 110290 खारिज कर दिया जाता है।

भाग-IX:

2023 का आई. ए. Nos.36417,36419 और 36422 विशेष में 2020 की छुट्टी याचिका (सी) Nos.2373-2377

221. इन आवेदनों के लिए क्रमशः प्रार्थना की गई है, (i) शामिल होने के लिए अनुमति; (ii) अभियोग; और (iii) निर्देश, मेसर्स दुर्गा माता हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के नाम से सहकारी आवास सोसायटी। यह सोसायटी 2020 के एस. एल. पी. (सी) Nos.2373-2377 से उत्पन्न अपीलों में शामिल होने की मांग कर रही है और उचित निर्देशों के लिए भी प्रार्थना कर रही है।

222. इन अंतर्वर्ती आवेदनों में निहित कथन,

संक्षेप में,

(i) कि 23.02.1967 दिनांकित बिक्री विलेख के आधार पर, एच. ई. एच. निजाम ने एन. आई. टी. आई. इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड की सीमा तक की भूमि में अपना अविभाजित आधा हिस्सा बेच दिया।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. एच. वाई. एंड ओ. आर. एस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

साइरस और नवाब कासिम नवाज जंग को हैदरनगर के सर्वेक्षण No.163 में एकड़ 175.06;

कि विक्रेताओं और खरीदारों को इस रूप में फंसाया गया था

प्रतिवादी सं। 156 , 157 और 1958 के सीएस No.14 में क्रमशः 206;

कि नवाब खासिम नवाज जंग (प्रतिवादी No.157) की मृत्यु हो गई और वह जीवित रह गए, उनकी पत्नी और बेटी (प्रतिवादी Nos.334 और 335);

कि ज्ञापन के अनुसार, हैदरनगर के सर्वेक्षण No.163 में भूमि प्रतिवादी संख्या को आवंटित की गई थी। 157 और 1982 के आवेदन No.31 में उच्च न्यायालय के दिनांक 08.07.1983 के आदेशों के अनुसार आधे शेयरों में 206; कि उन प्रतिवादियों ने इसके बाद तीसरे पक्ष के पक्ष में असाइनमेंट और बिक्री विलेखों के कई विलेखों को निष्पादित किया। आवेदक सहित-समाज;

कि आवेदक-सोसायटी को दिनांकित असाइनमेंट डीड द्वारा एकड़ 50.00 की सीमा की भूमि का असाइनमेंट मिला

18.04.1987 वर्ष 1989 के एक अन्य असाइनमेंट डीड के तहत नवाब खासिम नवाज जंग और एकड़ की एक और सीमा 16.00 से;

कि आवेदक-सोसायटी इस प्रकार मालिक बन गई और उसने हैदरनगर के सर्वेक्षण No.163 में 66 एकड़ की भूमि का कब्जा भी ले लिया; कि जब भूमि के किसी हिस्से पर कब्जा करने का दावा करने वाले कुछ व्यक्तियों ने आवेदक-सोसायटी के कब्जे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो सोसायटी ने केवल निषेधाज्ञा के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया;

कि उक्त मुकदमे की सुनवाई एक अन्य सहकारी समिति द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे के साथ की गई थी, जिसे इसी तरह आई. डी. पी. एल. कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के नाम से रखा गया था।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xi) कि 16.11.2005 दिनांकित एक सामान्य निर्णय द्वारा, दोनों मुकदमे

विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था;

(xii) कि उसी से उत्पन्न होने वाली पहली अपीलें अब हैं

लंबित हैं;

(xiii) कि उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के बाद, उन पहली अपीलों में उत्तरदाताओं में से एक ने आवेदक सोसायटी की अपील को अस्वीकार करने के लिए इस आधार पर एक आवेदन लिया है कि संपूर्ण प्रारंभिक डिक्री को विवादित निर्णय द्वारा दूषित किया गया है

धोखाधड़ी;

(xiv) कि दिनांक 20.12.2019 के विवादित फैसले के बारे में पता चलने पर, आवेदक-सोसायटी ने उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की;

(xv) कि इस बीच, आवेदक-सोसायटी को भी पता चला कि इस न्यायालय को उत्पन्न होने वाली अपीलों को जव्त कर लिया गया है।

उसी विवादित निर्णय से; और

(xvi) कि इसलिए, आवेदक-समाज मजबूर है

निदेशों के लिए अभियोग और आवेदन, ताकि उनके हैदरनगर के सर्वेक्षण सं. 163 में भूमि से संबंधित अधिकार

प्रभावित नहीं होते हैं।

223. श्री हेमेंद्रनाथ रेड्डी, वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे।

ई आवेदक ने यहाँ तर्क दिया:

कि उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक आयोजित करने में अतिशयोक्ति की

((i)

धोखाधड़ी द्वारा दूषित होने की डिक्री, जिसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों सहित कई कार्यवाहियों में अंतिमता प्राप्त करने के बाद

राज्य सरकार;

कि राजस्व द्वारा किए गए विभाजन के आधार पर

((ख)

संभागीय अधिकारी, धारा 54 सी. पी. सी. के संदर्भ में और प्राप्तकर्ता-सह-आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर, भूमि की पहचान की गई, उप-विभाजन किया गया और कब्जा सौंप दिया गया।

(iii) वह उत्परिवर्तन बहुत पहले 1989 में किया गया था, लेकिन जब इसे रद्द कर दिया गया था, तो आवेदक ने रिट याचिका दायर की और प्राप्त किया

उत्परिवर्तन बहाल; एम/एस ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड। & ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. मर्थी एंड ओआरएस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

(iv)

कि भूमि हड़पने की कार्यवाही भी इसके पक्ष में समाप्त हो गई

आवेदक;

कि सभी अपीलें कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ

(v)

न्यायालय, विवादित निर्णय में, केवल हैदरनगर के सर्वेक्षण No.172 में भूमि से संबंधित था।

(vi) कि प्रारंभिक डिक्री को धोखाधड़ी से दूषित घोषित करके, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के तहत उन मुद्दों को गंभीर झटका दिया है जो सुलझा लिए गए हैं।

अंतिमता; और

(vii) कि उच्च न्यायालय प्रारंभिक डिक्री को धोखाधड़ी से दूषित घोषित नहीं कर सकता था, जब धोखाधड़ी के संबंध में कोई अभिवचन नहीं थे और इन अपीलों में आक्षेपित आदेश से उच्च न्यायालय ने भूमि के अन्य भागों पर तीसरे पक्ष के अधिकारों पर संदेह पैदा कर दिया है, जब आवेदक जैसे वे तीसरे पक्ष भी इसमें पक्षकार नहीं थे।

विवादित निर्णय।

224. आवेदक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री हेमेंद्रनाथ रेड्डी ने रिट याचिका में पारित उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांक 30.03.2021 के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया।

2018 (बैच) का No.20707, जिसमें डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि विवादित फैसले में धोखाधड़ी से संबंधित निष्कर्ष केवल सर्वेक्षण No.172 में भूमि तक ही सीमित थे।

225. हमने श्री की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

हेमेंद्रनाथ रेड्डी। लेकिन हम निम्नलिखित कारणों से उनकी दलीलों से सहमत नहीं हो सकते हैं:

(i)

विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार भी, निष्कर्ष

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, इस स्थिति को एक अन्य खंड पीठ (उसी पीठासीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में, जिन्होंने विवादित निर्णय लिखा था) ने रिट याचिका में अपने दिनांक 30.03.2021 के फैसले में स्पष्ट किया था। 2018 (बैच) का No.20707। उक्त निर्णय दिनांक 31.03.2021 के पैराग्राफ No.169 में, बाद का प्रभाग

पीठ निम्नलिखित रूप में दर्ज की गई:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

" 169. शहनाज बेगम (10 ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा जो भी टिप्पणियां की गईं, वे विशेष रूप से केवल हैदरनगर गाँव के संबंध में विशेष तथ्यों के संदर्भ में की गई थीं, और उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है और हफीजपेट गाँव की भूमि पर भी लागू नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, हम नहीं जानते कि आवेदक-समाज हमारे सामने क्यों है; किसी भी मामले में, आवेदक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया-हमारे सामने समाज, कानून के लिए अज्ञात है। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया है, आवेदक-सोसायटी तीन के साथ आई है

आवेदन, क्रमशः प्रार्थना करना (i) पाने के लिए छोड़ना

(ii) 2020 के एस. एल. पी. (सी) Nos.2373-2377 से उत्पन्न अपीलों में पक्ष लेने के लिए; और
(iii) उचित स्पष्टीकरण के लिए कि विवादित निर्णय में टिप्पणियां नहीं हैं।

सर्वेक्षण No.163 में भूमि पर लागू। दूसरे शब्दों में, आवेदक-समाज जो चाहता है कि हम करें, वह उच्च न्यायालय के फैसले को स्पष्ट करना है। हम नहीं जानते कि किसके तहत

किसी भी स्थिति में, आवेदक-सोसायटी ने इस आधार पर विवादित निर्णय की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की है कि यह सर्वेक्षण No.163 में उनके अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए, यह आवेदक-समाज के लिए खुला नहीं है कि वह हमारे सामने आए और वह भी निर्देश के लिए आवेदन के रूप में। इसलिए ये तीनों आई. ए. बर्खास्त किए जाने के योग्य हैं। तदनुसार, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है।

क्लोज़न

उपरोक्त चर्चा के आलोक में:

ट्रिनिटी इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड और अन्य द्वारा दायर 2020 के एस. एल. पी. (सी) Nos.2373-2377 से उत्पन्न होने वाली सभी अपीलें एन. आई. टी. आई. इन्फ्रावेन्चर्स लिमिटेड हैं।

& ओआरएस। ईटीसी. वी. एम. एस. एच. वाई. एंड ओ. आर. एस. ईटीसी। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

बर्खास्त कर दिया। नतीजतन, तेलंगाना राज्य द्वारा दायर 2022 की आई. ए. संख्या 75869 को खारिज कर दिया जाता है।

समीना कौसर और अन्य द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) Nos.8884-8887 से उत्पन्न होने वाली सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। नतीजतन, 2022 का आई. ए. सं. 118143 खारिज कर दिया जाता है।

फरीदुद्दीन खान और अन्य द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) Nos.8888-8891 से उत्पन्न होने वाली सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। तेलंगाना राज्य द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) डायरी संख्या 19266 से उत्पन्न होने वाली सभी पांच अपीलें और एक अन्य को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया जाता है कि निष्कर्ष में दिया गया है।

अनुच्छेद 244 और आक्षेपित निर्णय के अनुच्छेद 414 (घ) में अभिलिखित निष्कर्ष राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

साहेबज़ादी हमीदुन्निसा बेगम के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दायर 2022 के एसएलपी (सी) No.24098 से उत्पन्न अपील को खारिज कर दिया जाता है।

2022 के एस. एल. पी. (सी) No.2203 से उत्पन्न अपीलें दायर की गईं।

टी. पंडरी नाथम और अन्य लोगों द्वारा; के. सुधन रेड्डी और अन्य लोगों द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) No.256; जी. अरुणा कुमारी और अन्य लोगों द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) No.1584; जी. राम कृष्ण रेड्डी और अन्य लोगों द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) No.980; के. परधा सारथी द्वारा दायर 2022 की एसएलपी (सी) No.8872 और अन्य जिन्होंने सत्य साई को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड से अलग-अलग भूखंड खरीदे हैं, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।

और पैराग्राफ 414 (जी) और 414 (आई) में "तीसरे पक्ष" शब्दों के उपयोग के कारण भी। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण द्वारा दायर 2020 के एसएलपी (सी) Nos.2373-2377 से उत्पन्न अपीलों में 2022 का आई. ए. No.112090

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आगे बढ़ने के लिए उपलब्ध अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कंपनी को बर्खास्त कर दिया जाता है।

कानून के अनुसार उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं के खिलाफ।

रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय की

(viii) दुर्गा द्वारा 2023 का

आई. ए. Nos.36417,36419 और 36422 दाखिल किया गया

ए.

माथा हाउस

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव हाउसिंग

सोसाइटी लिमिटेड,

2020 के एसएलपी (सी) Nos.2373 2377 से उत्पन्न अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

पक्षकारों को अपने-अपने खर्च

वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस (राहुल राठी,

एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)